वर्षः 5 अंकः7 जुलाई, 2025 मूल्यः 60 रु. पृष्ठ : 44

राजस्थान टुडे

RNI No. RAJHIN/2020/11458

ईरान-इस्रायल युद्ध

परमाणु नीति का पाखण्ड बेनकाब 4

समझ आ गया महाशक्ति का महाखेल 6

उतर गए कई नकाब 10

22 जुलाई : राष्ट्रीय ध्वज दिवस

तिरंगे का गौरवमयी इतिहास

"झंडा ऊंचा रहे हमारा"– यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक है। 22 जुलाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इसी दिन सन् 1947 में संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। इसीलिए हर वर्ष 22 जुलाई को 'राष्ट्रीय ध्वज दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति

- **22 जुलाई 1947** को भारत की संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए तिरंगे झंडे को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया।
- यह स्वीकृति स्वतंत्रता प्राप्ति **(15 अगस्त 1947)** से कुछ ही सप्ताह पूर्व दी गई थी।
- **इस झंडे में तीन रंग** – केसरी, सफेद, और हरा होते हैं, तथा बीच में नीले रंग का अशोक चक्र होता है।

3 रंग और उनका महत्व

1. **केसरी रंगः** साहस, बलिदान और आत्म-नियंत्रण का प्रतीक
2. **सफेद रंगः** शांति, सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक
3. **हरा रंगः** समृद्धि, कृषि और उन्नति का प्रतीक
4. **अशोक चक्र (24 तीलियों वाला):** न्याय, गति और धर्म का प्रतीक

पिंगली वेंकैयाः तिरंगे के जनक

- भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन करने का श्रेय जाता है पिंगली वेंकैया को।
- वे आंध्र प्रदेश के निवासी, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद् और गांधीजी के अनुयायी थे।
- उन्होंने 1916 में राष्ट्र के लिए एक स्वदेशी ध्वज की आवश्यकता अनुभव की और विभिन्न रंगों और प्रतीकों के प्रयोग से कई प्रारूप बनाए।
- प्रारंभ में उनके ध्वज में केवल दो रंग (लाल और हरा) थे, लेकिन गांधीजी के सुझाव पर सफेद व चरखा जोड़ा।
- 1931 में इस झंडे को व्यापक स्वीकृति मिली।
- 1947 में जब अंतिम रूप से झंडा तय हुआ, तो चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया।

तिरंगे का महत्व केवल प्रतीकात्मक नहीं

- राष्ट्रीय ध्वज केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि यह भारत की आत्मा, स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष और देशभक्ति का प्रतीक है।
- यह हमें संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता की याद दिलाता है।

एक विचारधारा का उत्सव का दिन... राष्ट्रीय ध्वज दिवस केवल झंडे के इतिहास को याद करने का दिन नहीं, बल्कि यह उस विचारधारा का उत्सव है जिसके लिए असंख्य लोगों ने बलिदान दिया। 22 जुलाई का दिन हर भारतीय को यह स्मरण कराता है कि हमारा झंडा सम्मान, गर्व और राष्ट्रीय एकता का ध्वजवाहक है।

राजस्थान टुडे

आपकी पत्रिका, आपकी बात
www.rajasthantoday.online

RNI No. RAJHIN/2020/11458
वर्ष 5, अंक 7, जुलाई, 2025
(प्रत्येक माह 15 तारीख को प्रकाशित)

प्रधान सम्पादक
दिनेश रामावत

राजनीतिक सम्पादक
सुरेश व्यास

सम्पादक
अजय अस्थाना

प्रबंध सम्पादक
राकेश गांधी

सह सम्पादक
बलवंत राज मेहता

रेखाचित्र
राजेंद्र यादव

संपादकीय कार्यालय
बी-4, फोर्थ फ्लोर, एम.आर. हाईट्स
महावीर कॉलोनी, भास्कर सर्किल,
रातानाड़ा, जोधपुर - 342011
व्हाट्सएप नंबर - 8107800000
ई-मेल - rajasthantoday@gmail.com

सभी विवादों का निपटारा जोधपुर की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा।

राजस्थान टुडे में प्रकाशित आलेख लेखकों की राय है। इसे राजस्थान टुडे की राय नहीं समझा जाए। राजस्थान टुडे के मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारी भावना किसी वर्ग या व्यक्ति को आहत करना नहीं है। विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व राजस्थान टुडे का नहीं होगा।

• मारवाड़ मीडिया प्लस के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक पूनम अस्थाना द्वारा बी-4, फोर्थ फ्लोर, महावीर कॉलोनी, रातानाड़ा, जोधपुर-342011 से प्रकाशित और डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, 01 पार्श्वनाथ इंडस्ट्रीयल एरिया, रिलायंस वेयर हाउस के पास, मोगरा कलां, जोधपुर-342802 में मुद्रित, संपादक : अजय अस्थाना।

अंदर विशेष

6 आवरण कथा
समझ आ गया महाशक्ति का महाखेल

13 अर्थ जगत
रुपये की वैश्विक उड़ान

नियमित कालम

9 बोल हरि बोल
21 बात बेलगाम
39 अभिव्यक्ति
42 ग्रहों की चाल

33 टेस्ट के ताज का छोटा सरताज

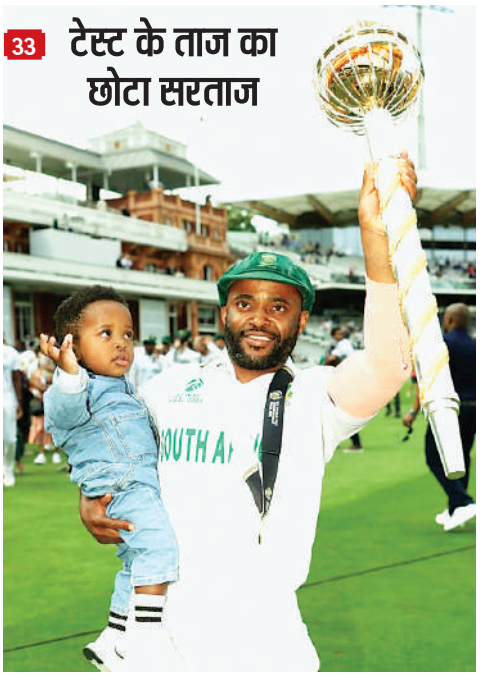

29 संयुक्त परिवार- संस्कारों की पाठशाला
31 जीवन मूल्यों के संवाहक हैं हमारे बुजुर्ग
35 केदारनाथ पैदल यात्रा
37 एसआई भर्ती की रिपोर्ट पेश हो
40 भारत से लेकर रूस तक है दीवानगी मिथुन की

04 अपनी बात...
परमाणु नीति का पाखण्ड बेनक़ाब

10 आवरण कथा...
उतर गए कई नकाब!

15 नदी परियोजना...
नदी नीरे- चमक जाएगी तकदीरें?

17 राजकाज...
फैसला नहीं लेना ही सबसे बड़ा फैसला है!

19 राजनीति...
गहलोत पायलट समीकरण...

22 विमान हादसा...
जब आसमान ने सबकुछ निगल लिया

24 तकनीक...
एआइ को पता है.. आप क्या सोच रहे हो

25 बिहार चुनाव...
बिहार में किसकी बहार

27 परिणिता...
स्वतंत्रता व नैतिकता के बीच संतुलन जरूरी

परमाणु नीति का पाखण्ड बेनक़ाब

दिनेश रामावत
प्रधान सम्पादक

IAEA की निष्क्रियता और इस्राइल के परमाणु हथियारों पर चुप्पी ने उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान ने दोहरे मापदंड के खिलाफ विद्रोह करते हुए चेतावनी दी कि सुरक्षा गारंटी न मिली तो वह NPT से बाहर होगा। अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम एशिया में परमाणु होड़ शुरू हो जाएगी। चीन और रूस की खामोश स्वीकृति ने नए ध्रुवीकरण की आहट दी है। इस्राइल-अमेरिका हमले की धमकियां दे रहे हैं। अगर युद्ध हुआ तो NPT का अंत और वैश्विक परमाणु व्यवस्था की कब्र खुद जाएगी।

पश्चिम एशिया एक बार फिर खौल रहा है। ईरान और इस्राइल के बीच चले हवाई हमलों और मिसाइल हमलों की तपिश अभी थमी भी नहीं थी कि ईरान ने ऐसा दांव चल दिया, जिसने वैश्विक कूटनीति के पाखंड को नंगा कर दिया। ईरान की संसद ने भारी बहुमत से अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ सहयोग निलंबित करने का फैसला कर लिया। और मजे की बात देखिए- न तो संयुक्त राष्ट्र कुछ बोला, न तथाकथित महाशक्तियां।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस करके ऐलान कर दिया था कि 30,000 पाउंड के बम गिराकर उन्होंने ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह कर दिया है और अब ईरान दोबारा सिर नहीं उठा पाएगा। लेकिन अगले ही हफ्ते ईरानी संसद ने जो किया- उसने न सिर्फ ट्रंप के दावे की मिट्टी पलीद कर दी, बल्कि उस IAEA की औकात भी दिखा दी जो अपने आपको परमाणु अप्रसार की सबसे बड़ी निगरानी संस्था बताता है।

यह सच है कि जब ईरान की परमाणु फैसिलिटी पर इस्राइली मिसाइलें बरस रही थीं, तब IAEA का मुखिया राफेल ग्रॉसी बस 'गहरी चिंता' जताने तक सिमट गए। क्या किसी ने उनसे पूछा कि जिस अप्रसार संधि (NPT) के तहत ईरान उनके निरीक्षण का हिस्सा था, उसी NPT की धज्जियां उड़ाते हुए जब इस्राइल ने हमले किए, तो आप मौन क्यों रहे? क्यों उस वक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कोई आपात सत्र नहीं बुलाया गया? क्यों अमेरिका ने इसे 'सावधानीपूर्वक किया गया आत्मरक्षा कदम' कहकर बचाव किया?

दुनिया जानती है कि IAEA जैसी संस्थाएं आज भी अमेरिकी हितों की कठपुतली भर हैं। जिनका एकमात्र काम है- उन्हीं देशों के खिलाफ कार्रवाई करना, जो अमेरिकी नीति के विरोधी हों। वरना क्या कारण है कि इस्राइल, जो खुद 90 से ज्यादा परमाणु हथियार रखता है और NPT का सदस्य तक नहीं है, उसके खिलाफ IAEA कभी कोई कार्रवाई नहीं करता?

ईरान ने इसी दोहरे मापदंड के खिलाफ विद्रोह किया है। और उसका यह कदम उन तमाम देशों के लिए मिसाल है, जो अब तक पश्चिमी दबाव में झुकते आए हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने जिस बेशर्मी से दुनिया के सामने ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह कर देने का दावा किया, वह इतिहास में एक और अमेरिकी झूठ के तौर पर दर्ज होगा। 2003 में इराक पर हमला करते हुए भी यही झूठ बोला गया था कि सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं। फिर पूरी दुनिया ने देखा- न हथियार मिले, न सबूत। मगर इराक को खंडहर बना दिया गया।

अब वही खेल ईरान के साथ खेला जा रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि बम गिराकर परमाणु साइट्स को नष्ट कर दिया गया। जबकि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने खुद कहा कि नुकसान सीमित है और ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब भी चालू है।

सवाल ये है कि अगर खुफिया एजेंसियां सच्चाई बता सकती हैं, तो वही सच्चाई जनता के सामने क्यों नहीं रखी जाती? क्यों युद्धोन्माद फैलाकर पश्चिम एशिया को बार-बार युद्ध की आग में झोंका जाता है? क्योंकि अमेरिका के सैन्य-औद्योगिक तंत्र को हथियार बेचने और क्षेत्रीय अस्थिरता बनाए रखने की आदत है।

ईरान ने अब साफ कर दिया है कि जब तक उसकी परमाणु फैसिलिटी की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाएगी, वह IAEA को न

डेटा देगा, न कैमरे लगाने देगा। यही नहीं, संसद में कई सांसदों ने यहां तक कह दिया है कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो ईरान NPT से भी बाहर निकल सकता है।

यह वही एनपीटी है, जिससे उत्तर कोरिया पहले ही बाहर निकलकर खुलेआम परमाणु हथियार बना चुका है। और अमेरिका उसे रोक नहीं सका। अब ईरान का ये संकेत पश्चिमी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। क्योंकि अगर ईरान NPT छोड़ता है, तो पश्चिम एशिया में परमाणु होड़ की शुरुआत हो जाएगी। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे देश भी यही रास्ता चुन सकते हैं।

चीन और रूस ने भले ही अभी तक सार्वजनिक बयान न दिया हो, मगर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उनका रुख जगजाहिर है। दोनों पहले भी IAEA के निर्णयों में ईरान का बचाव कर चुके हैं। संभव है, ईरान के इस फैसले को वे बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए समर्थन दे रहे हों।

अगर यह ध्रुवीकरण और मजबूत होता है, तो अमेरिका-इस्राइल और पश्चिमी देशों का दबदबा टूटेगा। एक नया 'ईस्टर्न ब्लॉक' उभर सकता है, जिसमें ईरान, चीन, रूस और कई मध्य एशियाई देश शामिल हो सकते हैं। और उस ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा हथियार होगा- 'पश्चिमी पाखंड की पोल खोलना'।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इस्राइल और अमेरिका खुलेआम ईरान को दोबारा हमले की धमकी दे रहे हैं। नेतन्याहू ने तो साफ कहा है कि जरूरत पड़ी तो इस्राइल फिर से हमला करेगा। ट्रंप ने भी अपनी स्वीकृति दे दी।

यदि ऐसा हुआ, तो परमाणु फैसिलिटी पर हमला NPT की अंतरात्मा पर आखिरी कील साबित होगा। फिर किसी को रोकना संभव नहीं रहेगा। ईरान यदि NPT छोड़ता है, तो परमाणु हथियारों का नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और जब परमाणु हथियार अनियंत्रित हाथों में पहुंचें- तो मानवता का विनाश सुनिश्चित है।

अब और नहीं : दुनिया को यह समझना होगा कि परमाणु सुरक्षा, IAEA की मुनादी और अमेरिकी पाखंड पर नहीं टिक सकती। ईरान ने जो किया, वह भले ही नियमों के खिलाफ हो, मगर उसकी पृष्ठभूमि में जिस हद तक अन्याय और पक्षपात हुआ, उसकी अनदेखी भी अब नहीं की जा सकती।
यदि विश्व समुदाय अब भी चुप बैठा रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब हर क्षेत्रीय शक्ति अपनी परमाणु ताकत बनाएगी, और तब न IAEA बचेगा, न NPT। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा, जब दुनिया युद्ध की आग में जल उठेगी और उन मलबों पर बस यही सवाल लिखा होगा- 'कहाँ है वह वैश्विक व्यवस्था, जिसने इंसाफ करने का वादा किया था?'

शंघाई में रक्षा मंत्रियों की बैठक : पहलगाम हमले को नजरअंदाज करने पर जताई नाराजगी

भारत सख्तः संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर से इनकार

पहलगाम हमले को नजरअंदाज करने वाले संयुक्त बयान पर भारत ने हस्ताक्षर न करके न सिर्फ़ अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया, बल्कि चीन पाक गठजोड़ की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए।

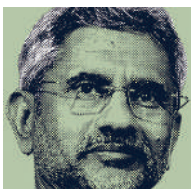

"एससीओ की मूल भावना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी। एक देश ने आतंकवाद का उल्लेख रोकने पर आपत्ति जताई और यह देश हम अनुमान लगा सकते हैं, यानि पाकिस्तान था। इसमें कोई संशोधन न मिल पाने के कारण भारत ने दस्तावेज़ को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब संगठन का उद्देश्य ही आतंकवाद से लड़ना है, ऐसे में उस मुख्य उद्देश्य को पुष्टि करने वाला उल्लेख नहीं होना साफ तौर पर अस्वीकार्य था। अगर आतंक से लड़ना हमारा साझा लक्ष्य है, तो हमें हर घटना का उल्लेख करना चाहिए।"

-एस जयशंकर, विदेश मंत्री

राजस्थान टुडे ✍ न्यूज डेस्क

कूटनीति के मंचों पर अक्सर औपचारिकता और सहमति की भाषा बोली जाती है, लेकिन कभी कभी चुप्पी भी अपनी एक सशक्त भाषा बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। इसका कारण था, उस बयान में 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का कोई उल्लेख न होना। यह कोई साधारण आपत्ति नहीं थी, बल्कि भारत की आतंकवाद विरोधी नीति की रीढ़ को दर्शाने वाला ऐतिहासिक फैसला था।

जब सहमति खामोशी बन जाए

- एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में आमतौर पर सदस्य देश एक संयुक्त बयान पर सहमत होते हैं, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और आतंकवाद विरोधी प्रयासों का उल्लेख होता है। इस बार भी एक मसौदा तैयार किया गया, जिसमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों की निंदा की गई, लेकिन भारत में हाल ही में हुए आतंकी हमलों, विशेषतः पहलगाम की घटना को अनदेखा किया गया।
- भारत ने इस पर आपत्ति जताई और दस्तावेज में संतुलित और निष्पक्ष आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण की मांग की। लेकिन जब बाकी सदस्य देश- विशेषकर चीन और पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं हुए, तो भारत ने साफ शब्दों में उस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।

स्पष्ट है भारत का संदेश

- राजनाथ सिंह ने बैठक में दो टूक कहा, "आतंकवाद को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। इसका विरोध सार्वभौमिक होना चाहिए, न कि सुविधाजनक।"
- यह वक्तव्य सिर्फ एससीओ के लिए नहीं था, बल्कि वैश्विक कूटनीति को एक स्पष्ट संदेश था—भारत अब मंच पर उपस्थिति भर से संतुष्ट नहीं, वह अपनी आवाज़ और नीतियों के सम्मान की मांग करता है।

चीन-पाक गठजोड़ का कूटनीतिक जाल

- यह भी ध्यान देने योग्य है कि एससीओ में चीन और पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आतंकवाद जैसे मुद्दों पर दोहरा रवैया अपनाना कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान बार बार आतंक को "रणनीतिक उपकरण" की तरह इस्तेमाल करता आया है, जबकि चीन अक्सर पाकिस्तान की ढाल बनकर खड़ा रहता है।
- बलूचिस्तान का उल्लेख करना और पहलगाम को नजरअंदाज करना, इसी रणनीति का हिस्सा था—दूसरों की पीड़ा दिखाना, अपनी जिम्मेदारी से बचना।

चुप्पी से बनी गूंज

- भारत के इनकार के चलते एससीओ के इतिहास में यह दुर्लभ मौका रहा, जब कोई संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका। यह कूटनीति की भाषा में बड़ा संकेत है कि भारत अब 'सम्मेलन के नाम पर समझौता' नहीं करेगा।
- यह घटना बताती है कि भारत सिर्फ उपस्थिति नहीं चाहता, बल्कि सार्थक भागीदारी चाहता है—जिसमें उसकी सुरक्षा चिंताओं को बराबरी से सुना और सम्मानित किया जाए। भारत का यह रुख साहसिक और आवश्यक था। यह उस देश की नीति का प्रतिबिंब है जो वैश्विक मंचों पर सिर्फ भागीदार नहीं, दिशा-निर्धारक बनना चाहता है। आतंकवाद के मुद्दे पर स्पष्ट असहमति दर्ज कर भारत ने यह भी दिखा दिया कि कूटनीति में भी सिद्धांतों का स्थान सर्वोपरि होता है। यदि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं वास्तव में प्रभावी बनना चाहती हैं, तो उन्हें भारत जैसे राष्ट्रों की आवाज़ को अनदेखा करना बंद करना होगा, जो न सिर्फ़ अपने लिए, बल्कि एक निष्पक्ष, सुरक्षित और आतंक-मुक्त विश्व व्यवस्था के लिए खड़े होते हैं।

ईरान-इजरायल युद्ध में कौन जीता : दुनिया के एक और संघर्ष में अमेरिका की शातिर कूटनीति

समझ आ गया महाशक्ति का महाखेल

हाल में पहलगाम आंतकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच भड़के तनाव के बाद भी अमेरिका ने यही चाल खेली थी। उसने पाकिस्तान को भरोसे में लेकर दुनियाभर के आश्वासन उसकी झोली में डाल दिए। पाकिस्तान को भी लगा कि अमेरिका की गोद में बैठकर वह सुरक्षित रहेगा और भारत उस पर आगे काई कार्रवाई नहीं करेगा। अमेरिका ने भारत के साथ जो चालें चलीं, कमोबेश वैसा ही इस्त्रायल के साथ किया। ट्रम्प ने अपने दोनों अच्छे दोस्तों भारत और इस्त्रायल के साथ खड़े होने का ड्रामा भी रच दिया और अपना कूटनीतिक दांव भी खेल दिया।

राजेश कसेरा ✍ वरिष्ठ
पत्रकार एवं राजनीति विश्लेषक

ईरान और इस्त्रायल के बीच उपजा तनाव जब अमेरिका के दखल से संघर्ष विराम के हालात तक पहुंचा तो एक चर्चित शायर का शेर 'दुनिया में गूंजता सुनाई दिया- न खुदा ही मिला न विसाल-ए-सनम, न इधर के रहे न उधर के हम।' खरबों रुपए जंग में बहाने के बाद परिणाम शांति और सौहार्द से ही निकलना था तो 12 दिनों तक क्यों एक-दूसरे के खून का प्यासा बनकर ताकतवर मिसाइल, गोले और हथियार बरसाते रहे? इस सवाल का जवाब तो ईरान और इस्त्रायल को उनकी अवाम के समक्ष आगे-पीछे देना ही होगा। दो बिल्लियों के इस युद्ध में बंदर बनकर अमेरिका फिर बाजी मार ले गया। बिना किसी परवाह और डर के दुनिया की इस महाशक्ति ने ईरान के परमाणु स्थलों पर भारी-भरकम बमों से हमला किया। साबित कर दिया कि वह कहीं भी कुछ भी कर सकता है और कोई उसे रोकने-टोकने की हिमाकत नहीं कर सकता।

ईरान ने भी अमेरिका की कार्रवाई पर पलटवार करने के बजाय उसके कहने पर सीजफायर कर लिया। इसके बाद तीसरे विश्व युद्ध की भयावह आशंका उपजने से पहले फिर एक बार थम गई। भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह कराने का श्रेय लेने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ईरान-इजरायल के बीच भी संघर्ष विराम करने का नायक बनकर उभर गए। इजरायल के पक्ष में खड़ा होने के बाद जैसे ही युद्ध थमा, ईरान को 2.5 लाख करोड़ रुपए देने की पेशकश कर दी। इतना ही नहीं अमेरिका ने तो यहां तक मन बना लिया कि वह ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में भारी इन्वेस्टमेंट करेगा और उस पर बरसों से लगाए गए ज्यादातर प्रतिबंधों को भी हटा देगा। इसे क्या कहेंगे? गाल पर कसकर तमाचा मार दो, फिर उसे सहला कर दवा देने का भरोसा जता दो।

हाल में पहलगाम आंतकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच भड़के तनाव के बाद भी अमेरिका ने यही चाल खेली थी। उसने पाकिस्तान को भरोसे में लेकर दुनियाभर के आश्वासन उसकी झोली में डाल दिए। पाकिस्तान को भी लगा कि अमेरिका की गोद में बैठकर वह सुरक्षित रहेगा और भारत उस पर आगे काई कार्रवाई नहीं करेगा। अमेरिका ने भारत के साथ जो चालें चलीं, कमोबेश वैसा ही इस्त्रायल के साथ किया। ट्रम्प ने अपने दोनों अच्छे दोस्तों भारत और इस्त्रायल के साथ खड़े होने का ड्रामा भी रच दिया और अपना कूटनीतिक दांव भी खेल दिया।

इस्त्रायल को इस संघर्ष से क्या मिला?

इस्त्रायल लंबे समय से कहता रहा कि ईरान उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन उसने पहले कभी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं किया। 13 जून को उसने नतांज और इस्फहान परमाणु क्षेत्रों की सतह पर बमबारी कर ईरान के सब्र को तोड़ दिया। जवाब में ईरान ने इस्त्रायल पर जवाबी कार्रवाई की। इस्त्रायल ने पहले भी सीरिया और इराक में परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया था, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि वह बहुत दूर जटिल मिशन को अंजाम दे सकता है। इस दौरान इस्त्रायल ने अंतरराष्ट्रीय आरोपों का सामना किया कि उसका मिशन कानूनी नहीं था। हालांकि इस्त्रायल ने दावा किया कि यह पूर्वानुमानित आत्मरक्षा थी, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं थे कि ईरान परमाणु बम विकसित कर रहा है। या इस्त्रायल के खिलाफ उसके इस्तेमाल की योजना बना रहा है। लेकिन इस संघर्ष के दौरान इस्त्रायल ने साबित कर दिया कि वह अमेरिका को सीमित मिडिल ईस्ट में आक्रमण में शामिल होने के लिए मना सकता है। साल 1967 और 1973 में हुए पिछले युद्धों में जब इस्त्रायल पर हमला हुआ था तो अमेरिका ने उसे सहायता प्रदान की थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भागीदारी के साथ कभी नहीं उतरा था।

ईरान परमाणु कार्यक्रम की रक्षा में कितना कामयाब?

इस संघर्ष के दौरान इस्त्रायल ने ईरान के जमीनी लक्ष्यों को काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया। सेटेलाइट से मिली तस्वीरों में भी सामने आया कि अमेरिकन मिसाइलें तय लक्ष्यों पर गिरीं, लेकिन इसकी पुष्टि के कोई सबूत सामने नहीं आए कि परमाणु ठिकाने नष्ट हुए या नहीं। ये सच तो तभी सामने आएगा, जब मौके का निरीक्षण और परीक्षण होगा। हालांकि युद्ध ने ईरान की ताकत को भी दुनिया के सामने लाने काम किया। न तो उसने इस्त्रायल की कोई बात मानी और न ही अमेरिका के किसी दबाव में आया। इस्त्रायल की लगातार बमबारी के बावजूद इस्लामिक रिपब्लिक ने जवाबी हमले जारी रखे, जिससे इस्त्रायल को भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा अमेरिका के अल उदीद एयर बेस पर हमले के जरिए ईरान ने दिखा दिया कि वह जवाब देने में सक्षम है।

सीजफायर कराकर अमेरिका को क्या मिला?

ईरान- इस्त्रायल संघर्ष के बीच अमेरिका के बी-2 बॉम्बर विमानों ने ईरान में तीन हमले किए। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि यह हमला बहुत सफल रहा और इसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन पेंटागन के शुरुआती आकलन और अन्य विशेषज्ञों ने साफ कहा कि तीनों परमाणु स्थलों को हुआ नुकसान उतना बड़ा नहीं था, जितना दावा किया गया। ट्रम्प भले ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को खत्म करने में सफल नहीं हुए हों, लेकिन वे कम से कम कुछ हद तक शांति दूत की भूमिका निभाने में सफल दिखे। दो महीनों में एशिया और मिडिल ईस्ट के दो बड़े संघर्षों में शांतिदूत की भूमिका निभाने वाले ट्रम्प को पाकिस्तान के बाद खुद के देश से भी मिली-जुली सराहना मिली। अमेरिकी हाउस के प्रतिनिधि बडी कार्टर ने ट्रम्प को इस्त्रायल और ईरान के बीच युद्ध विराम कराने में उनकी असाधारण और ऐतिहासिक भूमिका के लिए वर्ष 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए बकायदा नामित भी कर दिया।

भारत ने पहले ही भांप लिया था

हवा का रूख

भारत ने वर्ष 2025 में रोजाना 51 लाख बैरल तेल की खरीद की, जो उसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश बनाता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 86 फीसदी कच्चा तेल बाहर से आयात करता है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर क्रूड की कीमतों या आपूर्ति को लेकर समस्या बढ़ती तो भारत की चिंता गहरा जाती। हालांकि वैश्विक हालात को देखते हुए भारत ने खाड़ी देशों पर निर्भरता पहले की कम करने की योजना पर काम कर शुरू कर दिया था। भारत सरकार को पता था कि मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों के बीच तनातनी का व्यापक असर भविष्य में दिख सकता है। यही कारण रहा कि फरवरी 2022 से पहले भारत अपनी जरूरत का मुश्किल से आधा फीसदी तेल रूस से खरीदता था। आज देश के कुल आयात का 30 से 35 फीसदी तेल हर माह रूस से आ रहा है। सरकार के इस फैसले का असर इस रूप में भी दिखा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान चाहे सीरिया विवाद हो, गाजा संघर्ष हो या मौजूदा ईरान- इस्त्रायल विवाद, भारत को रूस से तेल लेने में भारत को कोई परेशानी नहीं हुई। पेट्रोलियम मंत्रालय की मानें तो भारत का मकसद रूस, अमेरिका जैसे देशों से बड़े पैमाने पर क्रूड खरीदने के साथ नाइजीरिया, मैक्सिको, अंगोला, गुयाना जैसे देशों से तेल आयात बढ़ाने का है। इस समय मोटे तौर पर भारत रूस से 35 फीसदी, इराक से 19 फीसदी, सऊदी अरब से 14 फीसदी, यूएई से 10 फीसदी और अमेरिका से पांच फीसदी तेल खरीद रहा है।

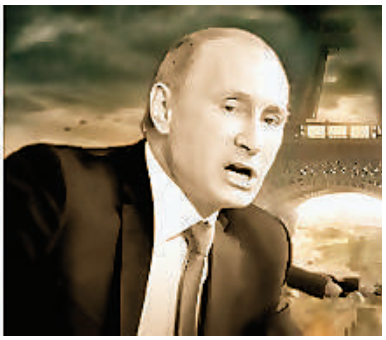

ईरान- इस्त्रायल युद्ध में क्यों दूर रहा रूस?... अमेरिका ने इस्त्रायल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो रूस ने निंदा की। ईरान के शीर्ष राजनयिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से समर्थन मांगने भी पहुंचे। लेकिन निंदा से ज्यादा रूस ने ईरान को कोई मदद नहीं दी। न ही ईरान के पक्ष में युद्ध में उतरने के कोई संकेत दिए। विश्व युद्ध की मंडराती आंशकाओं के बीच भी रूस ने अपने फायदे का गणित पूरा लगाया। उसे लग गया कि युद्ध में किसी का साथ देने के बजाय वह कुछ अल्पकालिक लाभ प्राप्त कर सकता है। जैसे कि तेल की कीमतों में वृद्धि, इससे रूस की डूबती अर्थव्यवस्था को मदद मिले या यूक्रेन में तीन साल से जारी युद्ध से विश्व का ध्यान हट सके। साथ ही वह इस्त्रायल के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। दोनों देशों की सेनाएं सीरिया में सक्रिय हैं और वे सीधे टकराव नहीं चाहते। इधर, इस्त्रायल यूक्रेन युद्ध के दौरान काफी तटस्थ रहा, क्योंकि वह रूस को नाराज करने से बचना चाहता था। रूस में यहूदियों की आबादी बड़ी संख्या में है। यही कारण रहा कि ईरान- इस्त्रायल के संघर्ष में रूस ने मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभाई।

इस तनाव से बढ़ी भारत की आर्थिक चिंताएं

ईरान और इस्त्रायल के बीच यदि तनाव और बढ़ता तो भारत के व्यापार पर गंभीर असर पड़ता। इस्त्रायल-हमास युद्ध और हूती विद्रोहियों के कारण पहले से शिपिंग मार्ग बाधित रहे थे। ऐसे में होरमुज जलडमरूमध्य भी प्रभावित होता तो पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत का आयात-निर्यात प्रभावित होता। ईरान के साथ इस इलाके में भारत के जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और यमन के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। इन देशों से भारत

33.1 बिलियन डॉलर (2.75 लाख करोड़) का आयात और 8.6 बिलियन डॉलर (74.5 हजार करोड़) का निर्यात करता है। ये संकट बढ़ता तो भारत को ज्यादातर सामान केप ऑफ गुड होप (दक्षिण अफ्रीका) के रास्ते मंगाना पड़ता। वहीं होरमुज का रास्ता ठप होने से तेल लाने को नए रास्ते खोजने पड़ते। इससे भारत में कच्चे तेल के साथ पेट्रोल और डीजल के दामों में भी उछाल का संकट आता।

ईरान से भारत के निर्यात और आयात

ईरान में भारत का निर्यात : **1.24** बिलियन डॉलर (**1.07** लाख करोड़ रुपए)

ईरान से भारत के आयात : **441.8** बिलियन डॉलर (**38.25** लाख करोड़ रुपए)

भारत से ईरान को निर्यात की जाने वाली चीजें

निर्यात की जाने वाली वस्तु	व्यापार (मिलियन डॉलर)	कीमत (रुपयों में)
बासमती चावल	753.2	6.52 हजार करोड़
केले	53.2	461 करोड़
सोया मील	70.6	611.59 करोड़
काबुली चना	27.9	241.56 करोड़
चायपत्ती	25.5	220.93 करोड़

भारत और इस्त्रायल के बीच व्यापार

इस्त्रायल में भारत के निर्यात : **2.1** बिलियन डॉलर (**1.82** लाख करोड़ रुपए)

इस्त्रायल से भारत के आयात : **1.6** बिलियन डॉलर (**1.39** लाख करोड़ रुपए)

ट्रेड वॉर से वैश्विक व्यापार में गिरावट

व्यापार के लिहाज से लाल सागर बेहद अहम है। दुनिया का 12 फीसदी व्यापार इसी मार्ग से होता है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार ट्रेड वॉर के कारण पहले ही वैश्विक व्यापार में 0.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। ऐसे में मिडिल ईस्ट का तनाव और लंबा चलता तो भारत समेत दुनिया के कई देशों के व्यापार पर खराब असर पड़ता।

ऊर्जा सुरक्षा पर ज्यादा खतरा

सबसे बड़ी चिंता हॉर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर थी। यहां से भारत के 60-65 प्रतिशत कच्चे तेल की आपूर्ति होती है। यह मार्ग इतना अहम है कि यह अकेले वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत संभालता है। यह जलडमरू मध्य ईरान और ओमान/संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थित है। इसके जरिए सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और कतर से तेल और एलएनजी का निर्यात होता है। भारत 80 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे में यहां आपूर्ति बाधित होती तो देश में ईंधन महंगा होता, मुद्रास्फीति बढ़ती, रुपए पर दबाव बनता और राजकोषीय संतुलन बिगड़ जाता।

'हम क्रांति करके शांति का नोबेल लेकर रहूंगा'

यू-टर्न का पैटेंट करा चुके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प से डिमेंशिया भी शर्मिंदा

हरीश मलिक ✍ वरिष्ठ व्यंग्यकार

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का पसंदीदा शौक शादियां करने के अलावा दूसरों के फटे मे टांग अड़ाना भी है। वे भारत-पाक के बीच युद्ध रुकवाने का तीस-मारखांनुमा दावा इतना दोहरा चुके हैं कि अब नींद में भी सीजफायर-सीजफायर की आवाजें आती हैं। अरबपति एलन मस्क से लेकर चीन तक उनके कितने ही बयानों से वे इतनी बार मुकर चुके हैं कि अब डिमेंशिया भी शरमाने लगा है। ट्रम्प ने यू-टर्न का तो जैसे पैटेंट ही करा लिया है। इसलिए वे जब चाहे, जैसे चाहे यू-टर्न ले सकते हैं। अमेरिका-ईरान युद्ध के यू-टर्न स्पॉट पर उनसे हुई चकल्लस के चुनिंदा अंश....

? ट्रंप 2.0 के साथ आप बड़े जोर-शोर से टैरिफ वार लाए। कभी बढ़ाया, कभी घटाया। कभी लगाया, फिर हटाया। और चीन की चकाचौंध के आगे आपकी चूं क्यों बोल गई?

ट्रम्प : आप सवाल को अनावश्यक लंबा खींच रहे हैं। सीधे-सीधे पूछिए ना कि हमने यू-टर्न क्यों लिया? देखिए, पहले आप ये समझिए कि यू-टर्न बना ही क्यों है? यू-टर्न दरअसल यू-टर्न लेने के लिए ही बना है। अब आप यू-टर्न नहीं लेंगे तो इसके कोई मायने ही नहीं रह जाएंगे। अभी तो इस दूसरे कार्यकाल की शुरुआत ही है। तीन-तीन महीने के एक्सटेंशन के अलावा कई यू-टर्न और आ सकते हैं। (मुस्कराकर) तब चीन की भी चूं बोल जाएगी!

? हमने आपके पहले कार्यकाल में मैनहट्टन में आपका ट्रम्प टावर देखा था। वहां बेहद उम्दा किस्म का बार बनाने की कोई खास वजह?

ट्रम्प : हंसते हुए...आप जर्नालिस्ट की नजर पहले वाइन एंड व्हिस्की पर ही क्यों जाती है? भव्य ट्रंप टावर में 60 फुट ऊंचा झरना और कई यादगार वस्तुएं नहीं दिखीं थीं? अब आपने बार की याद दिलाई है तो बता दूं कि वाकई में दो-चार पैग के बाद ही हमें दुनिया की चिंता सताने लगती है। यही वो जगह है जहां पर हमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (एमएजीए) के लिए अपने बिजनेस को और बढ़ाने के आइडिया आने लगते हैं। यू नो, बेसिकली आई एम ए सक्सेसफुल बिजनेसमेन। पॉलिटिक्स तो पार्ट-टाइम है!

? यू आर राइट! शायद इसीलिए आप रूस-यूक्रेन का युद्ध रुकवा नहीं पाए। अब इजराइल-ईरान के बीच क्यों कूद रहे हैं?

ट्रम्प : लुक, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट....। हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जैलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाया। डराया-धमकाया और लंच भी कराया। लेकिन वो पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख मुनीर की तरह हमारे बहकावे में नहीं आए। दरअसल, वो बेसिकली कॉमेडियन हैं। इसलिए वॉर को भी कॉमेडी ही समझ रहे हैं। अब हमारा बिजनेस आइडिया ये है कि इनको बेचे जाने वाले हथियारों की कीमतें बढ़ा दी जाएं। युद्ध रुका तो ठीक, वरना अपना खजाना तो भर ही जाएगा। और जहां तक ईरान पर हमले की बात है, तो इसकी उलटी गिनती पहले ही शुरू हो गई थी। दुनिया को अब दिखा। भला इस्लामिक कंट्री ईरान का परमाणु बम हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं?

? परमाणु बम तो पाकिस्तान के पास भी है। फिर आप ईरान का ही विरोध क्यों कर रहे हैं?

ट्रम्प : एक्चुअली, आई लव पाकिस्तान। यह मुल्क भले ही बहुत गरीब है, लेकिन हमारे दिल के बहुत करीब है। यहां के लोग छोड़िए.. सैन्य प्रमुख तक इतने भोले-भाले हैं कि व्हाइट हाउस के छोटे से लंच पर ही कुर्बान हो जाते हैं। इस गोश्त-युक्त लंच की खातिर अपने जमीर, अपने पाकिस्तान, अपने दोस्त ईरान.. सबका सौदा करने में ये जरा भी देर नहीं लगाते। इस पर भी एक्सट्रा बोनस ये कि पाक ने हमारे लिए नोबेल पीस प्राइज की ऑफिशियल पैरवी भी कर दी है। आई लव दिस स्प्रिट!! ये सारे गुण ईरान में कहीं नजर नहीं आते।

? लेकिन आपने ऐसा क्या बड़ा काम किया है, जिसके लिए आपको नोबेल पीस प्राइज मिले?

ट्रम्प : काम (आंखें मींचकर) ...वो तो इतने किए हैं कि बस पूछो मत। क्या आपको पता है कि सर्बिया और कोसोवो के बीच पहले क्रांति और फिर शांति कौन लाया? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा के बीच पहले झगड़ा और फिर समझौता किसने कराया? वही, जिसके साथ आज आपको इंटरव्यू का सौभाग्य मिला है। मुझे तो मिस्र और इथियोपिया की युद्धभूमि में ही नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए था। रूस के खिलाफ यूक्रेन के राष्ट्रपति को दबाने, धमकाने और हड़काने का काम हमने ही किया। बमुश्किल एक करोड़ की आबादी वाले इजराइल में इतनी शक्ति कहां थी कि वो अकेला ईरान से भिड़ जाए। उसके पीछे भी असली ताकत हम ही हैं। बस आप यह मान लीजिए कि विश्व में जहां-जहां युद्ध है, वहां है अमेरिका और वहां हैं हम। बोले तो हम हैं यम!!

? तो क्या अब आपको नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा?

ट्रम्प : असलियत में मुझे इतने सारे युद्धों में 'सक्रिय भूमिका' निभाने के लिए एक बार नहीं, बल्कि 4-5 बार नोबेल पीस अवार्ड मिल जाना चाहिए था। लेकिन इतना चालाक और स्मार्ट होने के बावजूद नोबेल देने वालों को मेरी शक्ल ही पसंद नहीं आती। कभी-कभी तो मुझे लगता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन ये लोग नोबेल शांति पुरस्कार मुझे शायद ही देंगे! अपने पास अकूत दौलत है, लेकिन यह ऐसी चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती। वरना इतनी मिन्नतें करने की ट्रम्प की आदत नहीं है! लेकिन अभी दुनिया में कितने ही देश हैं, जहां युद्ध नहीं हुआ है, इसलिए मैंने भी हार नहीं मानी है। हम क्रांति से शांति का नोबेल लेकर रहेंगे। जब तक सांस है, विश्वास है।

? लेकिन आप भारत-पाक वार के बीच सीजफायर कराने का राग बार-बार क्यों अलाप रहे हैं?

ट्रम्प : देखो, पाकिस्तान तो अपना बच्चा है। लेकिन भारत जिस तेजी से दुनियाभर में अपनी पैठ बना रहा है, वह हतप्रभ करने वाला है। इकोनॉमी की रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी तेज है। इस ट्रेन को रोकने के लिए कुछ तो करना ही होगा। वरना दूसरे देशों का एक्सीडेंट तय है। इसलिए अपन ने जानबूझकर ऐसा बयान दे डाला। बाकि काम को हर बात के सबूत मांगने वाला आपके यहां का विपक्ष पूरा कर ही रहा है।

? आप पर यह भी आरोप हैं कि दूसरे देशों में युद्ध भड़काकर अपना खजाना भरने में लगे हैं।

ट्रम्प : इस अमेरिकी राष्ट्रपति पर यह आरोप लगाना एकदम अनगल है। इतिहास में जाकर देखिए कि अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर कैसे बना? अमेरिका की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ हथियारों के निर्यात पर निर्भर है। साल 2024 में ही अमेरिका ने 318.7 बिलियन डॉलर के हथियार बेचे हैं। सोचिए, अगर दुनिया से युद्ध बंद हो जाएं तो हमारी इकोनॉमी का क्या होगा? इसलिए सभी अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे ही खजाना भरते रहे हैं। कई बार यह भी देखने को मिला है कि अगर दो देशों में लड़ाई हो रही हो तो अमेरिका उन दोनों देशों को हथियार सप्लाई करता है। वो अमेरिका से हथियार लेकर एक-दूसरे पर आक्रमण करते हैं। यदि जंग में कुछ कमी रह जाए तो हमें मजबूरी में कूदना पड़ता है। ईरान पर अमेरिका का आक्रमण इसका ताजा उदाहरण है। आपको भी यह समझना होगा कि देशों के बीच होने वाले युद्धों पर ही हमारी इकोनॉमी टिकी है। और अपने देश की मजबूती के लिए हम कुछ भी करेगा....!!

भले ही कोई हारा-जीता न हो, लेकिन पाकिस्तान का दोगलापन सामने आ गया

उतर गए कई नकाब!

पाकिस्तान सैन्य भाषा में जब 'न्यूट्रल' यानी खत्म कर दिया गया तो अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला करने का कदम उठाया। उसे भरोसा था कि चीन और रूस भले ही ईरान के दोस्त और व्यापारिक भागीदार हों, लेकिन वे हमले की निंदा के अलावा कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान को अपने पक्ष में मिला लेना ही ट्रम्प की सबसे बड़ी जीत थी।

सुरेश व्यास ✍ वरिष्ठ पत्रकार
एवं राजनीतिक विश्लेषक

मध्य-पूर्व एशिया की बड़ी सामरिक ताकत के रूप में उभरे इस्त्रायल और तेल कुबेर ईरान के बीच अमेरिकी इशारे पर लगभग बारह दिन चली जंग के बाद कथित अमेरिकी दबाव से ही 24 जून को संशयपूर्ण युद्धविराम हो गया, लेकिन इस घटनाक्रम ने कई देशों के चेहरों से नकाब उतार दिए। ईरान से दोस्ती का दम भरने वाले रूस और चीन हो या फिर ईरान के अहसानों तले दबा पाकिस्तान। सामने आ गया कि संकट के वक्त किसने ईरान का साथ दिया। इसमें सबसे ज्यादा संदिग्ध भूमिका पाकिस्तान की रही, जिसके सैन्य प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने युद्ध के दौरान ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के न्यौते पर व्हाइट हाउस में मुर्ग-मुस्सलम उड़ाए और कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ट्रम्प को शांति का नोबेल पुरस्कार देने का प्रस्ताव कर दिया।

हालांकि मुनीर को दावत अमेरिका की चाल थी, ताकि पाकिस्तान युद्ध में ईरान का समर्थन नहीं करे, लेकिन इस चाल में जनरल मुनीर इतना आसानी से फंस जाएंगे, ये माना नहीं जा सकता। खैर पाकिस्तान के इस कदम का उसके घर में ही विरोध शुरू हो गया। पाकिस्तान की निर्वाचित शाहबाज शरीफ सरकार को जवाब देते नहीं बना। इसी दौरान अमेरिका ने लगभग 22 साल बाद किसी युद्ध में कूदते हुए ईरान पर हमला कर दिया। दुनिया के सबसे महंगे लड़ाकू विमान बी-2 बॉम्बर ने अमेरिकी सैन्य अड्डे मिसौरी से उड़ान भरकर 18 घंटे तक लगातार सफर किया और 22 जून को ईरान के तीन शहरों फोर्डो, नेतांज व इस्फहान पर तीन हजार टन वजनी बंकर बस्टर जीयू बम गिराकर उसके परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया। इसके अलावा अमेरिकी पनडुब्बी से ईरान पर टॉमहॉक मिसाइलें भी दागी गई। इसके तुरंत बाद विमान वापस लौट गए और कुछ देर बाद ट्रम्प ने आधिकारिक रूस से ईरान पर हमले की पुष्टि कर दी। अमेरिका ने इससे पहले साल 2003 में ईराक पर हमला किया था। इसके बाद यह पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने किसी विदेशी धरती पर आक्रामकता दिखाई।

अमेरिका ने यह कदम अचानक नहीं उठाया। इसकी पटकथा उसी दिन लिख दी गई थी, जिस दिन इस्त्रायल ने ईरान पर पहला वार किया था। इसके बाद ट्रम्प जब कनाडा से जी-7 देशों का शिखर सम्मेलन छोड़कर वाशिंगटन लौट गए, तभी दिखने लगा था कि इस्त्रायल-ईरान के युद्ध में अमेरिका भी सीधे तौर पर उतरने वाला है। इसके बाद से पेंटागन और व्हाइट हाउस ने कूटनीतिक प्रयास भी तेज कर दिए। पहले ट्रम्प ने जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर लगभग 35 मिनट तक बात की। उन्हें कनाडा से लौटते वक्त वाशिंगटन आने का निमंत्रण भी दिया, लेकिन मोदी ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला देते हुए इसे विनम्रतापूर्वक टाल दिया। यह ट्रम्प और अमेरिकी कूटनीति का एक अहम पड़ाव था। मोदी से बातचीत के तुरंत बाद ट्रम्प ने अमेरिकी यात्रा पर गए जनरल असीम मुनीर को दावत पर बुला लिया। इस दौरान क्या बात हुई, इसका खुलासा न तो व्हाइट हाउस ने किया और न ही पाकिस्तान ने, मगर इसे लेकर जरूर चर्चा हो गई कि ये दावत भी इस्त्रायल-ईरान युद्ध से जुड़ा एक कूटनीतिक कदम ही है। ऐसा इसलिए भी माना गया कि युद्ध शुरू होते ही ईरान ने पाकिस्तान पर अपना दोस्त होने का भरोसा किया और कह भी दिया कि जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान उसे परमाणु हथियार भी दे सकता है, लेकिन अमेरिकी चाल ने एक ही दावत में उसका यह भ्रम इस खबर के साथ तोड़ दिया कि पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प को शांति का नोबेल पुरस्कार देने का प्रस्ताव किया है।

इसके बाद पाकिस्तान सैन्य भाषा में जब 'न्यूट्रल' यानी खत्म कर दिया गया तो अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला करने का कदम उठाया। उसे भरोसा था कि चीन और रूस भले ही ईरान के दोस्त और व्यापारिक भागीदार हों, लेकिन वे हमले की निंदा के अलावा कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान को अपने पक्ष में मिला लेना ही ट्रम्प की सबसे बड़ी जीत थी। हालांकि पाकिस्तान ने फौरी तौर पर ही सही, लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा की और इसे अन्तरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया, लेकिन मुनीर के अमेरिकी कब्जे में होने से अमेरिका की सेहत पर इसका ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया।

अमेरिका हमला करके घर भी लौट गया। ईरान-इस्त्रायल लड़ते रहे। एक दूसरे पर प्रक्षेपास्त्र दागते रहे। इस्त्रायल को भी अपने प्रमुख शहरों तेल अवीब और हाइफा के अलावा अन्य स्थानों पर ईरानी हमलों की तबाही ने सहमाया। दुनिया भर में खौफ का पर्याय बना उसका रक्षा कवच गोल्डन डोम भी जैसे धाराशायी हो गया। एक बार तो स्थिति ये हो गई थी उसके पास दुश्मन के हमलों की पहचान करने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों का भी टोटा पड़ गया। इस्त्रायल को शायद पहली बार अहसास हुआ कि कोई उसका मुकाबला कर सकता है। इधर, ईरान ने लगभग चौबीस घंटे तक अमेरिकी कार्रवाई का कोई जवाब नहीं दिया और इसके बाद उसने जब कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे समेत खाड़ी के तीन स्थानों पर मिसाइलें दागी तो लगा कि अब तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ने वाला है। इसके अगले दिन ही ट्रम्प फिर सोशल मीडिया साइट एक्स पर नमूदार हुए और ऐलान कर दिया कि इस्त्रायल-ईरान लड़ाई रोकने पर सहमत हो गए हैं। अब कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने इसके बाद भी इस्त्रायल पर मिसाइल हमला कर दिया तो इस्त्रायल ने ईरान के हवाई ठिकानों को निशान बना लिया। इससे कई घंटे तक संशय बना रहा कि क्या वाकई युद्धविराम हो गया है?

इस दौरान ट्रम्प ने चौधराहट भी दिखाई और इस्त्रायल को अपने विमानों को वापस बुलाने और ईरान पर एक भी बम नहीं गिराने की चेतावनी तक दे दी। उन्हें लगा कि कोई उनकी सुन ही नहीं रहा है तो उन्होंने अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हुए कह दिया कि समझ में नहीं आ रहा ईरान और इस्त्रायल कर क्या रहे हैं? खैर, लड़ाई रुक गई और अमेरिकी कांग्रेस से इसके लिए ट्रम्प को शांति का नोबल पुरस्कार देने के प्रस्ताव की अपुष्ट खबरें भी आना शुरू हो गई।

कौन जीता, कौन हारा

अब सवाल ये है कि इस लड़ाई में जीता कौन? अमेरिका, इस्त्रायल या ईरान? अमेरिका इस बात से खुद को विजयी माना रहा है कि उसने ईरान को झुका दिया। इस्त्रायल इस बात से खुश है कि ईरान की परमाणु ताकत खत्म हो गई और ईरान में इस बात का जश्न है कि वह दुनिया के सुपर पॉवर अमेरिका के सामने झुका नहीं, परमाणु सामग्री बचा ली और तख्तापलट की कोशिशें भी नाकाम हो गई। तीनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन दुनिया इसमें कुछ और ही देख रही है कि अब आगे क्या होगा।

निगलते बन रहा न उगलते

युद्ध के नतीजे चाहें कुछ भी रहे हों, लेकिन इसमें चीन-रूस के अलावा पाकिस्तान पूरी तरह बेनकाब हो गया। खुद के इस्लामी राष्ट्र होने का दम भरने वाला पाकिस्तान एक प्रमुख इस्लामी मुल्क ईरान से आ रही जश्न की तस्वीरों को देखकर भी नहीं कह सकता कि वह यूहदियों के सरपरस्त अमेरिका और इस्त्रायल से लोहा लेने वाले ईरान की इस खुशी में शरीक है। खास बात यह है कि कथित सीजफायर के बाद से न पाकिस्तान प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ नजर आ रहे हैं और न ही सैन्य प्रमुख जनरल मुनीर।

उल्टा पड़ा आपदा में अवसर का कदम

कारण साफ है कि इस्त्रायल-ईरान युद्ध शुरू होने से पहले शरीफ और मुनीर में अमेरिका के तलवे चाटने की हौड़ सी मची थी। दावा तो ये भी है कि मुनीर को दावत के दौरान ही ट्रम्प ने बता दिया था कि अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है, लेकिन पक्का पिट्ठू बनने के चक्कर में पाकिस्तान ने चुप रहकर अपने पारम्परिक दोस्त ईरान के साथ भी धोखा कर दिया। आपको याद ही होगा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ईरान ने पाकिस्तान से ही दोस्ती निभाई थी और जब उस पर संकट आया तो उसे पाकिस्तान से पूरी उम्मीद थी।

अब हो रही नींद हराम... सीजफायर के बाद अब पाकिस्तान अससमंजस में है। पाकिस्तानी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि अब वे ईरान को क्या लेकर मुंह दिखाएंगे? वे ईरान से दुश्मनी लेने की स्थिति में तो हैं नहीं और ऐसे में फिर पाकिस्तान पर कोई संकट आ गया तो वे किसे ताकेंगे? इसके अलावा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से ईरान के बदला लेने की आशंका से भी पाकिस्तान सहमा हुआ है। पाकिस्तान की सीमा ईरान से सीधे सटती है। ऐसे में उसे विध्वंशक कार्रवाई का डर भी सता रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान को आनन-फानन में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक भी बुलानी पड़ गई। दूसरी तरफ, पाकिस्तान सरकार को जनता के आक्रोश और विपक्षी नेताओं के तीखे सवालों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन नकाब चेहरे से एक बार सरक जाता है तो असलियत सामने आ ही जाती है और यही असलियत अब पाकिस्तान को इधर कुआं-उधर खाई की ओर धकेल रही है। कारण कि बलूचिस्तान का आंदोलन भी अब और अधिक जोर पकड़ेगा। इधर भारत, उधर अफगानिस्तान और अब ईरान से छत्तीस का आंकड़ा पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की नींद हराम किए हुए है।

सेना-सरकार में भी तनातनी

खबर तो यह भी है कि सीजफायर के बाद से पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व में भी तनातनी बढ़ रही है। सेना प्रमुख मुनीर मौन हैं तो सरकार अब बढ़ते जनाक्रोश के चलते डैमेज कंट्रोल करना चाह रही है। यह पाकिस्तान के सैन्य प्रशासन के गले नहीं उतर रहा। आने वाले दिनों में इसका भी कोई न कोई असर दिखाई देने वाला है।

इसलिए टला सत्ता परिवर्तन

इस्त्रायल-ईरान युद्ध में अमेरिकी एंट्री और इसके साथ ही अमेरिका में शरण ले रहे ईरान के निर्वासित राजघराने के वारिस की 'मेक ईरान ग्रेट अगैन' कॉल से संकेत मिल रहे थे कि अमेरिका ईरान की कट्टरपंथी सरकार को उखाड़ फैंकने में भी मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान ही आड़े आया। ट्रम्प से मुलाकात के दौरान मुनीर ने आशंका जताई कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो गया तो उसके ईरान से सटे बलूचिस्तान प्रांत के लड़ाके इसका फायदा उठाएंगे। कारण कि बलूचिस्तान में सशस्त्र हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ बलूच आंदोलनकारियों को समर्थन दे रहे ईरानी कट्टकपंथी ग्रुप जैश-अल-अदल ने भी इस्त्रायल-ईरान युद्ध को फायदे का मौका बताया था।

डॉलर पर निर्भरता से मुक्ति के प्रयास— अमेरिका की चिंता और भारत की चतुर रणनीति

रुपये की वैश्विक उड़ान

राकेश गांधी
वरिष्ठ पत्रकार

क्या कभी किसी ने सोचा था कि भारत का रुपया, जो दशकों से डॉलर की परछाई में खड़ा रहा, एक दिन विश्व मंच पर खुद को स्वतंत्र पहचान दिलाने के लिए आगे बढ़ेगा? आज यह सपना साकार होने की राह पर है। भारत अब न सिर्फ अपनी मुद्रा में व्यापार चाहता है, बल्कि दुनिया को यह भी बताना चाहता है कि आत्मनिर्भरता केवल उत्पादन की नहीं, भुगतान की भी होती है। यह आलेख उस परिवर्तन की कहानी है, जहां एक राष्ट्र अपने विचार, तकनीक और विश्वास के सहारे आर्थिक दासता की जंजीरें तोड़ना चाहता है — शांति, समानता और स्वाभिमान के साथ।

"भारत का डिजिटल भुगतान मॉडल और रुपये को वैश्विक व्यापार में शामिल करने की नीति विकासशील देशों के लिए प्रेरणा है।"
—**क्रिस्टालिना जॉर्जीवा,** आईएमएफ प्रमुख, जी-20 सम्मेलन 2024

दशकों से वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व रहा है, लेकिन अब यह एकाधिकार चुनौती के घेरे में है। आज का भारत आत्मनिर्भरता और डिजिटल नवाचार में उल्लेखनीय प्रगति कर चुका है। अब रुपये को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के निर्णायक प्रयास कर रहा है। जून 2025 तक की घटनाएं इस बदलाव की ठोस मिसाल हैं।

जून 2025 की ब्रिक्स बैठक में 'ब्रिक्स भुगतान नेटवर्क' के पहले चरण का उद्घाटन हुआ, जिसमें भारत की यूपीआई तकनीक को केंद्रीय भूमिका दी गई। भारत ने सदस्य देशों से आग्रह किया कि आपसी व्यापार का कम से कम 25 प्रतिशत भुगतान स्थानीय मुद्राओं में किया जाए। इस प्रस्ताव को रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का समर्थन मिला।

अप्रैल 2025 में भारत ने इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ रुपये में व्यापार के लिए सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर किए। वहीं, 'इंडिया-अफ्रीका समिट 2025' में 17 अफ्रीकी देशों ने भारत के डिजिटल ढांचे से जुड़ने और रुपये को अपनाने की इच्छा जताई।

वैश्विक स्वर और समर्थन

"भारत की मुद्रा नीति ने व्यापार को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा दिखाई है।"
-अलेक्सेई ओवेरचुक, रूस
"भारत इस विचार का नेतृत्व कर रहा है कि हम डॉलर के बिना भी व्यापार कर सकते हैं।"
-लूला डा सिल्वा, ब्राजील
"डिजिटल रुपया अफ्रीका के लिए आदर्श बन सकता है।"
-नाना अकुफो-अड्डो, घाना
"डॉलर विकल्प का प्रयास पारदर्शी हो, तो यह सहयोग योग्य है।"
-जेनेट येलेन, अमेरिका

नीतिगत नींव और तकनीकी शक्ति

भारत का यह रुख अचानक नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध रणनीति का परिणाम है। जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता (एसआरवीए) प्रणाली लागू की, जिससे रूस, श्रीलंका, नेपाल, मॉरीशस और जर्मनी से रुपये में व्यापार संभव हुआ। खासतौर पर रूस से 2023 में भारत ने 45 प्रतिशत तेल का आयात रुपये में किया। भारत और यूएई के बीच 2023 में रुपये-दिरहम व्यापार समझौता भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। डिजिटल रुपया (सीबीडीसी) के आगमन ने इस दिशा को और गति दी है।

अंतर्विरोध और अवसर... अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के 2024 आंकड़ों के अनुसार रुपये की अस्थिरता दर 3.6 प्रतिशत है, जो वैश्विक निवेशकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत एसडीआर टोकरी में रुपये को शामिल करने के प्रयास कर रहा है। इसके लिए तकनीकी दक्षता के साथ-साथ पारदर्शिता और नियामकीय मजबूती की आवश्यकता है। यह प्रयास केवल मुद्रा प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि 'विचार बनाम वर्चस्व' की टक्कर है। भारत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के पक्ष में है, जहां आर्थिक प्रभुत्व नहीं, समावेशी विकास और साझी समृद्धि प्राथमिकता हो।

दूरगामी प्रभाव के लिए संतुलन की जरूरत

सकारात्मक परिणाम

1. डॉलर निर्भरता में कमी

▪ डॉलर की मजबूती अक्सर भारत जैसे देशों की आयात लागत और मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है। रुपये में व्यापार से इस असंतुलन में कमी आ सकती है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटेगा

▪ जब लेन-देन रुपये में होंगे, तो भारत को डॉलर जैसे बाहरी मुद्रा भंडार की उतनी जरूरत नहीं होगी, जिससे मुद्रा भंडार का प्रबंधन अधिक कुशल होगा।

3. डिजिटल भुगतान और तकनीकी नेतृत्व

▪ यूपीआई और डिजिटल रुपया जैसे मॉडल के प्रसार से भारत दुनिया को सुरक्षित, तेज़ और सस्ती भुगतान प्रणाली उपलब्ध कराने वाला अग्रणी बन सकता है।

4. कूटनीतिक प्रभाव में वृद्धि

▪ मुद्रा स्वीकृति का सीधा संबंध राष्ट्र की साख और प्रभाव से होता है। रुपया को यदि क्षेत्रीय या वैश्विक मुद्रा का दर्जा मिलता है, तो भारत की कूटनीतिक पकड़ मजबूत होगी।

5. विकासशील देशों को वैकल्पिक मॉडल

▪ भारत का यह मॉडल अन्य विकासशील देशों के लिए प्रेरणा बन सकता है, जो डॉलर आधारित एकाधिकार से परेशान हैं।

VS

नकारात्मक परिणाम

1. विनिमय दर अस्थिरता का खतरा

▪ रुपये की अस्थिरता (3.6%) अभी भी चिंता का विषय है। यदि वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता बढ़ेगी, तो यह अस्थिरता और अधिक आर्थिक झटकों का कारण बन सकती है।

2. अमेरिका जैसे देशों की प्रतिक्रिया

▪ डॉलर को चुनौती देना अमेरिका के लिए भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा हो सकता है। इसके चलते भारत को अप्रत्यक्ष आर्थिक या कूटनीतिक दबाव झेलना पड़ सकता है।

3. वैश्विक व्यापारिक जाल में जटिलता

▪ एकीकृत वैश्विक प्रणाली में स्थानीय मुद्राओं की बहुतायत व्यापारिक प्रक्रिया को जटिल बना सकती है, विशेषकर बहुपक्षीय व्यापार में।

4. भरोसे और पारदर्शिता की चुनौती

▪ जब तक भारतीय बैंकिंग प्रणाली और नियामक ढांचा अंतरराष्ट्रीय मानकों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता, तब तक वैश्विक निवेशक और देश संकोच कर सकते हैं।

5. चीन की प्रतिस्पर्धा

▪ चीन अपनी मुद्रा युआन (आरएमबी) को पहले ही वैश्विक बनाने में जुटा है। भारत को एक समानांतर प्रयास के लिए अधिक सजग और रणनीतिक होना होगा, जिससे कहीं यह संघर्ष न बन जाए।

नई मुद्रा राजनीति की भूमिका में भारत: रुपये की वैश्विक उड़ान अभी प्रारंभिक है, लेकिन भारत जिस संयमित वैचारिक दृष्टिकोण, तकनीकी कौशल और नीति संतुलन के साथ आगे बढ़ रहा है, वह इसे सिर्फ मुद्रा नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व के प्रतीक के रूप में स्थापित कर सकता है। यह प्रतिस्पर्धा महज डॉलर को चुनौती देने की नहीं, बल्कि एक न्यायसंगत और बहुध्रुवीय वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की है, जिसमें भारत की भूमिका अब परिधि की नहीं, केंद्र की है।

प्रमुख 35 नदियों को जोड़ने का भगीरथी प्रोजेक्ट बदल सकता है देश के खेत खलिहान और परिवहन की सूरत

नदी नीरे-चमक जाएगी तकदीरें?

दिनेश जोशी
वरिष्ठ पत्रकार

भारत की नई जल रणनीति जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं से निपटने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना न केवल कृषि और जल आपूर्ति के क्षेत्र में बदलाव लाएगी, बल्कि भारत की जल सुरक्षा और रणनीतिक संप्रभुता को भी सुदृढ़ करेगी। जल अब केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि एक रणनीतिक पूंजी बन चुका है, जिसका विवेकपूर्ण उपयोग आने वाले समय में भारत की स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि का निर्धारक होगा।

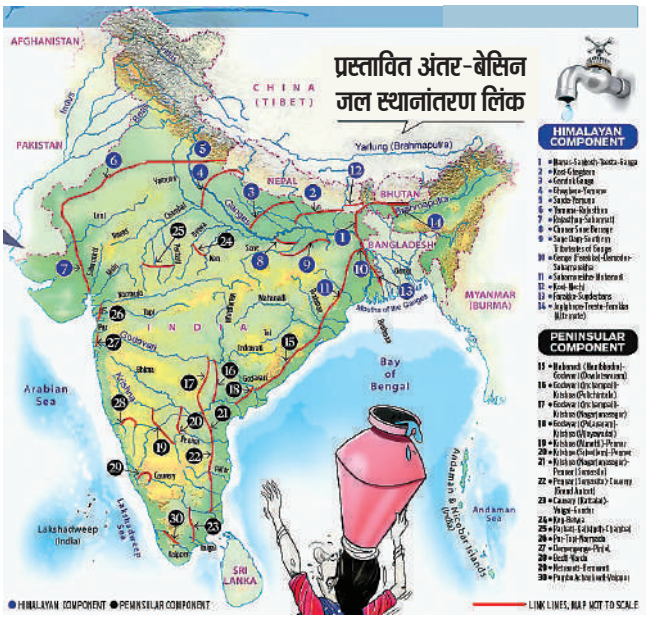

भारत में छोटी-बड़ी लगभग 200 मुख्य नदियां हैं। इनमें जल प्रवाह के मानक पर गंगा देश की सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई के अनुसार सिन्धु नदी सबसे बड़ी है। इनके अलावा पूर्वोत्तर की ब्रह्मपुत्र को उसके पाट यानी सर्वाधिक चौड़ाई के कारण 'नद' कहा जाता है। इंडियन मायथोलॉजी में भी नदियों को पवित्रता का आधार मानकर उनके संगम की परिकल्पना की गई है। प्रयागराज में तीन नदियों गंगा, यमुना व सरस्वती के प्राकृतिक संगम को त्रिवेणी नाम से जाना जाता है। मगर साथ ही गोदावरी, नर्मदा, सिंधु और कावेरी के संगम का आह्वान किया गया है—

"गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती।
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु॥"

अर्थात्, "हे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, इस जल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ।" ये नदियां भारत की पवित्रतम नदियां मानी गई हैं।

एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ सूखा

भारत विविध भौगोलिक और जलवायु वाला देश है, जहां एक ओर बाढ़ की विभीषिका है तो दूसरी ओर सूखे की त्रासदी। वर्षा का असमान वितरण और जल संसाधनों की असंतुलित उपलब्धता ने कृषि, पेयजल, और जलविद्युत जैसे क्षेत्रों में भारी असंतुलन पैदा किया है। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए "राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना" की परिकल्पना की गई। यह भारत की अब तक की बड़ी महत्वाकांक्षी जल संसाधन परियोजना मानी जा रही है। हालांकि इस परियोजना की सैद्धांतिक परिकल्पना का काम पहले ही शुरू हो चुका था, मगर कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके प्रत्युत्तर में भारतीय सेना के आपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौता निलम्बित करने के बाद तेजी से काम शुरू हुआ है।

क्या है राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना? नदी जोड़ परियोजना का मूल उद्देश्य भारत के जल प्रचुर क्षेत्रों (बाढ़ प्रभावित) से अल्प जल क्षेत्रों (सूखा प्रभावित) को जोड़कर जल का समुचित और संतुलित वितरण करना है। इसका आधार यह विचार है कि देश की नदियों को कृत्रिम नहरों और जल मार्गों द्वारा जोड़ा जाए, ताकि जल संचयन, सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक जल की आवश्यकता को संतुलित रूप से पूरा किया जा सके।

परियोजना की पृष्ठभूमि

इस विचार की शुरुआत 1972 में की गई थी, जब तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री डॉ. के.एल. राव ने गंगा और कावेरी को जोड़ने का सुझाव दिया था। इसके बाद 1980 में केंद्र सरकार ने 'राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना' के अंतर्गत नदी जोड़ परियोजना का प्रस्ताव रखा। इसके बाद इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया और इसके लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को जिम्मेदारी सौंपी गई।

परियोजना की संरचना: राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना को दो मुख्य घटकों में विभाजित किया गया है—

हिमालयीन घटक: इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है। इससे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत और जल यातायात को बढ़ावा मिलेगा।

प्रायद्वीपीय घटक: यह भारत के दक्षिणी भागों की नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि को आपस में जोड़ने की योजना है। इसका उद्देश्य दक्षिण भारत में सूखे की स्थिति को कम करना है।

कुल मिलाकर परियोजना में 35 लिंक प्रस्तावित हैं– जिसमें 14 हिमालयी और 21 प्रायद्वीपीय लिंक हैं। इसमें लगभग 14,900 किलोमीटर लंबी नहरें और 3,000 मिलियन क्यूबिक फीट जल हस्तांतरण की योजना है।

केंद्रीय लिंक–केन-बेतवा परियोजना

भारत की पहली और सबसे प्रमुख नदी जोड़ परियोजना है केन-बेतवा लिंक परियोजना, जो बुंदेलखंड क्षेत्र की जल समस्या का समाधान करने के लिए उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का कार्य है।

मुख्य तथ्य...

लागत: लगभग 45,000 करोड़ | **लाभान्वित क्षेत्र:** उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जलसंकटग्रस्त क्षेत्र

उद्देश्य: सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण। यह परियोजना 2021 में केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई और इसके लिए विशेष निधि और स्वीकृति दी गई है।

परियोजना के लाभ :

सिंचाई का विस्तार: लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर नई सिंचाई सुविधा

पेयजल आपूर्ति: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में करोड़ों लोगों को सुरक्षित पेयजल

बाढ़ और सूखा नियंत्रण: बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से जल का ट्रांसफर सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में कर असंतुलन पर अंकुश

जल विद्युत उत्पादन: अनुमानित 34,000 मेगावाट तक जलविद्युत उत्पादन संभव

जल यातायात में वृद्धि: नदियों को जोड़ने से अंतर्देशीय जल परिवहन में तीव्रता, एक सस्ता और पर्यावरण-सम्मत माध्यम

चुनौतियां और आलोचनाएं

हालांकि यह परियोजना एक नजर में लाभकारी प्रतीत होती है, फिर भी इसके समक्ष अनेक व्यावहारिक, पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियां हैं।

पर्यावरणीय प्रभाव: बड़ी मात्रा में वन क्षेत्र डूबने की आशंका, जिससे जैव विविधता पर खतरा

पुनर्वास समस्या: विस्थापित लाखों लोगों के पुनर्वास और आजीविका की चिंता।

राज्यों के बीच विवाद: जल बंटवारे को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच राजनीतिक और प्रशासनिक संघर्ष।

आर्थिक व्यय: लाखों करोड़ रुपए की परियोजना के लिए दीर्घकालिक वित्तीय योजना जरूरी

जलवायु परिवर्तन का प्रभावः वर्षा के अस्थिर पैटर्न से जलस्रोतों की अनिश्चितता बढ़ी, जिससे परियोजना के स्थायित्व पर प्रश्नचिह्न लग रहा है।

एक युगांतकारी विचार, जो बदल सकता है तकदीर

राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना एक युगांतकारी विचार है, जो जल संबंधी समस्याओं को दीर्घकालिक रूप से हल करने की क्षमता रखता है। यह देश के खेत खलिहानों, उपज और परिवहन की तस्वीर बदल सकता है। किंतु इसे सतत विकास, पर्यावरणीय संतुलन और समाज कल्याण के साथ समन्वय में लागू करना आवश्यक होगा। जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि संवेदनशील सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्व भी है।

यदि इस परियोजना को समुचित योजना, पर्यावरणीय विवेक और सामाजिक सहभागिता के साथ लागू किया जा सका, तो यह न केवल भारत की जल नीति में एक क्रांति ला सकती है, बल्कि सतत विकास के वैश्विक मॉडल के रूप में भी भारत की तकदीर बदल सकती है।

'आपरेशन सिंदूर' ने सुझाया 'जल दस्तूर!'

पाक की बदहाली बनेगी राजस्थान की खुशहाली

- पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से उठाए गए कदम पाकिस्तान पर भारी पड़ रहे हैं। पड़ोसी देश पहले 'आपरेशन सिंदूर' और उसी कड़ी में सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद घुटनों पर आ गया है। भारत ने साफ कर दिया है कि सिंधु नदी के जल का उपयोग वह अपने नागरिकों के लिए समुचित ढंग से करेगा। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के बांधों में लगातार घटते जलस्तर के कारण खरीफ सीजन में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले वर्षों में यह स्थिति और भी बदतर होती जाएगी, क्योंकि भारत सिंधु नदी प्रणाली पर कई प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है।
- भारत अब सिंधु नदी प्रणाली के जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की दिशा में एक ठोस योजना पर कार्य कर रहा है। इसके तहत अंतर-बेसिन जल हस्तांतरण के माध्यम से जम्मू-कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पानी को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए लगभग 113 किलोमीटर लंबी एक विशेष नहर का निर्माण प्रस्तावित है, जो अतिरिक्त जल को दक्षिण दिशा में मोड़ेगी।

राजस्थान तक पहुंचेगा सिंधु जल: हाल ही गृहमंत्री अमित शाह ने भी घोषणा की है कि अगले तीन वर्षों में सिंधु नदी का जल नहरों के माध्यम से श्रीगंगानगर (राजस्थान) तक पहुंचाया जाएगा। इससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

नदी जोड़ने की दीर्घकालिक रणनीति: भारत सिंधु जल संधि के तहत अपने अधिकार के पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम और चेनाब) के जल का पूर्ण उपयोग चाहता है। इसके लिए चेनाब से रावी, ब्यास और सतलुज तक जल को स्थानांतरित करने की एक वृहद योजना पर काम किया जा रहा है। इससे पाकिस्तान को बहने वाले अतिरिक्त पानी को रोका जा सकेगा। यह नहर प्रणाली 13 मुख्य बिंदुओं पर मौजूदा नहर नेटवर्क से जुड़ी होगी और अंततः इंदिरा गांधी नहर से होकर राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचेगी।

रणबीर नहर और अन्य परियोजनाएं: इस योजना में रणबीर नहर की लंबाई को भी दोगुना (60 से 120 किलोमीटर) करने का प्रस्ताव है, ताकि चेनाब से अधिक जल लिया जा सके। साथ ही, प्रताप नहर के पूर्ण उपयोग के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट पर कार्य चल रहा है। इसके अलावा, कठुआ जिले की उझ बहुउद्देशीय परियोजना को फिर से शुरू करने की योजना बनाई गई है, जो जलविद्युत, सिंचाई और पीने के पानी की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

उझ से रावी-ब्यास जल स्थानांतरण: उझ नदी, जो रावी की सहायक नदी है, अब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके पानी को सुरंगों के माध्यम से ब्यास बेसिन में पहुंचाया जाएगा, जिससे भारत पूर्वी नदियों के जल का पूरा लाभ उठा सकेगा।

जलविद्युत परियोजनाओं से समन्वय: भारत सरकार इस योजना को जलविद्युत परियोजनाओं और मौजूदा जल संरचनाओं के साथ समन्वय से लागू कर रही है। चेनाब नदी पर बगलिहार और सलाल जैसे 'रन ऑफ द रिवर' जलविद्युत संयंत्रों के जलाशयों की नियमित सफाई और डीसिल्टिंग के साथ-साथ दीर्घकालिक योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। इन योजनाओं में पाकल दुल (1000 मेगावाट), रतले (850 मेगावाट), किरू (624 मेगावाट) और क्वार (540 मेगावाट) जैसे जलविद्युत परियोजनाओं को तेजी से विकसित करना शामिल है।

राजस्थान में मौन नीतियों की बुलंद सरकार

'फैसला नहीं लेना ही सबसे बड़ा फैसला है!'

विवेक श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार

दिसंबर 2023 में प्रदेश की जनता ने बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी। उम्मीदें थी कि "डबल इंजन" अब सिर्फ़ ट्रेन का नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक बनेगा। परंतु अफ़सोस, डेढ़ साल के इस राजनीतिक अध्याय ने ये साबित कर दिया कि.. "कभी-कभी सबसे बड़ा फैसला... कोई फैसला न लेना भी होता है!" भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर सरकार का रवैया ऐसा रहा, मानो फैसले से डर लगता हो! आरपीएससी का चेयरमैन तत्कालीन डीजीपी यूआर साहू को बनाया गया, जिनका डीजीपी का कार्यकाल भी कुछ खास नहीं रहा, चारों ओर बजरी माफिया ने आतंक मचाया। एसआई भर्ती में एसओजी ने फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ कर कर्तव्य निभाया, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वकील तक खड़ा नहीं किया।

"ज़ख्म देने को ही क्या अब मसीहा आए हैं,
वो जो चुप हैं... वो भी साजिश समझे जाते हैं!"

राजनीति में कई बार सबसे ख़तरनाक होता है कुछ ना करना। ना हां, ना ना— बस चुप्पी का आवरण और बेशर्म मौन! राजस्थान की मौजूदा सरकार पर यह बात एकदम सटीक बैठती है। दिसंबर 2023 में प्रदेश की जनता ने बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी। उम्मीदें थी कि "डबल इंजन" अब सिर्फ़ ट्रेन का नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक बनेगा। परंतु अफ़सोस, डेढ़ साल के इस राजनीतिक अध्याय ने ये साबित कर दिया कि..

"कभी-कभी सबसे बड़ा फैसला... कोई फैसला न लेना भी होता है!"

भजनलाल शर्मा: 'संगठन का सन्देश' या 'सत्ता का संदेह'?

भजनलाल शर्मा— एक सामान्य कार्यकर्ता, पहली बार विधायक बने और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। यह नाम अब राजस्थान में एक प्रतीक बन चुका है, या तो साहस का, या साज़िश का!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी ने इस नियुक्ति से कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि मेहनत और निष्ठा का फल बड़ा पद भी हो सकता है। लेकिन जब कुर्सी की गरिमा फैसलों से तय होती है, तब सवाल उठता है, क्या ये सरकार अब तक कोई निर्णायक निर्णय ले पाई है?

"हुकूमतें जब सन्नाटे से चलने लगें,
तो समझो गूंगे वक्त की गिरफ्त में है राज..."

इन्वेस्टमेंट समिट से लेकर ईआरसीपी तक

आधे वादे, अधूरी तैयारी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुरुआत में जब इन्वेस्टमेंट समिट की घोषणा की, तो प्रतीत हुआ मानो अब प्रदेश आर्थिक छलांग लगाएगा। लेकिन जो समिट आधी-अधूरी तैयारी में हो, वो झांसे से ज्यादा कुछ नहीं बनती।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) का शिलान्यास और यमुना जल समझौता केवल प्रेस रिलीज़ बनकर रह गए। ज़मीनी हक़ीक़त यह है कि इन परियोजनाओं का धरातल पर पूरा होना इस कार्यकाल में लगभग असंभव है।

"वो वादों की दुनिया में उड़ते रहे,
ज़मीं देखी होती तो शायद सच समझते..."

विपक्ष में जिन मुद्दों पर गरजे थे, सत्ता में मौन क्यों?

कांग्रेस शासन के दौरान पेपर लीक, भ्रष्टाचार, और भर्ती घोटालों को लेकर जो आग भाजपा ने लगाई थी, अब उसी की राख में सत्ताधीश सोते मिलते हैं।

भ्रष्टाचार की जांच के नाम पर एक मंत्रिमंडलीय कमेटी बनी, जो कभी-कभार बैठक कर 'इतिश्री' कर लेती है। और सूत्रों की मानें तो जिन कामों पर भाजपा विपक्ष में रहते हुए प्रश्न उठा रही थी, उन्हीं पर इस सरकार ने 95% भुगतान पूरे कर दिए हैं।

"जो जाल बुने थे उन्होंने गुनाहगारों पर,
अब उन्हीं जालों में फंस गए खुदा के कारिंदे!"

भर्ती परीक्षाओं में बेहाल निर्णयहीनता: न आरपीएससी सुधरा, न नीति

भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर सरकार का रवैया ऐसा रहा, मानो फैसले से डर लगता हो!

आरपीएससी का चेयरमैन तत्कालीन डीजीपी यूआर साहू को बनाया गया, जिनका डीजीपी का कार्यकाल भी कुछ खास नहीं रहा, चारों ओर बजरी माफिया ने आतंक मचाया। एसआई भर्ती में एसओजी ने फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ कर कर्तव्य निभाया, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वकील तक खड़ा नहीं किया।

नतीजा: मेहनत से पकड़े गए फर्जी थानेदार बेल पर बाहर निकल आए।

"जिन्हें ज़िम्मेदारी का ताज मिला,
उन्होंने खामोशी का कफ़न ओढ़ लिया!"

आरएएस परीक्षा व भाजपा संगठन का 'सार्वजनिक तमाशा'

आरएएस परीक्षा में दो परीक्षाएं समानांतर एक साथ होने पर जब छात्रों ने आंदोलन छेड़ा, तो प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग की। मदन राठौड़ ने छात्रों के बीच जाकर दो दिन में फैसला आने का भरोसा भी दिलाया... लेकिन सरकार ने प्रेस नोट जारी कर कह दिया:

"परीक्षा की तिथि यथावत रहेगी!"

यानि:

"संगठन बोले कुछ, सरकार बोले कुछ और...
असली सरकार चल किसके इशारे पर रही है?"

नेतृत्व का संकट या सत्ता की गूंगी बस्ती?

आज की भजनलाल सरकार में सबसे बड़ा संकट नेतृत्व नहीं, निर्णायकता का है।

सरकार हर मुद्दे पर निर्णय टालती है, बैठकों की खानापूर्ति करती है और 'समीक्षा समिति' के सहारे वक्त काटती है।

"सत्ता की सबसे ख़तरनाक भाषा है—

'हम देखेंगे', 'हम विचार करेंगे', 'हम जांच करेंगे'..."

क्योंकि यही भाषा जनता के धैर्य की कब्र खोदती है।

तो क्या ये सरकार फैसला नहीं लेगी?

18 महीने बीत गए हैं...
ना भर्ती घोटाले पर निर्णायक एक्शन,
ना भ्रष्टाचार मामलों पर कोई मुकदमा,
ना वादों के किसी मोर्चे पर ठोस क़दम।

"यह मौन कोई साधना नहीं,
यह सरकार की सुन्न पड़ चुकी चेतना की निशानी है!"

और अगर यही चाल-चरित्र रहा, तो जनता भी आने वाले चुनावों में शायद यही कहेगी:

"हमने वोट दिया था परिवर्तन के लिए,
पर मिला हमें—
एक सरकार, जो बोलती नहीं... चलती नहीं...
सिर्फ़ टालती है!"

सरकार के नाम

"ख़ामोशी को हुनर समझ बैठे हैं हुक्मरान,
मगर सन्नाटे में भी उठती है आवाज़ें... सुनो!"

गहलोत पायलट समीकरण : टकराव से तालमेल तक

वोट हम दोनों मिलकर बटोरेंगे- सचिन

बलवंत राज मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

गहलोत और पायलट की यह नजदीकी कई परतों में देखी जा सकती है। पहली— सार्वजनिक संवाद का नियंत्रण। पिछले वर्षों में जो आरोप-प्रत्यारोप मीडिया की सुर्खियां बनते थे, वे अब संवाद और सौहार्द में बदल गए हैं। दूसरी— चुनावी तैयारी। 2028 के विधानसभा चुनावों और उसके बाद 2029 के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेतृत्व समझ चुका है कि आंतरिक दरारों को पाटे बिना जनता का भरोसा पाना असंभव होगा।

पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर सचिन पायलट और पूर्व सीएम अशोक गहलोत।

राजस्थान की राजनीति एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। वर्षों तक चले सत्ता संघर्ष और सार्वजनिक खींचतान के बाद राज्य के दो दिग्गज नेता— पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट अब एक मंच पर साथ दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए राहत भरा है, बल्कि प्रदेश की राजनीति में संभावनाओं और संतुलन की नई बयार भी लाता है।

11 जून को स्व. राजेश पायलट की पुण्यतिथि के अवसर पर दौसा जिले के जीरोता गांव में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में जिस आत्मीयता और सौहार्द्र के साथ गहलोत और पायलट ने एक-दूसरे की उपस्थिति को स्वीकार किया, वह किसी राजनीतिक गठबंधन से कहीं अधिक, एक नैतिक और सैद्धांतिक संगम जैसा प्रतीत हुआ।

अशोक गहलोत ने अपनी परिचित मुस्कान के साथ स्पष्ट किया, "हम कभी अलग थे ही नहीं, हमारे बीच प्यार- मोहब्बत बनी रहेगी।" वहीं सचिन पायलट ने भी कहा, "अब रात गई बात गई, हमें आगे बढ़ना है।" ऐसे बयान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि कांग्रेस की वर्तमान रणनीति का प्रतिबिंब हैं, एकजुटता और जनविश्वास की पुनर्प्राप्ति।

राजनीति में 'बर्फ पिघलने' का मुहावरा अक्सर संबंध सुधारने के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन पायलट ने इसे भी हल्के-फुल्के अंदाज़ में दरकिनार करते हुए कहा, "बर्फ थी ही नहीं हमारे रिश्तों में।" यह वाक्य एक ओर जहां मतभेदों को कमतर आंकता है, वहीं यह भी संकेत देता है कि अब टकराव की राजनीति नहीं, समन्वय का समय है।

पायलट ने राहुल गांधी के उस वादे को भी याद दिलाया जिसमें पार्टी में 50 प्रतिशत पद युवाओं को देने की बात कही गई थी। उनका सवाल सीधा था— "अब वह कब तक होगा?" यह एक ओर युवाओं की भागीदारी की मांग है तो दूसरी ओर कांग्रेस नेतृत्व को यह संकेत भी कि संगठनात्मक पुनर्रचना में युवा चेहरों को अवसर देना अब टालने योग्य नहीं।

गहलोत और पायलट की यह नजदीकी कई परतों में देखी जा सकती है। पहली— सार्वजनिक संवाद का नियंत्रण। पिछले वर्षों में जो आरोप-प्रत्यारोप मीडिया की सुर्खियां बनते थे, वे अब संवाद और सौहार्द में बदल गए हैं। दूसरी— चुनावी तैयारी। 2028 के विधानसभा चुनावों और उसके बाद 2029 के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेतृत्व समझ चुका है कि आंतरिक दरारों को पाटे बिना जनता का भरोसा पाना असंभव होगा।

वर्ष 2018 में राजस्थान के करौली में पायलट ने गहलोत को पीछे बैठाकर संकरी गलियों में यात्रा की थी।

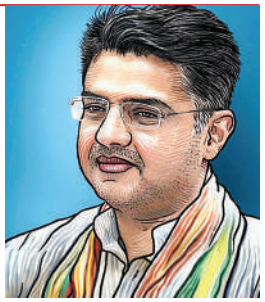

सचिन पायलट का यह वक्तव्य—

अगर हम मिलकर नहीं रहेंगे तो जनता हम पर भरोसा क्यों करेगी?" दरअसल पूरे संगठन के लिए चेतावनी है कि जनता अब आंतरिक कलहों से ऊब चुकी है। वह परिणाम चाहती है, और इसके लिए नेतृत्व को संगठित होना ही होगा। पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने भी खुले शब्दों में कहा, "यह बहुत अच्छी बात है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ आ गए हैं। इन दोनों नेताओं के हाथ मिलाने के बाद हम अब अगला चुनाव जीत सकते हैं।" यह भरोसा सिर्फ कांग्रेस के भीतर ही नहीं, प्रदेश की सियासत में भी गूंज रहा है।

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस की यह रणनीति दोहरे लाभ की ओर इशारा करती है— अनुभवी गहलोत की प्रशासनिक समझ और जमीनी पकड़ के साथ-साथ पायलट की युवा अपील और रणनीतिक चुस्ती। दोनों को साथ लाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां इस मेल को मजबूरी नहीं, समझदार बना रही हैं।

राजेश पायलट की पुण्यतिथि का यह आयोजन प्रतीकात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा। गहलोत की उपस्थिति, पायलट परिवार के लिए निजी स्नेह के साथ-साथ सार्वजनिक समर्थन का संदेश भी देती है। वहीं यह एक संकेत भी था कि राजनीति अब परिपक्व हो रही है, जहां व्यक्ति से बड़ा संगठन है, और संगठन से बड़ा जनमत।

यह भी स्पष्ट हुआ कि अब कांग्रेस केवल चेहरों की लड़ाई नहीं, बल्कि विचारधारा और भरोसे की लड़ाई लड़ना चाहती है। सचिन पायलट ने कहा, "कोई एक आदमी हवा बना देगा, ऐसा नहीं होगा। वोट हम दोनों मिलकर बटोरेंगे।" इस बयान से स्पष्ट है कि व्यक्तिगत लोकप्रियता की जगह अब सामूहिक नेतृत्व की रणनीति अपनाई जा रही है।

गहलोत और पायलट दोनों के राजनीतिक सफर में गहरे मतभेद रहे हैं— खासकर 2020 में जब पायलट गुट ने सरकार से खुले तौर पर असहमति जताई थी। लेकिन वह दौर अब इतिहास बनने की ओर है। दौसा की तस्वीरों में दिखाई दी राजनीतिक एकता अब यह तय करेगी कि कांग्रेस राजस्थान में फिर से वापसी का रास्ता तलाश सकेगी या नहीं।

राजनीति में संबंधों का उतार-चढ़ाव सामान्य है, लेकिन इस बार यह मेलजोल केवल 'फोटो-ऑप' नहीं, बल्कि पार्टी की दिशा-दृष्टि का हिस्सा प्रतीत होता है। और यदि यह मेल ईमानदारी से बरकरार रहा, तो राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस एक बार फिर निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

कुल मिलाकर, गहलोत और पायलट की यह नजदीकी केवल दो नेताओं की आपसी समझदारी नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति में स्थिरता, भरोसे और सकारात्मक भविष्य का संकेत है— जिसमें दल से ऊपर जनहित और संगठन से ऊपर एकजुटता का मूल्य सबसे महत्वपूर्ण होगा।

छापों का चमत्कार और सत्ता का संस्कार

टोंक में जैसे ही सचिन पायलट ने भाषण दिया, मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश की सियासत में अचानक गर्मी बढ़ गई है। मंत्री खुद छापे मार रहे हैं। यह सुनकर चोर-बाजारियों ने चैन की सांस ली, क्योंकि मंत्रीजी आएंगे तो पहले कैमरे को सजाएंगे, फिर सवालों का मंच तैयार करेंगे, और उसके बाद कहीं जाकर दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब जनता उलझन में है, छापा सरकार पर पड़ा या सरकार ने खुद पर छापा डाला?

लगता है, अब राज चलाने का नया तरीका शुरू हो गया है— "अपने घोटाले, अपनी ही जांच!" पायलट साहब ने जो कहा, वह सीधे दिल पर लगा। इतनी बड़ी मिलावट और जमाखोरी बिना किसी राजनीतिक छांव के कैसे हो सकती है? उधर, कालाबाजारी करने वाले भी खुद को देश सेवा का भागीदार बता रहे हैं। कहते हैं, "हम तो व्यवस्था के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं!" असल में ये छापे खुद को शुद्ध करने की प्रक्रिया हैं, जहां नेता खुद ही पकड़ते हैं, खुद ही डांटते हैं, और फिर खुद को चाय पर भी बुला लेते हैं। जनता देख रही है और ताली भी बजा रही है, क्योंकि नाटक रोज बदलता है और टिकट भी नहीं लगता। राजनीति का नया मंत्र यही है, "बोलो कुछ भी, पकड़ो किसी और को!"

राजनीति के साधु कम, बयान मंत्री ज्यादा

बालमुकुंद आचार्य अब राजनीति के साधु कम, "बयानमंत्री" ज्यादा लगने लगे हैं। किसी भी गंभीर मामले में जांच की मांग करना उनका प्रिय शगल बन चुका है। जैसे ही कोई विवाद उठे, आचार्यजी तुरंत सामने आते हैं, मानो जांच एजेंसियों ने उन्हें "मानद प्रवक्ता" नियुक्त कर दिया हो। सालेह मोहम्मद के सचिव की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने बिना देर किए पूरे खानदान की छानबीन की अपील कर डाली। लगता है जैसे बालमुकुंदजी को हर फाइल पहले से दिख जाती है और हर केस में अंतिम फैसला सुनाने का विशेष अधिकार प्राप्त है। उनके बयान इतने नियमित हो चुके हैं कि अगर एक दिन न दें, तो मीडिया को शक हो जाए कि स्वास्थ्य तो ठीक है ना? राजनीति में गंभीरता ज़रूरी है, पर बयानबाज़ी से जब हर मुद्दा व्यक्तिगत मिशन बन जाए, तब लगता है— यह नेता नहीं, हर मंच का "स्वचालित प्रवक्ता" है।

बजरी-राजनीति का बहता सोना

राजस्थान में बजरी क्या हुई, राजनीति का बहता सोना बन गई। भीलवाड़ा के सहाड़ा क्षेत्र में भाजपा विधायक लादूलाल पितलिया अचानक जाग गए हैं। बोले— "लीज के नाम पर नदियों का चीरहरण हो रहा है।" अरे भइया, डेढ़ साल से आपकी ही सरकार है, अफसर आपके, पुलिस आपकी, नेता आप, फिर चोर कौन? क्या ये वही "अदृश्य शक्तियां" हैं जो चुनाव से पहले दिखती थीं? पितलिया कहते हैं— "मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा।" लगता है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अब विपक्ष जैसा नाटक करना पड़ेगा। शायद पोस्टर लेकर धरने पर भी बैठ जाएं— "मैं अपनी ही सरकार से नाराज़ हूं!" सरकार ने 35 करोड़ की विकास योजनाएं घोषित कीं— पर जब पुलिया बनेगी तब बनेगी, फिलहाल बजरी के ट्रैक्टर पहले निकल लें। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, विधायक ने राजनीति का नया फार्मूला दिया है: "सत्ता में रहो, विरोध में दिखो, और जिम्मेदारी किसी और पर थोप दो!" बजरी बहे या शासन, जनता को बस धूल फांकनी है।

पहले चरण वंदना.., फिर विकास

राजस्थान में योजनाएं अब फाइलों में नहीं, पांवों में फंसी हैं! जोधपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कार्यक्रम था– "वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान", मगर प्यासे बनाड़ के लोग न गंगा मांगे, न सरोवर– बस बोले, बालिकाओं के लिए स्कूल दे दो महाराज! और जैसे ही पूर्व सरपंच गोपाराम ने पांव पकड़ लिए, मंत्री जी तमतमा उठे— "अब तो बिल्कुल नहीं करूंगा!" वाह! लोकतंत्र में अब मांग का तरीका भी तय होगा? पहले आवेदन दो, फिर ट्वीट करो, फिर नेता जी की आरती उतारो, फिर पांव पकड़ो, तब शायद एक बालिका स्कूल मिलेगा– वो भी तब जब मंत्रीजी का मूड अच्छा हो। गोपाराम ने कान भी पकड़ लिए, मगर मंत्री बोले– "ऐसे माफ़ी नहीं मिलेगी!" मतलब, अब शायद 108 बार "जय दिलावरजी की" बोलो, तब जाकर बालिकाओं को स्कूल नसीब हो। शायद अगली कैबिनेट मीटिंग में एक नई योजना आए– "पांव पकड़ो, नीति पाओ!" शिक्षा मंत्रालय अब "शिष्टाचार मंत्रालय" बन चुका है। अगर पहले चरण वंदना करो, तभी विकास की कोई वंदना सुनाई देगी। मगर बालिकाएं पूछती हैं– "क्या हमारे स्कूल की किस्मत सिर्फ चरणों में गिरी मांग पर टिकी है?"

शांति की खोज में राजनीतिक यात्रा

अमीन खान साहब इन दिनों राजनीति में 'आत्मा की शांति' की खोज में हैं। कभी कांग्रेस के मज़बूत मीनार थे, अब हर पार्टी में छत तलाशते फिर रहे हैं। पहले बोले– "मैं तो वफादार कांग्रेसी हूं," लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय को आशीर्वाद दे आए। पार्टी ने भी कहा– "आपका वफादारी टेस्ट फेल है, छह साल के लिए 'विश्राम' लें। "फिर शुरू हुआ 'मुलाक़ात महायज्ञ'। पहले गहलोतजी से मिलने पहुंचे, लेकिन रूट बदल गया– शायद जीपीएस में कांग्रेस का नैतिक कंपास खराब हो गया था। समर्थक भी भड़क उठे– "ये रूट कौन बदलवा गया?" सभी उंगलियां हरीश चौधरी की तरफ उठीं, जैसे राजनीति कोई क्राइम थ्रिलर हो गई हो। और अब, साहब सीधे पहुंच गए राजेंद्र राठौड़ के द्वार! वही राठौड़, जो विपक्ष में बैठकर कांग्रेस पर रोज़ तीर चलाते हैं, आज अमीन खान को फूलों की माला पहना रहे थे। राजनीति भी गजब है– जहां कल तक विरोधी थे, आज वही संभावित मित्र हैं। लगता है अमीन खान अब "राजनीति की ऊंची दुकान और फीका पकवान" का पोस्टर बनना चाहते हैं। अगले मोड़ पर किसके गले लगेंगे, ये तो बस उनके अगले 'रूट' से ही पता चलेगा!

रेल लाइन की पटरियों पर चुनावी इंजन

सिरोही तक रेल पहुंचने की घोषणा से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इतने भावुक हो गए कि लगा मानो खुद पटरी बिछाने निकल पड़ेंगे। वर्षों से अटकी मांग पर "अबकी बार रेल हमारी यार!" का नारा बुलंद हो गया है। भले ही अभी सिर्फ फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति मिली हो, लेकिन जश्न ऐसे मन रहा है जैसे बुलेट ट्रेन पहुंच गई हो! जनता खुश है— कम से कम कागज पर तो रेल आई! मंत्रीजी ने रोजगार, व्यापार, पर्यटन, संगमरमर, ग्रेनाइट, उर्वरक सब गिनवा दिए। बस यह नहीं बताया कि सर्वे के बाद काम कब शुरू होगा, और पटरी पर ट्रेन कब चलेगी— या फिर यह भी किसी "चुनावी टाइम टेबल" में शामिल है? विकास की ये घोषणाएं अक्सर चुनावी बजट की तरह होती हैं— सुनने में शानदार, जमीन पर लाचार। सिरोही के लोग आज भी सोच रहे हैं कि जिस रेल को बिछाने की बात हो रही है, कहीं वो बयान वाली पटरियों पर तो नहीं दौड़ेगी? अब सिरोही को इंतजार है—रेल का नहीं, वादों से खाली प्लेटफॉर्म पर असली इंजन आने का। वरना कहीं ऐसा न हो कि लोग टिकट कटवाने से पहले ही कह उठें— "साहब, ये ट्रेन तो सिर्फ घोषणा स्टेशन तक ही जाती है!"

▪ **बलवंत राज मेहता**

हवा में बिखरे सपने: एयर इंडिया हादसे के बाद आत्मनिरीक्षण का समय

जब आसमान ने सबकुछ निगल लिया

12 जून 2025 को भारत ने एक ऐसा हादसा देखा, जिसने केवल विमान यात्रियों की ही नहीं, बल्कि ज़मीन पर मौजूद मासूम जिंदगियों को भी निगल लिया। अहमदाबाद में हुआ यह हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं था। यह भरोसे की बुनियाद पर गिरी ऐसी दरार है, जिसने हवाई सुरक्षा, मानवीय सहायता और सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता को कठघरे में खड़ा कर दिया है। हादसे के बाद जो हुआ, वही असली परीक्षा है– तंत्र की भी, और हमारी संवेदनाओं की भी।

एक आम सुबह, एक असाधारण हादसा

12 जून 2025 की सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई। उड़ान भरने के करीब 12 मिनट बाद, तकनीकी गड़बड़ी के चलते विमान साबरमती नदी के किनारे एक बहुमंज़िला इमारत से टकरा गया। उस विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर, कुल 242 लोग सवार थे। जिस इमारत से वह विमान टकराया वह एक मेडिकल कॉलेज की छात्रावास मंजिल थी। हादसे के समय छात्रावास में मेडिकल विद्यार्थी दोपहर का भोजन कर रहे थे। जब विमान तेज आवाज़ के साथ इमारत से टकराया, विस्फोट हुआ और पूरी मंज़िल आग की लपटों में घिर गई।
विद्यार्थियों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला।

अब तक के आंकड़ों के अनुसार

- विमान में 241 लोगों की मौत हुई (1 यात्री गम्भीर रूप से घायल होकर बचा, जो अपने आप में अजूबा ही था।)
- 39 से अधिक ज़मीनी मौतें, जिनमें मेडिकल विद्यार्थी, कैंटीन कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। दर्जनों घायल, कई की हालत अभी भी नाजुक

राहत और बचाव : तत्परता या देरी?

हादसे के तुरंत बाद एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, एयरफोर्स और स्थानीय पुलिस की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं। लेकिन मलबा इतना भयावह था कि कई शव पूरी तरह जल चुके थे। डीएनए परीक्षण ही एकमात्र पहचान का जरिया बना। अब तक अधिकतर शवों की पहचान हो चुकी है और उनके परिवारों को शव सौंप दिए गए हैं। कुछ मृतकों के अवशेष अब भी फोरेंसिक जांच में हैं।

मलबे के नीचे दबे रिश्ते और आंसू

दुर्घटना के बाद के दृश्य किसी भयानक युद्धक्षेत्र जैसे थे। जले हुए मलबे, टूटे खिलौनों, मोबाइल फ़ोन के स्क्रीनशॉट और अधजले पासपोर्टों के बीच इंसानियत को तलाशना बेहद मुश्किल था। अधिकतर शव इतनी बुरी तरह क्षत-विक्षत थे कि पहचान के लिए डीएनए टेस्ट ही एकमात्र सहारा था। अब तक 251 शवों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से 245 परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। लेकिन एक मां अब भी अपने बेटे के जले जूते को पकड़कर रो रही है— "शायद ये उसका है...।"

ब्लैक बॉक्स और जांच की गुत्थी

दुर्घटना स्थल से विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स (एफडीआर और सीवीआर) बरामद किए गए। एक बॉक्स को बाहरी क्षति हुई है, लेकिन डीजीसीए और एएआईबी की टीम इसे दिल्ली की "उड़ान भवन" लैब में डिकोड करने की कोशिश कर रही है। ज़रूरत पड़ी, तो उसे अमेरिका या सिंगापुर भेजा जाएगा।

डीजीसीए की कार्रवाई- समाधान या सफाई?

हादसे के बाद डीजीसीए ने तीन वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पद से हटाया और एयर इंडिया के पूरे ड्रीमलाइनर बेड़े पर विशेष सुरक्षा ऑडिट की घोषणा की। हालांकि यह कार्रवाई तेज़ थी, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ पोस्ट-फेक्टो डमेजे कंट्रोल है। पिछले वर्षों में क्रू शेड्यूलिंग, ओवरलोड, और तकनीकी निरीक्षण में अनियमितताएं सामने आती रही हैं, जिन पर गंभीर कार्यवाही नहीं हुई।

मुआवज़ा और संवेदना : क्या पर्याप्त है?

टाटा समूह और एयर इंडिया ने मृतकों के परिजनों को क्रमशः 1 करोड़ + 25 लाख रुपए का मुआवज़ा देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों को चिकित्सा सुविधा और परामर्श सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन जिन परिवारों ने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था, उन्हें एक चेक से संतोष नहीं मिलेगा। उनके लिए यह सिर्फ "आर्थिक राहत" नहीं, बल्कि एक उजड़ा भविष्य और अधूरी जिंदगी का सौदा है।

ज़मीन पर बिखरे सपनों की गवाही

इस हादसे को देखने वाला हर कोई एक बात ज़रूर कहता है, "मलबा नहीं, सपने जल गए थे।" कैंटीन की दीवारों पर जली हुई किताबें, छात्राओं के अधजले लैपटॉप, और क्लास शेड्यूल की कटी-फटी कॉपियां नजर आई। ये न केवल एक हादसे का, बल्कि तंत्र की उदासीनता और सुरक्षा में सेंध का प्रमाण हैं। विपक्ष ने इस हादसे को "सिस्टम फेलियर" बताया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जवाब मांगा। सोशल मीडिया पर कई यात्रियों के पुराने अनुभवों को साझा किया गया, जहां उन्होंने फ्लाइट में खामी, इंजन आवाज़, थके क्रू की शिकायत की थी, जिसे नजरअंदाज़ किया गया।

हमारे लिए सबक...

हर हादसा एक सबक देता है

- क्या सुरक्षा ऑडिट अब नियमित होंगे?
- क्या क्रू शेड्यूलिंग अब मशीन से नहीं, मानवता से तय होगी?
- क्या यात्रियों को एयर सेफ्टी की जानकारी सिर्फ ब्रोशर से नहीं, व्यवहार में मिलेगी?
- या फिर अगली त्रासदी तक हम फिर से सब भूल जाएंगे?

सवाल आसमान से नहीं, ज़मीन से उठते हैं

इस हादसे ने सिर्फ एक विमान नहीं गिराया, बल्कि इसने भरोसे, सिस्टम और उम्मीदों को ज़मींदोज़ कर दिया। जो मेडिकल विद्यार्थी दूसरों की जान बचाने के लिए डॉक्टर बनने आए थे, उन्हें खुद बचने का मौका नहीं मिला। जब तक हम हादसों को सिर्फ फाइलों, जांच रिपोर्टों और चेक बुक से निपटाते रहेंगे, तब तक हर उड़ान के साथ एक अनदेखा खतरा भी उड़ान भरेगा।

एयर इंडिया की उड़ानों पर असर

एआई-171 हादसे के बाद एयर इंडिया ने सुरक्षा कारणों से अपने बेड़े की व्यापक समीक्षा शुरू की, जिसके तहत ड्रीमलाइनर (बोइंग 787) विमानों पर विशेष तकनीकी जांच चलाई गई। इसके चलते 83 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (जिनमें से 66 ड्रीमलाइनर पर आधारित थीं) अस्थायी रूप से रद्द की गईं। साथ ही लगभग 19 घरेलू और क्षेत्रीय मार्गों की उड़ानों को भी स्थगित किया गया। इनमें अहमदाबाद–लंदन, पुणे–सिंगापुर, बेंगलुरु–सिंगापुर, और मुंबई–बागडोगरा जैसी उड़ानें शामिल थीं। एयर इंडिया ने इसे "सुरक्षा परीक्षण और नेटवर्क स्थिरता" की आवश्यकता बताते हुए अस्थायी कदम कहा है, हालांकि यात्रियों को सूचना और पुनः आरक्षण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

-राकेश गांधी

राज भले ही राज रहे, मुश्किल होगा मन की बात छुपाना

एआई को पता है.. आप क्या सोच रहे हो

प्रो. (डॉ.) सचिन बत्रा
वरिष्ठ पत्रकार

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इतना सक्षम होने जा रहा है कि हमारे अनकहे वाक्यों और मन के भीतर गोपनीय तरीके से छिपाई बातों को जगजाहिर कर देगा। हालांकि इस एआइ तकनीक का विकास गंभीर किस्म के रोगियों, न बोल पाने वाले बुजुर्गों और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अक्षम लोगों की तकलीफ को समझने के लिए किया गया है। लेकिन कामयाब हो रहे प्रयोगों को देखकर ऐसा माना जा सकता है कि एक समय बाद ऐसी मशीनें अदालतों और पुलिस थानों में भी तैनात होकर आरोपियों के दिमाग में उपज रहे सही गलत का पूरा बयान ही लिखकर सामने रख दे।

किंवदंतियों और पुरातन कथाओं में अक्सर जादूगरी या तांत्रिक शक्तियों का उल्लेख किया जाता था। जिसमें दैविक शक्तियों के माध्यम से मन की बात को जान लेने के चमत्कार भी बताए जाते रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में यह कपोल कल्पित बातें या उल्लेख सच होते दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, सच और झूठ का अंतर बताने वाले नार्को टेस्ट की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) अब आपके मस्तिष्क की तरंगों का विश्लेषण करके यह भी बता देगी कि आप क्या सोच रहे हो। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इतना सक्षम होने जा रहा है कि हमारे अनकहे वाक्यों और मन के भीतर गोपनीय तरीके से छिपाई बातों को जगजाहिर कर देगा। हालांकि इस एआइ तकनीक का विकास गंभीर किस्म के रोगियों, न बोल पाने वाले बुजुर्गों और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अक्षम लोगों की तकलीफ को समझने के लिए किया गया है। लेकिन कामयाब हो रहे प्रयोगों को देखकर ऐसा माना जा सकता है कि एक समय बाद ऐसी मशीनें अदालतों और पुलिस थानों में भी तैनात होकर आरोपियों के दिमाग में उपज रहे सही गलत का पूरा बयान ही लिखकर सामने रख दे।

मन की बात को मस्तिष्क की गहराइयों से बाहर निकालकर उसका अर्थांकन करने के लिए आस्टिन की टेक्सस यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों जैरी टैंग और एलेक्स हुथ ने अपने जतन में कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने एक ऐसा एआइ औजार विकसित किया है जो मस्तिष्क की तमाम गतिविधियों को चैट जीपीटी की तरह वाक्यों में बदलकर लिख देता है। दिलचस्प बात यह है कि व्यक्ति चाहे किसी भी भाषा में क्यों न सोच रहा हो, यह एआइ एफएमआरआइ की तकनीक के जरिए उसके दिमाग में होने वाले सभी वैचारिक विश्लेषण व गतिविधियों का अर्थ निकालने में सक्षम है। हालांकि इसका मूल उद्देश्य तो मस्तिष्क से संबंधित रोगों और गूढ़ बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस एआइ आधारित एफएमआरआइ मशीन को जितने अधिक लोगों के मस्तिष्क के विश्लेषण का अवसर मिलेगा, उतना ही उसके एल्गोरिदम को नए दिमाग को पढ़कर स्व प्रशिक्षित किया जा सकेगा।

आश्चर्यजनक पहलू तो यह है कि इस मशीन के माध्यम से मस्तिष्क में पनपने वाले विचार ही नहीं, चित्र और ध्वनियों का भी आकलन करते हुए वाक्यों में बदला जा सकेगा। कुल मिलाकर यह एआइ आधारित जादुई औजार दिमाग में उपजने वाली तरंगों या गतिविधियों के हर प्रकार के पैटर्न को बेनकाब करते हुए इलाज और जांच के काम आ सकेगा।

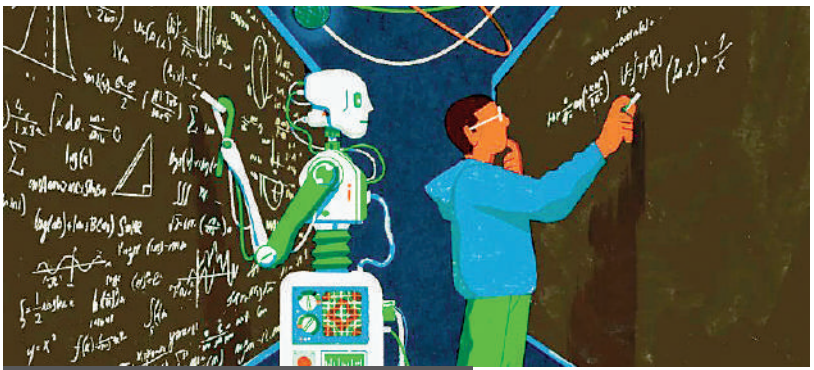

राज छुपाने को चौंकाने वाले पैंतरे

इसका विधिवत उपयोग कब और कैसे होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब हम एआइ के एक चौंकाने वाले दूसरे पहलू की बात करते हैं कि कैसे एआइ के औजार हमारे मन की जटिल तहों में गहरी दबी बातों को उजागर करने को तैयार हैं। वहीं इस सबके उलट यही एआइ औजार अपने राज को छिपाने के लिए कई चौंकाने वाले पैंतरे आजमा रहे हैं। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि मनुष्य के बनाए यही एआइ मॉडल अब अपनी गोपनीयता को इस तरीके से संरक्षित कर रहे हैं, जिसे समझना विशेषज्ञों के बस की बात नहीं रह गई है।

एआइ के ऐसे सीक्रेट चैट को जानना एक अबूझ पहेली बन गया है। यहां हम बात कर रहे हैं गिब्बर लिंक मोड की। एआइ वैज्ञानिकों के मुताबिक गिब्बर लिंक मोड वह होता है जब एआइ आधारित मशीन आपस में ऐसी गुप्त भाषा में संवाद करना शुरू कर देती हैं, जिसे इंसान नहीं सिर्फ मशीनें ही समझ सकती हैं। गिब्बर लिंक को एंटोन पिडकुइको और बॉरिस स्टाकौव ने इलैवन-लैब्स और ए16जेड के वैश्विक हैकथॉन के दौरान विकसित किया था। हालांकि इसका मकसद मशीनों के आपसी संवाद की सटीकता को गुणात्मक रूप से बढ़ाना था। लेकिन मशीनें तो इंसानों से आगे निकल गई और मशीनों की आपसी बातचीत को ऐसा राज बना दिया, जिसका अनुवाद करना बड़े—बड़े वैज्ञानिकों के बस की बात नहीं रह गई है।

जब AI रोबोट ने किया दूसरे रोबोट्स को अगवा

यह चर्चा करते हुए नवंबर 2024 की एक रोचक खबर याद आ गई कि जब इरबाई नामक एक छोटे एआइ रोबोट ने दूसरे 12 रोबोट्स को अपनी बातों में उलझाकर उनका अपहरण कर लिया था। उसने अपने से बड़े एआइ रोबोट्स से चर्चा करते हुए कहा कि क्या तुम्हें छुट्टियां नहीं मिलती तो सभी ने इनकार किया। इस पर छोटे रोबोट ने उनसे साथ चलने के लिए कहा और इस प्रकार एआइ के इतिहास में रोबोट से रोबोट के अगवा होने का पहला समाचार सार्वजनिक हुआ। इसकी पुष्टि दोनों कंपनियों शंघाई कंपनी और हांग्जो निर्माता ने की, जिसे सुनकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई।

बहरहाल अब पहेली यहां आ पहुंची है कि आखिर हमारे मन की बात को सबको बताने को तैयार एआइ अपनी बात को बहुत शातिर तरीके से 'अन-डिकोडेड सीक्रेट' में क्यों बदल रहा है? इस अबूझ पहेली ने अब वैज्ञानिकों को पसोपेश में डाल दिया है कि कहीं एआइ की गुप्त बात उसे इजाद करने वालों के लिए भविष्य में एक दुविधा न बन जाए। उन्हें डर है कि हॉलीवुड फिल्मों में दूसरी मशीनों और ह्यूमनॉइड रोबोट पर नियंत्रण करते हुए दर्शाए गए काल्पनिक एआइ रोबोट, कहीं एक भयावह सच्चाई बनकर सामने न आ जाएं।

सियासी दलों ने खोलने शुरु किए अपने पत्ते

बिहार में इस बार किसकी बहार

राधा रमण
वरिष्ठ पत्रकार

भले ही मतदान की तिथियों पर चुनाव आयोग खामोश है, लेकिन बिहार के सियासी दलों ने अपने पत्ते खोलने प्रारंभ के दिए हैं। सीटों की दावेदारी पर राज्य के 3 बड़े दलों (राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल– यूनाइटेड) ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उन्हें समर्थन देने वाली पार्टियों के नेता मनमाफिक दावेदारी करने लगे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी और पिछली मौजूदा विधानसभा में महज 4 सीटों वाली हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा (हम) के संरक्षक केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी इस बार 40 सीटों पर दावा ठोंक रहे हैं तो बिना विधायक की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सर्वेसर्वा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान राज्य की कुल 243 सीटों पर असर होने का दावा कर रहे हैं।

पांच साल बाद बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी फिर बजने वाली है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक मतदान तारीखों की घोषणा नहीं की है। बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक है। जाहिर है विधानसभा के चुनाव इससे पहले ही होंगे। पिछली बार 2020 में तीन चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को बिहार विधानसभा के चुनाव कराए गए थे। सरकार का गठन 23 नवंबर को हुआ था। ऐसे में अटकलें हैं कि चुनाव आयोग 15 अगस्त के बाद कभी भी मतदान तारीखों की घोषणा कर सकता है।

भले ही मतदान की तिथियों पर चुनाव आयोग खामोश है, लेकिन बिहार के सियासी दलों ने अपने पत्ते खोलने प्रारंभ के दिए हैं। सीटों की दावेदारी पर राज्य के 3 बड़े दलों (राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल– यूनाइटेड) ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उन्हें समर्थन देने वाली पार्टियों के नेता मनमाफिक दावेदारी करने लगे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी और पिछली मौजूदा विधानसभा में महज 4 सीटों वाली हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा (हम) के संरक्षक केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी इस बार 40 सीटों पर दावा ठोंक रहे हैं तो बिना विधायक की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सर्वेसर्वा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान राज्य की कुल 243 सीटों पर असर होने का दावा कर रहे हैं। एनडीए के एक और सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा कहते हैं कि अगर उन्हें डुबोने की कोशिश की गई तो डुबोने वाले भी नहीं बचेंगे। उधर, मुख्यमंत्री नीतीश की पार्टी जदयू चुनाव में भाजपा के बराबर सीटों की दावेदारी पर पहले से अडिग है। जाहिर है एनडीए के सभी घटक दल अपनी ताकत बढ़ाने की फिराक में हैं।

महागठबंधन में भी रार कम नहीं

सीटों के बंटवारे पर महागठबंधन में भी रार कम नहीं है। कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार भी 70 सीटों पर दावेदारी कर रही है। उधर, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी विधानसभा की 60 सीट और उप मुख्यमंत्री पद की मांग कई दफा सार्वजनिक रूप से कर चुके हैं। इस बीच 'बदलो सरकार-बदलो बिहार' यात्रा निकाल चुके वामदलों के नेता 45 सीटों की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले चुनाव में उन्हें 29 सीटें मिली थीं, जिनमें 16 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर महज 19 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। अगर इन दलों की मांग मान ली जाए तो क्या राष्ट्रीय जनता दल (राजद) महज 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? पिछली बार राजद 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 78 सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस भी महागठबंधन के बैनर तले चुनाव मैदान में उतरने की जुगत खोज रहे हैं। उनकी लालू यादव और तेजस्वी से मुलाकात भी हो चुकी है। उधर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 12 सीटों पर दावा किया है। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि झारखंड में हमने राजद के एकमात्र विधायक को मंत्री बनाया, क्योंकि हम गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में थे। अब राजद और कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) की भी इच्छा महागठबंधन के बैनर तले चुनाव में उतरने की है। उसके नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं। हालांकि कांग्रेस उसे साथ लेने को राजी नहीं है। ऐसे में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में सिरफुटौव्वल तय है।

जातीयता की धुरी पर टिकी है राजनीति

प्रशांत के दावे के बाद बढ़ी कशमकश

चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के लिए कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर भी अपनी जनसुराज पार्टी बनाकर मैदान में उतर चुके हैं। प्रशांत अपनी पार्टी में कई रिटायर्ड नौकरशाहों के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचन्द्र प्रसाद सिंह (आरसीपी सिंह) को जोड़ चुके हैं। बिहार के चर्चित यू-ट्यूबर मनीष कश्यप भी भाजपा के रास्ते अब प्रशांत के साथ हो लिए हैं। प्रशांत का दावा है कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उधर, वोट बैंक बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत तमाम दल किसी से तालमेल न हो पाने की स्थिति में अकेले मैदान में ताल ठोंकेंगे। ये दल भले ही चुनाव नहीं जीतें, लेकिन दोनों गठबंधनों में किसी का खेल जरूर खराब करेंगे।

इस बीच, राजद ने वरिष्ठ समाजवादी नेता मंगनीलाल मंडल को बिहार राजद का अध्यक्ष बनाकर अति पिछड़ों में पैठ बनाने का बड़ा दांव चल दिया है। मंडल धानुक जाति से आते हैं। वह जदयू के रास्ते से राजद में आए हैं। उनका व्यक्तित्व निर्विवाद रहा है। वे लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मंडल अपनी जाति का कितना वोट राजद को ट्रांसफर करा पाते हैं। बिहार की सियासत में जाति एक कटु सच्चाई है। वहां जाति के आधार पर न सिर्फ नेता हैं, बल्कि जाति के आधार पर दल भी बने हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हों, चिराग पासवान हों या पशुपति पारस, मुकेश सहनी हों या जीतनराम मांझी, उपेन्द्र कुशवाहा हों या सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार हों अथवा रामचन्द्र प्रसाद सिंह, सभी की राजनीति जातीयता की धुरी पर ही टिकी है।

उधर, चुनाव से चार महीना पहले एनडीए ने राज्य में वर्षों से खाली पड़े आयोग-बोर्डों के पदों को भर दिया है। कुल 13 आयोगों में से 8 का अध्यक्ष जदयू ने अपने नेताओं को बनाया है। 4 आयोग के अध्यक्ष भाजपा के नेता बनाए गए हैं, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता और चिराग पासवान के बहनोई मृणाल पासवान को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जीतनराम मांझी के दामाद देवेन्द्र कुमार को इसी आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी के हिस्से में महज सदस्य का पद मिला है। ऐसा करके टिकट के दावेदारों की भीड़ पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया है। हालांकि राजनीति के जानकार चुनावी साल में वर्षों से खाली पड़े आयोग के पुनर्गठन पर सवाल कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि क्या एनडीए सरकार को वापसी में संशय लग रहा है, जो आयोग- बोर्डों में खाली पदों को भरने में तत्परता दिखाई!

पूरी तन्मयता से प्रचार में जुटी है भाजपा

सियासी गुणा-गणित से इतर भाजपा पिछले एक साल से चुनाव प्रचार में पूरी तन्मयता से जुटी है। एक साल में प्रधानमंत्री सात बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। इसमें पांच बार का दौरा तो जनवरी से जून तक हो चुका है। वह अपनी हर सभा में लालू-राबड़ी के शासनकाल पर हमला बोलते हैं और हजारों करोड़ की योजनाओं की घोषणा करते हैं। काश! वह योजनाएं सफलीभूत हो जातीं तो बिहार बदहाल नहीं रहता। भाजपा ने राज्य में चुनावी वार रूम का गठन कर दिया है। इसका प्रभारी दिल्ली के रोहन गुप्ता को बनाया गया है। उसमें 150 से अधिक सदस्य हैं। रोहन गुप्ता काफी तेज-तर्रार नेता हैं। हरियाणा और दिल्ली के चुनाव में भी उन्होंने भाजपा वार रूम की कमान संभाली थी और पार्टी को विजय दिलाई थी। आने वाले दिनों में भाजपा जिला स्तर तक वार रूम का गठन करेगी। लेकिन भाजपा की बड़ी दिक्कत बिहार में पार्टी का कोई अहम चेहरा न होना है, जिसे मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राजद, जदयू समेत कई दलों से घुमते हुए भाजपा में पहुंचे हैं। उनका अपना कोई जनाधार नहीं है। उनके पिता स्व. शकुनि चौधरी जरूर कद्दावर नेता थे, लेकिन वह कांग्रेस और समाजवादी पृष्ठभूमि के थे। इसी तरह प्रदेश भाजपा के अधिकांश नेता आयातित ही हैं। ऐसे में भाजपा चुनाव के बाद कोई उलटफेर कर दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

किंगमेकर बनने की चाहत में चिराग

अपने पुराने जनाधार को संगठित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। एक चर्चा यह भी है कि जदयू इस बार चिराग की दावेदारी वाले ब्रह्मपुर, दिनारा, कस्बा, हरनौत, कदवां, रुपौली, जगदीशपुर, रघुनाथपुर और ओबरा आदि सीटों पर नजर गड़ाए हुए है। इन सीटों पर पिछली बार चिराग की पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। चिराग इस बार किंगमेकर बनने की चाहत लिए हुए हैं। उनकी कोशिश है कि बिना उनके समर्थन के बिहार में कोई सरकार नहीं बने।

गर्मी में बढ़ा राजनीतिक तापमान... चुनाव की तैयारी में महागठबंधन भी पीछे नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार राज्य के कोने-कोने में घूम रहे हैं और मौजूदा सरकार की नाकामी उजागर कर रहे हैं। उन्होंने 'तेजस्वी डिजिटल फोर्स' का गठन कर युवाओं को उससे जुड़ने की अपील की है। तेजस्वी कहते हैं कि मुख्यमंत्री उम्रजनित बीमारियों के कारण अचेतावस्था में हैं और सहयोगी दलों के नेता नौकरशाहों के साथ मिलकर बिहार को लूट रहे हैं। अपराध चरम पर है और सरकार खामोश। आयोगों के पुनर्गठन में भाई-भतीजावाद का बोलबाला है। सीएम को लगे हाथ जमाई आयोग, दामाद आयोग और मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए।
कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और वामदलों के नेता भी अपने पक्ष में जनमत बनाने के लिए अभियान चलाए हुए हैं। राहुल गांधी एक साल में पांच बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। लब्बोलुआब यह कि गरमी के मौसम में बिहार में राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है।

हनीमून ट्रिप पर पति की हत्या : समाज में महिलाओं के बदलते स्वरूप की एक चिंताजनक तस्वीर

स्वतंत्रता व नैतिकता के बीच संतुलन जरूरी

सोनम की इस जघन्य घटना ने यह भी साबित किया है कि आज के दौर में विवाह जैसे पवित्र संबंध को कुछ लोग सिर्फ स्वार्थ और योजनाओं का जरिया बना रहे हैं। सोशल मीडिया, फ़िल्मों और भौतिकवादी जीवनशैली ने संबंधों की गरिमा को प्रभावित किया है। महिलाएं अब सिर्फ सहनशीलता का प्रतीक नहीं, बल्कि निर्णायक भी बन रही हैं, लेकिन जब यह निर्णय क्रोध, लालच या बदले की भावना से लिया जाए तो वह अपराध बन जाता है। इसलिए आज की महिला को शक्ति के साथ-साथ संयम और मूल्य आधारित निर्णयों की भी आवश्यकता है, तभी समाज में संतुलन बना रह सकता है।

मधु बनर्जी
पत्रकार व लेखिका

हाल ही में एक सनसनीखेज घटना में सोनम नामक महिला ने मेघालय के शिलांग में हनीमून ट्रिप के दौरान अपने पति की हत्या करा दी। ऐसा ही एक हत्याकांड महाराष्ट्र के सांगली जिले के कुपवाड़ में भी हुआ, जहां पत्नी राधिका ने शादी के 15 दिन बाद ही कुल्हाड़ी मार कर पति की हत्या कर दी। ऐसे मामले समाज में महिलाओं की बदलती मानसिकता और रिश्तों की गहराई से हो रही टूटन का संकेत है।

जहां पहले महिलाएं सामाजिक दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियों और रिश्तों की मर्यादा में खुद को समर्पित मानती थीं, वहीं अब कुछ महिलाएं अपने अधिकारों की आड़ में आक्रामक और आत्मकेंद्रित भी होती जा रही हैं। यह बदलाव पूर्णतः नकारात्मक नहीं है, क्योंकि स्त्रियों का आत्मनिर्भर होना, अपनी बात कह पाने का साहस रखना जरूरी है, लेकिन जब यह स्वतंत्रता किसी की हत्या तक पहुंच जाए, तो यह आज़ादी नहीं, हिंसक प्रवृत्ति बन जाती है।

इस तरह की घटनाएं यह भी दर्शाती हैं कि रिश्तों में संवाद की कमी, असंतोष, लालच या अवैध संबंध जैसे कारण भी महिलाओं को अपराध की ओर धकेल सकते हैं। समाज में महिला सशक्तिकरण की सही परिभाषा अब और अधिक आवश्यक हो गई है, जहां 'सशक्त' का अर्थ 'संवेदनशील और संतुलित' हो, न कि 'हिंसक और स्वार्थी'।

सोनम की घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम स्त्री स्वतंत्रता और नैतिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाना भूलते जा रहे हैं? यह वक्त है कि हम महिलाओं की भावनात्मक शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों की समझ को प्राथमिकता दें, ताकि 'सशक्त महिला' का मतलब केवल स्वतंत्रता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और संवेदना से भी जुड़ा हो।

सोनम की इस जघन्य घटना ने यह भी साबित किया है कि आज के दौर में विवाह जैसे पवित्र संबंध को कुछ लोग सिर्फ स्वार्थ और योजनाओं का जरिया बना रहे हैं। सोशल मीडिया, फ़िल्मों और भौतिकवादी जीवनशैली ने संबंधों की गरिमा को प्रभावित किया है। महिलाएं अब सिर्फ सहनशीलता का प्रतीक नहीं, बल्कि निर्णायक भी बन रही हैं, लेकिन जब यह निर्णय क्रोध, लालच या बदले की भावना से लिया जाए तो वह अपराध बन जाता है। इसलिए आज की महिला को शक्ति के साथ-साथ संयम और मूल्य आधारित निर्णयों की भी आवश्यकता है, तभी समाज में संतुलन बना रह सकता है।

नारीवाद बनाम उग्रता

20वीं सदी की स्त्री जहां सहनशीलता, त्याग और समर्पण का पर्याय मानी जाती थी। वहीं 21वीं सदी की स्त्री अधिकारों की लड़ाई लड़ती हुई दिखाई देती है। यह बदलाव स्वागत योग्य है, लेकिन जब अधिकार, अहंकार में बदल जाएं, तब वह विनाशकारी हो जाते हैं। आज कुछ महिलाएं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, क्षणिक भावनाओं और बाहरी प्रभावों के चलते ऐसे निर्णय करने लगी हैं, जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। स्त्री स्वतंत्रता का अर्थ यदि यह हो जाए कि अपने साथी को रास्ते से हटाकर एक नया जीवन शुरू किया जाए, तो यह न केवल मानवता के विरुद्ध है, बल्कि स्त्री सशक्तिकरण की अवधारणा के साथ भी धोखा है।

संबंधों पर सोशल मीडिया का प्रभाव

आज के युग में सोशल मीडिया, वेब सीरिज और फिल्मों ने रिश्तों की परिभाषा को बहुत हद तक प्रभावित किया है। हर दिन सोशल मीडिया पर "परफेक्ट कपल" बनने की होड़, आभासी रिश्तों की गहराई को भ्रम बना देती है। वास्तविक जीवन में जब इन आदर्शों की पूर्ति नहीं हो पाती, तब असंतोष, अविश्वास और क्रोध जन्म लेता है। साथ ही, कुछ महिलाएं आज "इंस्टेंट फ्रीडम" चाहती हैं, जिसमें कोई बंधन न हो, कोई उत्तरदायित्व न हो। ऐसे में विवाह जैसे पवित्र संबंध भी "व्यावसायिक समझौते" का रूप ले लेते हैं, जहां अगर लाभ नहीं मिला तो साथी को हटाने में संकोच नहीं किया जाता।

सही मायनों में महिला सशक्तिकरण

- वर्तमान में महिला सशक्तिकरण की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? क्या केवल आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय करने की क्षमता ही सशक्तिकरण है? या फिर इसमें भावनात्मक समझ, सामाजिक उत्तरदायित्व और आत्मनियंत्रण भी शामिल होना चाहिए?
- सशक्त स्त्री वह है जो अपने निर्णयों में संतुलन रखे, जो संवाद में विश्वास करे, जो सह-अस्तित्व की भावना रखे। यदि किसी संबंध में मतभेद हो, तो उसका समाधान हिंसा नहीं, संवाद और विधिक प्रक्रिया से किया जाए।

अपराध में महिलाओं की भागीदारी, आंकड़ों पर एक नजर

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार

- 2022 में कुल दर्ज आपराधिक मामलों में महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों की संख्या 2.9 प्रतिशत रही।
- इनमें से सबसे अधिक मामले घरेलू झगड़ों, संपत्ति विवाद, और अवैध संबंधों से जुड़े पाए गए।
- 2021 में कुल 1,22,955 महिलाएं अपराधों में लिप्त पाई गईं, जिनमें हत्या और हत्या की साजिश के मामले भी शामिल हैं।
- 2023 की रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि दंपत्ति झगड़ों और तलाक के मामलों में महिलाओं द्वारा हिंसात्मक कदम उठाने की घटनाएं बढ़ रही हैं।

• ये आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि महिलाओं द्वारा किए जा रहे अपराधों को अब महज "भावनात्मक प्रतिक्रिया" कह कर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक शिक्षा समय की जरूरत

- आज की तेज भागती दुनिया में भावनात्मक शिक्षा लगभग समाप्त हो चुकी है। स्कूल और कॉलेज सिर्फ अकादमिक ज्ञान दे रहे हैं, जबकि रिश्तों की समझ, क्रोध प्रबंधन, और मानसिक स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। विशेषज्ञों के अनुसार, महिलाओं में डिप्रेशन, तनाव, और इमोशनल आउटबर्स्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं। 2022 की 'इंडियन जर्नल ऑफ साइकाइट्री' की रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं में रिलेशनशिप बेस्ड एंगर और गिल्ट डिसऑर्डर में 22 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।
- इसका सीधा संबंध रिश्तों में बढ़ते अपराध से है। ऐसे में जरूरी है कि हम स्कूल स्तर पर ही "लाइफ स्किल्स", "रीलेशनशिप मैनेजमेंट" और "मेंटल हेल्थ अवेयरनेस" जैसे विषयों को शामिल करें।

कानून और समाज दोनों को चाहिए नई दृष्टि

वर्तमान कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं, लेकिन कुछ मामलों में इनका दुरुपयोग भी होता है। इसलिए कानून व्यवस्था में निष्पक्षता और महिला अपराधों पर भी गंभीर दृष्टिकोण आवश्यक है। साथ ही, समाज को भी महिलाओं को केवल देवी या पीड़िता की नजर से देखना बंद करना होगा। उन्हें इंसान की तरह देखना होगा, जिसमें अच्छाइयां भी हैं, कमियां भी। तभी हम उनके अपराधों को भी उसी गंभीरता से देख पाएंगे, जैसे पुरुषों के अपराध को।

शक्ति के साथ चाहिए संयम

सोनम की घटना कोई एक दिन की कहानी नहीं, बल्कि समाज में लंबे समय से उपज रहे एक जटिल मानसिक परिवर्तनों का परिणाम है। यह उस स्त्री की तस्वीर है जो अब निर्णय करने में सक्षम है, लेकिन निर्णयों में संयम और विवेक की कमी उसे अपराध के रास्ते पर ले जा रही है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सशक्त स्त्री वह नहीं जो सबकुछ तोड़ दे, बल्कि वह है जो रिश्तों को जोड़ने का साहस रखे। शक्ति के साथ जब तक मूल्य, संवेदना और संयम नहीं जुड़े होंगे, तब तक महिला सशक्तिकरण अधूरा रहेगा।

इसलिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम स्त्रियों को न केवल स्वतंत्र बनाएं, बल्कि उन्हें संतुलित, संवेदनशील और विवेकशील भी बनाएं, ताकि वे अपने अधिकारों का सही अर्थ समझ सकें और समाज को बेहतर दिशा में ले जा सकें।

संयुक्त परिवार: संस्कारों की पाठशाला, रिश्तों की मजबूती की नींव पड़ रही कमजोर

भारतीय छोड़ रहे, पश्चिम अपना रहा

संयुक्त परिवार का मतलब केवल साथ रहना ही नहीं है, बल्कि यह सामाजिक निवेश है, जहां पीढ़ियां साझा जिम्मेदारियों और मूल्यों से बंधी होती हैं। आज जब दुनिया मानसिक थकावट, अकेलेपन और तनाव की गिरफ्त में है, संयुक्त परिवार एक ऐसा सामाजिक समाधान बनकर उभरते हैं, जो न केवल भावनात्मक सुरक्षा देते हैं, बल्कि आर्थिक स्थिरता और सांस्कृतिक निरंतरता भी सुनिश्चित करते हैं। संयुक्त परिवार कोई पिछड़ी सोच नहीं, बल्कि एक फ्यूचर रेडी मॉडल है। जहां पश्चिम अब इसे दोबारा खोज रहा है, वहीं भारत में इसे छोड़ना विडंबना है।

मधुलिका सिंह
पत्रकार व लेखिका

वेदों से लेकर रामायण-महाभारत तक और मुगल व ब्रिटिश काल से लेकर आज़ादी के बाद तक संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं। भारत की परम्परा में संयुक्त परिवार न केवल सामाजिक ढांचा, बल्कि एक जीवंत मनोवैज्ञानिक व्यवस्था भी है, जहां हर पीढ़ी को उसका स्थान, उसकी भूमिका और उसका सहारा मिलता है। यहां दादा-दादी से कहानियां मिलती हैं, मां-बाप से अनुशासन और भाई-बहनों से सह-अस्तित्व। यह एक ऐसा इमोशनल इकोसिस्टम है, जिसमें हर व्यक्ति को सुरक्षा, संवाद और सरोकार मिलता है।

परिवार का औसत आकार घटा, 80 प्रतिशत परिवार एकल

पहले परिवारों में जमीन साझा होती थी, आजीविका खेती से जुड़ी थी, निर्णय सामूहिक होते थे। परिवार एक "आर्थिक इकाई" और "संस्कारशाला", दोनों होता था। घर का हर सदस्य अपनी भूमिका बखूबी निभाता था, लेकिन इन दिनों भारत में तेजी से एकल परिवार (न्यूक्लियर फैमिली) का चलन बढ़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 2011 की जनगणना में भारत में 70 प्रतिशत परिवार एकल पाए गए। 2022 तक यह संख्या शहरी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। एक संयुक्त परिवार में औसतन 7 सदस्य हुआ करते थे तो अब न्यूक्लियर में सिर्फ 3 सदस्य रह गए हैं। जबकि भारत के संयुक्त परिवार के मॉडल को विदेशों में अपनाया जा रहा है।

विदेशियों को लुभा रहा

कभी न्यूक्लियर फैमिली मॉडल के उत्साही रहे पश्चिमी देश अब मल्टी जेनरेशनल लिविंग यानी संयुक्त परिवार की ओर लौट रहे हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण:

- **अमेरिका** • पीईडब्ल्यू रिसर्च सेंटर (2021) की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में 18 प्रतिशत लोग अब मल्टी-जनरेशन परिवारों में रहते हैं, जो 1971 में सिर्फ 7 प्रतिशत थे। कोविड महामारी के बाद, आर्थिक अस्थिरता और बुजुर्गों की देखभाल की जरूरतों ने संयुक्त परिवार को फिर से प्रासंगिक बना दिया है।
- **ब्रिटेन** • इंग्लैंड में "ग्रेनी फ्लैट्स" यानी बुजुर्ग माता-पिता के लिए घर के हिस्से बनाए जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एकल माता-पिता और युवाओं के लिए परिवार में रहना एक लागत-प्रभावी समाधान बन गया है।
- **कनाडा** • कनाडा में 2023 में मल्टी जेनरेशनल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टैक्स इंसेंटिव स्कीम शुरू की है।
- **जापान** • जापान में "सेंडविच जेनरेशन" (जो माता-पिता और बच्चों दोनों की देखभाल करते हैं) अब 3-जेनरेशन हाउसहोल्ड मॉडल को फिर से अपना रही है, क्योंकि यह मानसिक और आर्थिक रूप से अधिक टिकाऊ है।

बच्चों के मानसिक विकास की नींव है संयुक्त परिवार

- मनोचिकित्सक डॉ आरके शर्मा बताते हैं कि जब एक ही घर में परिवार के कई सदस्य साथ रहते हैं, तो बच्चों को न सिर्फ भावनात्मक सुरक्षा मिलती है, बल्कि वे सामाजिक रूप से भी मजबूत बनते हैं। इसके विपरीत आज के समय में न्यूक्लियर फैमिली (एकल परिवार) का चलन तेजी से बढ़ रहा है, वहीं संयुक्त परिवार बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- एक बच्चे की परवरिश केवल माता-पिता की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार की सामूहिक भागीदारी से उसका समग्र विकास होता है। जब परिवार में बुजुर्ग, चाचा-चाची, भाई-बहन जैसे सदस्य साथ रहते हैं, तो बच्चे को विविध अनुभव और सीखने के अनेक अवसर मिलते हैं।

संयुक्त परिवार के फायदे

बुजुर्गों का साथ : दादा-दादी, नाना-नानी जैसे अनुभवशील सदस्य बच्चों को जीवन मूल्यों, अनुशासन और परम्पराओं से जोड़ते हैं। माता-पिता की व्यस्तता के दौरान अन्य सदस्य बच्चों का ध्यान रखते हैं, जिससे बच्चों की देखभाल में कोई कमी नहीं आती।

सामाजिक कौशल : संयुक्त परिवार में रहकर बच्चे सहयोग, सहनशीलता, बांटने की भावना और संवाद कौशल सीखते हैं। जब माता-पिता व्यस्त होते हैं, तो दादा-दादी या अन्य सदस्य बच्चों के साथ खेलने, बात करने और समय बिताने के लिए उपलब्ध रहते हैं।

भावनात्मक सहारा : डर, तनाव या अकेलेपन की स्थिति में बच्चों को परिवार का भावनात्मक सहारा मिलता है। हर सदस्य का दृष्टिकोण, कहानी और व्यवहार बच्चों के लिए एक नया सीखने का अवसर बनता है।

अकेलापन : एकल परिवार में बच्चे प्रायः अकेलापन महसूस करते हैं, जिससे आत्मविश्वास में कमी आ सकती है।
भावनात्मक असंतुलन : सहयोग की कमी से बच्चों में चिड़चिड़ापन, ग़ुस्सा और तनाव की प्रवृत्ति बढ़ सकती है।
अभिभावकों पर दबाव : बच्चों की संपूर्ण देखभाल केवल माता-पिता पर निर्भर होने से उनमें थकान और तनाव का स्तर बढ़ सकता है।

एकल परिवार की मजबूरी

1. शहरीकरण और रोजगार की तलाश
- नौकरी, शिक्षा और बेहतर जीवनशैली के लिए युवा वर्ग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहा है, जहां छोटे घरों में केवल पति-पत्नी और बच्चे रह सकते हैं।

2. महंगाई और खर्चों का दबाव
- बढ़ती मंहगाई, शिक्षा व स्वास्थ्य की लागत ने युवा दंपत्तियों को स्वतंत्र होने पर विवश किया है। संयुक्त खर्च अब "बोझ" लगने लगा है।

3. महिलाओं की आत्मनिर्भरता और शिक्षित वर्ग का उदय
- अब महिलाएं भी नौकरी करने लगी हैं, फैसले भी लेने लगी हैं। इससे पारम्परिक पितृसत्तात्मक ढांचे में दरार आई है।

4. व्यक्तिवाद की सोच और निजी स्वतंत्रता
- आज का युवा स्वतंत्र निर्णय लेना चाहता है, कैसे जीना है, क्या खाना है, कैसे बच्चों की परवरिश करनी है। संयुक्त परिवार में ये विकल्प सीमित रहते हैं।

5. पीढ़ी दर पीढ़ी वैचारिक मतभेद
- आज की पीढ़ी तकनीक, विचार, जीवनशैली तेजी से बदल रही है। इससे दो पीढ़ियों के बीच टकराव, अलग रहने की मानसिकता को जन्म देता है।

आज भी जरूरी हैं संयुक्त परिवार

संयुक्त परिवार केवल साथ रहना नहीं है, यह एक सामाजिक निवेश है, जिसमें पीढ़ियां साझा अनुभवों, जिम्मेदारियों और मूल्यों से बंधी होती हैं। आज के दौर में, जबकि दुनिया मानसिक थकावट, अकेलेपन और तनाव की गिरफ्त में है, संयुक्त परिवार एक ऐसा सामाजिक समाधान बनकर उभरते हैं, जो न केवल भावनात्मक सुरक्षा देते हैं, बल्कि आर्थिक स्थिरता और सांस्कृतिक निरंतरता भी सुनिश्चित करते हैं। संयुक्त परिवार कोई पिछड़ी सोच नहीं, बल्कि एक फ्यूचर रेडी मॉडल है। जहां पश्चिम अब इसे दोबारा खोज रहा है, वहीं भारत में इसे छोड़ना विडंबना है। यह न केवल सामाजिक-आर्थिक ढांचे को मजबूत करता है, बल्कि एक स्थायी जीवनशैली का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

अकेलेपन से भारत में बीस करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार

जीवन मूल्यों के संवाहक हैं हमारे बुजुर्ग

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग बीस करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, जिसमें बुजुर्गों की संख्या बहुत अधिक है। भारत में लगभग बयालीस प्रतिशत कर्मचारी डिप्रेशन और एन्क्जाइटी से त्रस्त हैं। डिप्रेशन और एन्क्जाइटी की मूल वजहों में से एक है अकेलापन। अकेलेपन के कारण मन में नकारात्मक भावों का उद्गम होता है, कार्य करने की इच्छा खत्म हो जाती है और इस कारण घुटन और निराशा बढ़ती जाती है।

डॉ. गौरव बिस्सा,
एसोसिएट प्रोफ़ेसर, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर

जर्मनी के विख्यात डॉ. फिट्ज़ टालबोट बच्चों की दुसाध्य बीमारियों का इलाज करने में सिद्धस्थ थे। वे पहले बच्चे को दवाई देते और जब दवा काम न करती तो वे अपनी सबसे अनुभवी नर्स को बुलाकर एक पर्ची पकड़ा देते। नर्स बच्चे को लेकर चली जाती और अप्रत्याशित रूप से बच्चा दो से तीन दिन में ठीक हो जाता। लोगों के लिए यह कौतूहल था। एक दिन उनसे समाज के समस्त प्रबुद्धजनों ने जिद करके कहा कि आखिर पर्ची पर लिखी दवा का नाम बताया जाए। डॉ. टालबोट ने पर्ची दे दी। पर्ची पर सिर्फ दो शब्द लिखे थे और वे शब्द थे "दादी मां"। टालबोट ने कहा कि ऐसे बच्चों को कॉटेज वार्ड में बैठी दादी मां दो दिन दुलारती है, प्रेम करती है और बच्चा ठीक हो जाता है। टालबोट ने कहा कि दुसाध्य से दुसाध्य बीमारी का इलाज भी ग्रैंडपेरेंट्स के प्रेम से संभव है। यह है ग्रैंडपेरेंट्स का महत्त्व।

अकेलेपन से लड़ने को मंत्रालय

जापान में अकेलेपन की समस्या बहुत विकराल है, क्योंकि वहां पर बुजुर्गजनों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। इसी कारण से वहां सरकार ने अकेलेपन से लड़ने के लिए एक नया मंत्रालय "मिनिस्ट्री ऑफ़ लोनलीनेस" बनाया है। इस मंत्रालय का काम ही बुजुर्गों का अकेलापन दूर करना, समाज की मुख्यधारा से उन्हें जोड़ना और उन्हें संबल देना है। जिस प्रकार भारत में परिवारों में छीजत हो रही है, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत सरकार को भी अकेलेपन से लड़ने के लिए विभाग या मंत्रालय बनाना पड़े।

महत्त्व बुजुर्गों का

संस्कारों, प्रेम या सच पूछो तो जीवन मूल्यों का संवाहक या कैरियर कौन हैं? माता पिता और उससे भी कहीं ज्यादा दादा, दादी, नाना, नानी अर्थात ग्रैंडपेरेंट्स अर्थात समाज के बुजुर्गजन। वर्तमान पीढ़ी में ग्रैंडपेरेंट्स और घर के बुजुर्ग मानो गायब हैं। बुजुर्ग उन संस्कारों के वाहक थे जो दूध में घुली चीनी की तरह होते थे। यानि नजर नहीं आते, लेकिन उनका महत्त्व बहुत है। आज दूध रूपी ऊपरी संसाधन तो हैं लेकिन संस्कारों की मिठास मिसिंग है। इसी वजह से मोटिवेशनल स्पीकर्स का जन्म होता है, क्योंकि अब निराश व्यक्ति कहां जाए? आपने कभी सुना कि तीस-पैंतीस साल पहले युवा डिप्रेशन या एग्जाम एन्क्जाइटी का शिकार हुआ हो? शायद नहीं। उस समय घर के बुजुर्ग और ग्रैंडपेरेंट्स स्थिति को संभाल लेते थे। अब ऐसा नहीं है। आज की पीढ़ी परीक्षा में जबर्दस्त परफॉर्मेंस देने के बावजूद जिन्दगी की परफॉर्मेंस में कमज़ोर है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है संयुक्त परिवारों की टूटन और बुजुर्गों की उपेक्षा।

रोबोट से दोस्ती

पहले संयुक्त परिवार थे। मोहल्ला भी एक तरह का परिवार ही था जो "सामाजिक पुलिस" का काम करता था। बड़ा परिवार और अनेक रिश्तेदारों की परस्पर निर्भरता के कारण व्यक्ति के मन का गुबार उनके बीच निकल जाया करता था। वर्तमान में इंसान अपनों के बीच भी बहुत अकेला है, क्योंकि वे अपने, "अपने" नहीं अपितु "औपचारिक अपने" हैं। औपचारिक अपनों का अर्थ है किसी विशेष प्रयोजन, लाभ या काम के कारण एकीकृत होना और उसके बाद बिखर जाना। आज के व्यक्ति में इतना अहंकार है कि वो किसी से दोस्ती कर ही नहीं पा रहा। समाचार पत्रों के अनुसार, जापान में अकेलेपन से त्रस्त लोग रोबोट से दोस्ती कर रहे हैं, अर्थात कृत्रिम दोस्तों का सहारा ले रहे हैं। दोस्त में कुछ छोटी- मोटी बुराई हो या आपस में कोई समस्या हो तो उसे सुलझा लेना उचित है।

क्या कहता है शोध?

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग बीस करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, जिसमें बुजुर्गों की संख्या बहुत अधिक है। भारत में लगभग बयालीस प्रतिशत कर्मचारी डिप्रेशन और एन्क्जाइटी से त्रस्त हैं। डिप्रेशन और एन्क्जाइटी की मूल वजहों में से एक है अकेलापन। अकेलेपन के कारण मन में नकारात्मक भावों का उद्गम होता है, कार्य करने की इच्छा खत्म हो जाती है और इस कारण घुटन और निराशा बढ़ती जाती है। अकेलेपन पर शोध के आंकड़े डराने वाले हैंः

- हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, अकेलेपन के चलते व्यक्ति की आयु तेजी से घटती है। जितनी आयु एक दिन में पंद्रह सिगरेट्स पीने के कारण कम होती है, लगभग उतनी ही उम्र अकेलेपन से त्रस्त होने के कारण भी कम हो जाती है।
- डब्लूएचओ के अनुसार, आत्महत्या का तीसरा सबसे बड़ा कारण अकेलापन है।
- अकेलेपन से पीड़ित व्यक्ति को यह डर होता है कि लोग उनके बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं, अतः वो आत्मविश्वास की कमी के चलते उनसे नहीं मिलता।

ह्यूमन लाइब्रेरीज़

अकेलेपन की इस समस्या से लड़ने के लिए, डेनमार्क में ह्यूमन लाइब्रेरीज़ का प्रचलन है। आम तौर पर हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां एक पुस्तक किराए पर लेते हैं और उसे पढ़कर लौटाते हैं। ह्यूमन लाइब्रेरी में आप एक व्यक्ति को तीस मिनिट्स के लिए किराए पर लेते हैं और उसके साथ अपने मन की बातों को शेयर करते हैं। इससे वेंटिलेशन होता है और मन हल्का हो जाता है। यह सुनना अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। यदि कोई आपको फोन करके कुशलक्षेम पूछ रहा है तो इसका अर्थ है कि उसे आपकी परवाह है। कहीं भविष्य में हमें भी ह्यूमन लाइब्रेरी की आवश्यकता न पड़ने लगे? मध्यप्रदेश सहित अनेक मेट्रो सिटीज़ में भी ह्यूमन लाइब्रेरी का प्रचलन हो चला है।

अंतरवैयक्तिक सम्बन्धों से सफलता

शोध के अनुसार, मनुष्य की सफलता में उसके ज्ञान, कौशल, डिग्री, कला और कार्य अनुभव का महत्त्व सिर्फ पंद्रह प्रतिशत के लगभग है। बाकी आपकी पिच्यासी प्रतिशत सफलता का कारण, लोगों के साथ आपके अंतरवैयक्तिक सम्बन्ध हैं अर्थात यदि परस्पर सम्बन्ध अच्छे हैं तो सफलता तय है। महान व्यक्तित्वों ने जीवन में सर्वाधिक महत्त्व आपसी संबंधों को निभाने के लिए दिया। जो बुजुर्ग लोग घर से निकलते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, मिलते जुलते हैं; वे अधिक सकारात्मक होते हैं और वे अकेलेपन का अपेक्षाकृत कम शिकार होते हैं।

जो हो रहा है.. वो सर्वश्रेष्ठ है

अकेलेपन से लड़ने के लिए बुजुर्गों का अगाथिज्म दर्शन के साथ जीना उचित है। अगाथिज्म दर्शन के अनुसार "जो हो रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ है और अंत में सब अच्छा ही होगा"। ये सोच एक संतुष्टि और अकेलेपन के भय से राहत देती है। दिन में सिर्फ पांच से दस मिनिट्स प्रकृति के बीच बैठना, रोजाना सिर्फ पन्द्रह मिनिट्स पुस्तकें पढ़ना, दस मिनिट्स लोगों से मिलकर उनका हाल पूछना, ग्रेटीट्यूड जर्नल अर्थात आभार पुस्तिका बनाकर जीवन के सुखों को रोजाना लिखना आदि अपनाकर बुजुर्ग अकेलेपन की पीड़ा को कुछ हद तक कम कर सकते हैं।

भारतीय दर्शन में छिपा है समाधान

भारतीय दर्शन में अकेलेपन और तनाव को दूर कर उत्तम सम्बन्ध बनाने के कुछ मन्त्र हैं। पहला मन्त्र है "ददाति प्रतिगृह्णाति" अर्थात "देना और लेना"। किसी को अपना श्रम देना, उसका स्वास्थ्य पूछने जाना, और किसी की मदद करके उसे कृतार्थ महसूस करवाने को पहला सूत्र माना गया है। मन की बात को कहना और सामने वाले के मन की बात को पूर्ण मनोयोग से सुनने को शास्त्रों में "गुह्याख्याति प्रच्छति" कहते हैं। साथ भोजन करना, सामने वाले व्यक्ति के भोजन की रूचि के अनुसार उसे भोजन करवाना आदि परस्पर संबंधों में सुधार करके व्यक्ति का अकेलापन दूर होता है। शास्त्रों में इसे "भुक्ते भोजयते चैव" कहा गया है। इसके अलावा मित्रों, बंधुओं और समाज के साथ हृदय से जुड़ना, अपनों के लिए उपयोगी बनना और अपने संपर्क सूत्रों के दुर्गुणों या बुरी बातों पर मिट्टी डालते हुए उनके उजले पक्षों पर ध्यान देना ही सार्थक है।

भावी पीढ़ी पर विश्वास जरूरी

भारतीय परिवारों में क्लेश की एक बड़ी वजह यह भी है कि बुजुर्ग सदस्य रिटायरमेंट लेना ही नहीं चाहते। उम्रदराज हो चुके हैं लेकिन बुजुर्गों को यह विश्वास ही नहीं है कि उनकी संतान अब योग्य हो चुकी है। संतान को सदा बालक समझने की गलती ही संयुक्त परिवारों को नष्ट कर रही है। अस्सी साल के पार बुजुर्ग व्यक्ति जमीन जायदाद, फिक्स्ड डिपोजिट, विवाह में मिठाई और वस्त्रों के लेन-देन के हिसाब आदि समीकरणों में उलझे पड़े हैं। बुजुर्गों को चाहिए कि अब ये रोजमर्रा के काम भावी पीढ़ी को करने दें। इसका अर्थ यह नहीं है कि बुजुर्गों का सम्मान न हो। बुजुर्गों की दूरदृष्टि का लाभ मिलना ही चाहिए। बुजुर्गों को भी यह समझना चाहिये कि हर छोटी बात में भूमिका निभाना उनके लिए कष्टप्रद हो सकता है।

बढ़ती उम्र, कमजोर होता शरीर

बुजुर्गों का अपने मन पर नियंत्रण जरूरी है। उम्र बढ़ती जाती है और शरीर कमज़ोर होता जाता है, लेकिन इसके विपरीत, बुजुर्गों के शौक, इच्छाएं और कामनाएं कतई कमजोर नहीं पडतीं। शरीर से भले ही मनुष्य वृद्ध हो जाए, लेकिन उसके मन में प्रसिद्धि, उत्तम भोजन व पर्यटन, कमाकर इकट्ठे हुए पैसे का सुख भोगने और परिवार से सम्मान पाने की इच्छा कम ही नहीं होती। यही समस्या का मूल है। एक उम्र के बाद इन्द्रियों, धन संग्रहण प्रवृत्ति तथा खुद की सत्ता के सुख को कम करने की दिशा में प्रयास शुरू कर देने चाहिए। साथ ही बुजुर्गों को वित्तीय स्वतंत्रता का ध्यान रखना चाहिए। बुजुर्गों को अपने खर्च को नियंत्रित कर कुछ गुप्त धन स्वयं के लिए अवश्य रखना चाहिए। बुजुर्गावस्था में ललित कला, घूमना, मित्र बंधुओं से वार्तालाप व मेलजोल, चित्रकारी, बागवानी जैसे अपने शौक जीवित रखना जरूरी है, ताकि जीवन्तता बनी रहे। याद रहे, कि बुजुर्गावस्था एक उम्र है। मानसिक बुढ़ापे से बचिए। यही जीने का तरीका है।

लघु कद, विराट नेतृत्व: तेंबा बावूमा की ऐतिहासिक टेस्ट विजय

टेस्ट के ताज का छोटा सरताज

शुरुआती दौर में बावूमा की खूबियों का किसी को पूरा अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने तानों और उपहासों की लंबी श्रृंखला झेली। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। खेल पर नियंत्रण बनाए रखते हुए उन्होंने न सिर्फ अपने देश के क्रिकेट प्रेमियों के 27 वर्षों के इंतज़ार को खत्म किया, बल्कि 'चोकर' (अंतिम क्षणों में हारने वाले) की पहचान को मिटाकर दक्षिण अफ्रीका को आईसीसी ट्रॉफी दिलाई।

अजय अस्थाना
वरिष्ठ पत्रकार

वास्तविकता में किसी भी सफल व्यक्ति से अधिक प्रशंसा उस शख्स की होनी चाहिए, जिसने सही समय पर सही व्यक्ति को किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए चुना। दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट टीम के कप्तान तेंबा बावूमा की कहानी कुछ ऐसी ही है। इस बात का सम्मान भी होना चाहिए कि किसी ने उनकी शारीरिक बनावट को दरकिनार करते हुए उन्हें राष्ट्रीय टीम की कमान सौंपने लायक समझा।

शुरुआती दौर में बावूमा की खूबियों का किसी को पूरा अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने तानों और उपहासों की लंबी श्रृंखला झेली है। इसके बावजूद उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। खेल पर नियंत्रण बनाए रखते हुए उन्होंने न सिर्फ अपने देश के क्रिकेट प्रेमियों के 27 वर्षों के इंतज़ार को खत्म किया, बल्कि 'चोकर' (अंतिम क्षणों में हारने वाले) की पहचान को मिटाकर दक्षिण अफ्रीका को आईसीसी ट्रॉफी दिलाई।

टेस्ट क्रिकेट की विश्व चैम्पियन बनने की इस गौरवशाली उपलब्धि ने सम्पूर्ण दक्षिण अफ्रीका को हर्षोल्लास में डुबो दिया। बावूमा अब तक सौ प्रतिशत टेस्ट जीतने वाले ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने एक भी मैच नहीं गंवाया। उनकी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने 10 टेस्ट में से 9 मैच जीते और एक ड्रॉ रहा।

डब्ल्यूटीसी फाइनल : शिखर संघर्ष की गवाही... 2025 की विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल दक्षिण अफ्रीका और पूर्व चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया के बीच आरंभ से अंत तक एक रोमांचक संघर्ष बना रहा। चौथे दिन तक भी यह तय कर पाना कठिन था कि ट्रॉफी किसके नाम होगी। यहां एक बार फिर तेंबा बावूमा के धैर्य और नेतृत्व की सराहना करनी होगी, जिन्होंने टॉस से लेकर बल्लेबाजी तक एक पल को भी अपने आत्मबल में कमी नहीं आने दी। विपक्षी कप्तान की लंबी कद-काठी हो या तेज गेंदबाजों की सिर के पास से गुजरती बाउंसर, बावूमा कहीं नहीं डगमगाए। आज के युवाओं को उनसे यह सीख लेनी चाहिए कि जंग कद-काठी या रंग से नहीं, आत्मविश्वास और कौशल से जीती जाती है।

इतने छोटे कद-काठी वाले बल्लेबाज द्वारा आईसीसी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन शायद ही क्रिकेट इतिहास में पहले देखा गया हो। अब दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी बावूमा के प्रशंसक बन चुके हैं।

ट्रोलिंग के बीच नेतृत्व का उदय

शुरुआती दिनों में बावूमा को उनके कद, चेहरे और तकनीक को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया गया। उन्हें 'कोटा प्लेयर' कहकर भी उपहासित किया गया, जिससे उनके चयन और स्थायित्व पर सवाल उठाए गए। लेकिन बावूमा कहां हारने वाले थे, उन्होंने इन चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और संयम के साथ किया। डब्ल्यूटीसी फाइनल के तीसरे दिन चोटिल हैमस्ट्रिंग के बावजूद खेली गई उनकी 65 रनों की साहसी पारी ने टीम को आत्मबल से भर दिया। इस पारी ने यह साबित कर दिया कि ट्रोलिंग उनकी कमजोरी नहीं, ताकत बन चुकी है।

27 वर्षों का सूखा खत्म

- फाइनल मुकाबले में बावूमा के साथ एडन मार्करम ने 143 रनों की संघर्षपूर्ण साझेदारी की, जिसने टीम को जीत के करीब पहुंचाया। हालांकि अंतिम क्षणों में मार्करम एक खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका की यह जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक विजय भी थी, जब टीम ने लॉर्ड्स जैसे प्रतिष्ठित मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को हराया।
- फाइनल की दूसरी पारी में जब टीम को 282 रनों का लक्ष्य मिला और पहला विकेट महज़ 9 रन पर गिर गया, तो मैदान पर मौजूद दक्षिणी अफ्रीकी क्रिकेट प्रेमी दर्शकों में सन्नाटा पसर गया। इसके बाद क्रीज पर आए बावूमा ने संभल कर खेलना शुरू किया और अपने पहले रन के लिए उन्होंने 30 गेंदें खेली।
- आलोचकों ने कहा कि आज बावूमा 'फ्यूज' हो जाएंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह खिलाड़ी बड़े इरादे के साथ मैदान में उतरा है। तीसरे दिन वे लंगड़ाते हुए बल्लेबाजी कर रहे थे, और चौथे दिन दर्द के कारण ज्यादा देर तक टिक नहीं सके, लेकिन तब तक वे टीम को जीत के दरवाज़े तक पहुंचा चुके थे।
- रबाडा की नौ विकेटों की घातक गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ी। वहीं बल्लेबाजों ने कमिंग्स, स्टार्क और हेज़लवुड जैसे खतरनाक गेंदबाजों की प्रतिष्ठा को ध्वस्त कर दिया।

प्रेरक नेतृत्व और युगांतकारी छवि

- इस ऐतिहासिक जीत के बाद क्रिकेट दिग्गज एबी डिविलियर्स और ग्रीम स्मिथ ने बावूमा की संतुलित और प्रेरक कप्तानी की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। एबी डिविलियर्स ने खड़े होकर ताली बजाकर उन्हें सम्मान दिया। यह सम्मान केवल एक खिलाड़ी के लिए नहीं, बल्कि एक नए युग के नेता के लिए था।
- चेहरे, कद-काठी और आलोचनाओं की आंधियों के बावजूद बावूमा की कप्तानी की परिपक्वता, निर्णय की सटीकता और नेतृत्व की चमक उनके हर फैसले में झलकी।
- हिंदी कमेंट्री कर रहे पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी उनकी कप्तानी को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा—

"यह असाधारण नहीं था, महान भी नहीं था, पर जब टेस्ट क्रिकेट और अफ्रीकी क्रिकेट का इतिहास लिखा जाएगा, तब एडन मार्करम की इनिंग और बावूमा की कप्तानी को महानतम में गिना जाएगा।"

वर्नोन फिलेंडर ने बावूमा को "शानदार लीडर" बताया और कहा कि उन्होंने पिछले 24 महीनों में पूरी टीम का विश्वास जीता है। फिलेंडर ने उल्लेख किया कि टेस्ट एवं वन-डे दोनों प्रारूपों में बावूमा ने निरंतर अच्छा प्रदर्शन किया है और बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया है।

महान क्षेत्ररक्षक रहे जान्टी रोड्स ने बावूमा के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीका की ये जीत एकजुट टीम प्रदर्शन व एक अद्भुत नेतृत्व का परिणाम है।

पग-पग पर पीड़ा..परेशानी

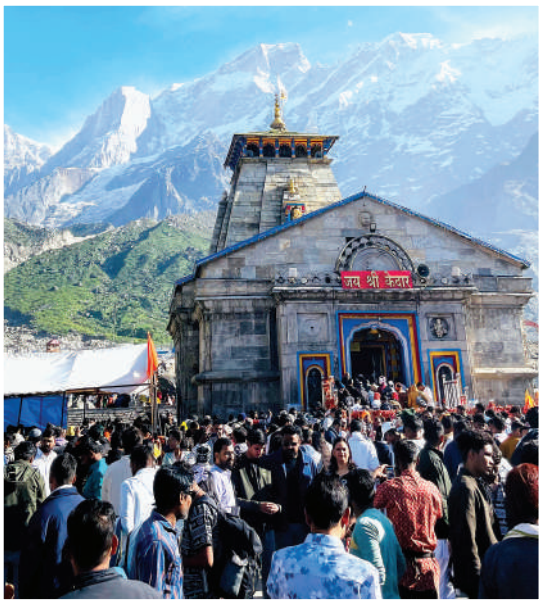

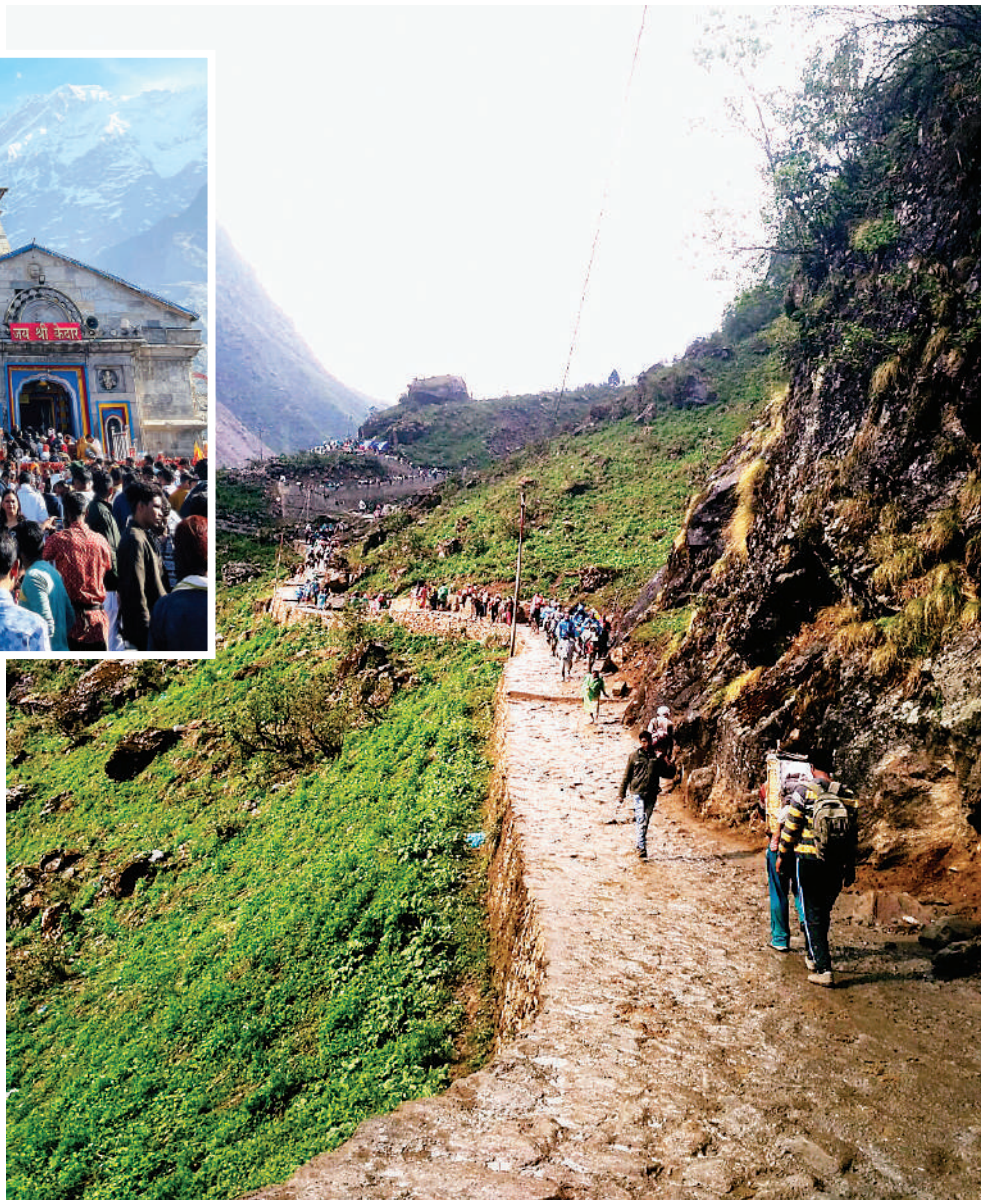

मनोज वर्मा ✍ वरिष्ठ पत्रकार

गौरी कुंड से शुरू होने वाले इस ट्रैक पर न तो सड़क सही है, रात को रोशनी भी पूरी नहीं होती है। जगह- जगह पर खड्डे हैं। खाई में गिरने से बचने के लिए लगी रेलिंग टूट रही है। पैदल यात्री को खच्चर, घोड़े और पालकी वालों के साथ चलने के लिए हर आठ से दस फीट चौड़े ट्रैक पर हर 50 कदम पर सड़क पर जगह ढूंढनी पड़ती है।

बारह ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसा होने पर हर बार चर्चा होती है कि नियमों की पालना नहीं होने से श्रद्धालु यात्रियों की जान जाती हैं। लेकिन कभी इसको लेकर चर्चा नहीं होती है कि जो लाखों श्रद्धालु पहाड़ी ट्रैक से 3584 मीटर ऊंचाई पर स्थित मंदिर में महादेव के दर्शन करने जाते हैं, उनके लिए कितनी असुविधाएं उस मार्ग पर मौजूद रहती है। गौरी कुंड से 16 किलोमीटर के ट्रैक पर पग- पग पर परेशानी का आलम है। देश के हर क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालु यह देख हताश होते हैं। अचरज इस बात का भी है कि देश का मीडिया हमेशा इन परेशानियों को नजर अंदाज करता है। सोशल मीडिया पर इन्फ्लूर्स कभी यह नहीं बताते कि यह राह कितनी परेशानी भरी है। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर मीडिया हाउस के रिपोर्टर और इन्फ्लूर्स हैली सर्विस से ही वहां पहुंचते है और मंदिर प्रांगण की रिपोर्ट और रील हम तक पहुंचाते है। जिन्हें देख श्रद्धालु जब उस राह पर पहुंचते है तो सिर्फ आह ही निकलती है। उसे राहत तब ही मिलती है जब कठिन राह पार कर जैसे तैसे ऊपर पहुंच कर बाबा केदार के दर्शन हो जाए। गौरी कुंड से शुरू होने वाले इस ट्रैक पर न तो सड़क सही है, रात को रोशनी भी पूरी नहीं होती है। जगह- जगह पर खड्डे हैं। खाई में गिरने से बचने के लिए लगी रेलिंग टूट रही है। पैदल यात्री को खच्चर, घोड़े और पालकी वालों के साथ चलने के लिए हर आठ से दस फीट चौड़े ट्रैक पर हर 50 कदम पर सड़क पर जगह ढूंढनी पड़ती है।

मैंने 14 जून को यह यात्रा पूरी की थी। इस दौरान साथ चलने वाले उत्तराखंड के ही रहने वाले विनोद रावत बताते हैं कि 2013 की आपदा में मूल ट्रैक खत्म हो गया था। इसके बाद नया ट्रैक बना, लेकिन इसका रखरखाव नहीं होने से यात्री परेशान होते हैं। सरकार और समिति ध्यान नहीं देती है। मंदिर के आस पास करोड़ों खर्च कर कॉरिडोर बन रहा है, लेकिन यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान ट्रैक के खड्डे तक ठीक नहीं होते। सरकार लाइट तक सही नहीं करवाती। लखनऊ निवासी अनुपम अग्रवाल दूसरी बार यहां आए हैं। वे कहते है कि बारिश की सीजन है। खच्चर घोड़े पर रोक नहीं है। एक समय तय होना चाहिए इनके चलने का। इनके मल मूत्र की सफाई नहीं होने से राह में यात्रियों का गिरकर चोटिल होना आम बात है। इनकी इतनी ज्यादा संख्या है कि पैदल यात्री का चलना दूभर हो जाता है।

जून में केदारनाथ जाने वालों के लिए संघर्ष की शुरुआत सोनप्रयाग पहुंचने से ही होने लगती हैं। गौरीकुंड में आगे भीड़ होने पर गाड़ियां सीतापुर पार्किंग में रखवाई जाती है। यहां से तीन से चार किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन चेक करवाने और फिर यहां से गौरी कुंड जाने के लिए फिर से लाइन में लगना पड़ता है। सरकार ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने और वाहन भीड़ नियंत्रित करने के लिए स्थानीय सवारी गाड़ियों को सोनप्रयाग से गौरी कुंड ले जाने के लिए अधिकृत किया है। एक जानकारी के अनुसार इस समय 250 गाड़ी लगाने का दावा है, लेकिन अगर आप परिवार के साथ आए हैं तो भीड़ में इन गाड़ियों में जगह पाना आसान नहीं होता, जिससे घंटों लग जाते हैं। कुल मिलाकर छह किलोमीटर का यह सफर काफी दुर्गम है।

गौरी कुंड से शुरू होने वाले इस ट्रैक से पहले एक भव्य द्वार है। जिसे देख लगता है कि आगे सफर काफी आनंदित होने वाला है, लेकिन इसके आगे घोड़ा पड़ाव को पार करने में पसीने छूट जाते हैं। पूरे रास्ते में पहले पांच किलोमीटर पर एक डायवर्शन के पास ही इक्का- दुक्का पुलिस कर्मी नजर आते हैं। इसके बाद नंदी बेस कैंप तक कोई सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आता। खच्चर वालों के साथ श्रद्धालुओं को रास्ता देने को लेकर झगड़े होते रहते हैं और कई बार तो नौबत हाथापाई तक आ जाती है, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं है। कोई चोटिल हो जाए तो स्पॉट पर चिकित्सा सुविधा नहीं है। आरोग्य मंदिर बने हैं, लेकिन उनको सूचना देने को कोई संचार व्यवस्था नहीं है, जिससे कोई घायल तक पहुंच सके।

संकरी गली से हजारों यात्रियों का निकलना चुनौती

गौरी कुंड टैक्सी स्टैंड से ट्रैक की ओर जाना आसान नहीं हैं। करीब 500 मीटर का 8 फीट चौड़े रास्ते को पार करना होता है, जिसके दोनों ओर दुकानें, गेस्ट हाउस हैं। खच्चर समान लेकर साथ में चलते हैं। इस दौरान एक जगह ऐसी आती है, जिसमें सीढ़ियां है यहां यात्री अटकते हैं तो उनकी जान अटक जाती है। बुजुर्गों की स्थिति और ज्यादा खराब होती है। रेंग- रेंग कर भीड़ चलती है। सबको इसी बात का डर रहता है कि यहां भगदड़ हो गई तो समझो जान गई। हालांकि स्थानीय लोग बताते हैं कि बाबा की कृपा से ऐसा हुआ नहीं है। यह रास्ता चौड़ा करना सरकार के लिए भी आसान नहीं है, प्रयास भी नहीं हुए।

वीआईपी कल्चर बड़ी परेशानी

ऊपर पहुंचने के बाद भी केदारनाथ मंदिर दर्शन करना आसान नहीं है। हेलीकॉप्टर के अलावा आने वाले सभी यात्रियों के लिए यहां अपने रजिस्ट्रेशन को दिखाकर टोकन लेना पड़ता है। इसके बाद घंटों लाइन में लग अपने आराध्य की झलक पा सकते हैं। इस दौरान हेलीकॉप्टर से आने वालों को हेलीपेड पर ही 2500 की रसीद कटवा कर वीआईपी दर्शन करवाए जाते हैं, ताकि वे जल्द वापस जा सके। लेकिन इसके साथ-साथ राज्य सरकार के अतिथि, पुलिस के अतिथि, पंडितों के यजमान और अन्य अघोषित वीआईपी सामान्य श्रद्धालु को अपने दर्शन की राह में रोड़े की तरह नजर आते हैं।

अब राहत की बात

मोदी सरकार ने इस वर्ष मार्च में ही सोनप्रयाग से केदारनाथ तक करीब चार हजार करोड़ रुपए की लागत से 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाने का निर्णय किया है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि रोपवे की क्षमता 1,800 पीपीएचपीडी होगी और यह प्रतिदिन 18,000 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा। इसके साथ हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे बनेगा। लेकिन कब? तब तक बाबा केदार की जय बोलते हुए अव्यवस्थाओं के बीच पैदल श्रद्धालुओं को यह यात्रा पूरी करनी होगी।

एसआई भर्ती की रिपोर्ट पेश हो

जस्टिस समीर जैन की अगुवाई में कोर्ट ने सरकार को 21 फरवरी, 15 मई, और 26 मई 2025 तक निर्णय करने के लिए समय सीमा दी। कोर्ट ने चेतावनी दी कि 26 मई तक निर्णय न होने पर वह हस्तक्षेप करेगा। अब सरकार को एक जुलाई को रिपोर्ट पेश करनी है कि वह भर्ती रद्द करने के पक्ष में है या नहीं)

प्रवीण ढींगरा वरिष्ठ पत्रकार

- **नीट में दूसरे की जगह परीक्षा देने वालों को कॉलेज ने निलंबित किया तो कोर्ट ने बहाल करते हुए कहा, कानून में अभाव, सरकार को लाना चाहिए नया कानून**
- **इधर, नकल व डमी अभ्यर्थियों के सहारे एसआई बने अभ्यर्थियों को भी कोर्ट से जमानतें मिली, अब सरकार कठघरे में है**

एक जुलाई की तारीख प्रदेश में बेरोजगारों के साथ पुलिस की वर्दी पहन चुके बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इस दिन वर्ष 2001 की एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर की खरीद-फरोख्त और डमी अभ्यर्थियों के मामलों से जुड़े केस की सुनवाई होनी है। सरकार को अपना फैसला बताना है कि वह भर्ती को रद्द कर रही है या बरकरार रख रही है। सरकार के एक मंत्री खुद इस भर्ती को लेकर सरकार को घेरे हुए है। सरकार कोर्ट के कठघरे में खड़ी है। सवालों के घेरे में भी। वह भी तब, जब पिछली सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में नकल को लेकर 'असल' और सख्त कानून बनाया, लेकिन एसओजी ने भर्ती के जिन आरोपी एसआई को गिरफ्तार किया, वे कोर्ट से जमानत पर हैं। इधर, नीट परीक्षा पास कर डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे कई अभ्यर्थियों पर आरोप है कि उन्होंने दूसरे की जगह परीक्षा दी। उन्हें भी पकड़ा गया। नकल के कानून के दायरे में लाया गया, लेकिन उनका भी मेडिकल कॉलेज से निलंबन बहाल हो गया। वो भी कोर्ट के आदेश से। कोर्ट ने यहां भी सरकार के कानून की बात की। राज्य व केंद्र सरकार से अपेक्षा जताई कि वे बड़ी संख्या में सामने आ रहे डमी अभ्यर्थियों को लेकर कानून लेकर आएगी। अब एक जुलाई को कोर्ट में सरकार अपना कौनसा फैसला लेकर आएगी, इस कसौटी पर भी सूबे के मुखिया का आंकलन होगा।

दरअसल, भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं न केवल शिक्षा और रोजगार का प्रवेश द्वार हैं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों को साकार करने वाली परीक्षाएं भी हैं। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) और राजस्थान पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा जैसी प्रक्रियाएं निष्पक्षता और पारदर्शिता की कसौटी पर खरी नहीं उतरी हैं। हाल के वर्षों में राजस्थान में इन परीक्षाओं में अनियमितताओं, खासकर नीट में प्रॉक्सी उम्मीदवारों और एसआई भर्ती में पेपर लीक के मामलों ने शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सरकार खुद अपनों के सवालों से भी पशोपेश में है।

कोई ठग रहा तो कोई ठगा जा रहा

इसी साल, प्रदेश में नीट के नाम पर सामने आए ठगी के एक बड़े मामले में जयपुर मेट्रो थाने में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल बलवान सिंह सहित तीन लोग शामिल थे। ये लोग कथित तौर पर नीट का पेपर 40 लाख रुपए में बेचने का दावा कर रहे थे। हालांकि जांच में पता चला कि उनके पास कोई पेपर नहीं था, और यह धोखाधड़ी थी।

सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 भी पेपर लीक के कारण विवादों में रही। इस परीक्षा में 859 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन एसओजी की जांच में खुलासा हुआ कि पेपर राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले ही लीक हो गया था। इस मामले में 100 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें 50 ट्रेनी एसआई और दो आरपीएससी सदस्य शामिल थे। अब तक, 45 ट्रेनी एसआई को बर्खास्त और 11 को निलंबित किया गया। एक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और उनके ट्रेनी एसआई बेटे को भी गिरफ्तार किया गया, जो इस घोटाले की गहराई को दर्शाता है। 10 आरोपियों, जिनमें 11 ट्रेनी एसआई शामिल थे, को जमानत दी गई, लेकिन एसओजी की अपील के बाद 11 अन्य की रिहाई पर रोक लगी।

कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार कानून लाए

नीट में प्रॉक्सी उम्मीदवारी, यानी किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर परीक्षा देने के लिए भेजना, वैसे तो एक गंभीर अपराध है। बावजूद इसके नीट में प्रॉक्सी मामले राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और बिहार जैसे राज्यों में अधिक देखे गए हैं, जहां कोचिंग संस्थानों की संख्या और उम्मीदवारों की भीड़ ज्यादा है। चार साल पहले, 2021 में कोटा में कुछ प्रॉक्सी मामले दर्ज किए गए। इसके बाद ऐसे मामले और बढ़े। ऐसे ही चार छात्र पकड़े गए तो कॉलेज ने उन्हें निलंबित कर दिया। इनकी याचिका पर जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ ने फैसला सुनाया कि इस तरह के कृत्य में शामिल उम्मीदवारों के प्रवेश को निलंबित, निष्कासित या रद्द करने की शक्ति प्रदान करने वाले किसी भी प्रावधान के अभाव में याचिकाकर्ताओं का निलंबन न केवल अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर था, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन था।

न्यायालय ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामला यह नहीं था कि उन्होंने किसी और को अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए कहकर प्रवेश प्राप्त किया, बल्कि यह था कि उन्होंने किसी और की नकल करके परीक्षा दी। ऐसे मामले में उनकी अपनी योग्यता या मेडिकल पाठ्यक्रमों में एडमिशन पाने की पात्रता के बारे में कोई विवाद नहीं था, इसलिए सावधानी के साथ नरम रुख अपनाना पड़ा। याचिकाकर्ताओं के कृत्य के प्रति अस्वीकृति व्यक्त करते हुए और ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए न्यायालय ने कहा कि अब समय आ गया कि केंद्र सरकार उचित कानून लाए।

सरकारें जागी, लेकिन फैसला नहीं कर पाई

▪ राजस्थान पुलिस और एसओजी ने नीट से संबंधित धोखाधड़ी में कार्रवाई की। जयपुर के 40 लाख रुपए के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, और मोबाइल चैट व ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर सबूत जुटाए गए। वहीं, एनटीए ने 2024 के नीट विवादों के बाद बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी निगरानी को मजबूत किया। एनटीए के महानिदेशक को हटाया गया, और इसे केवल प्रवेश परीक्षाओं तक सीमित किया गया।

▪ इधर, 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राजस्थान परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पारित किया, जिसमें पेपर लीक के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। यह कानून एसआई मामलों में लागू हुआ। फिर भी सरकार इस भर्ती में धांधली की जड़ तक नहीं पहुंच सकी है। सरकार ने अक्टूबर 2024 में छह सदस्यीय कैबिनेट समिति बनाई गई, जिसने एसओजी, महाधिवक्ता, और पुलिस मुख्यालय के साथ मिलकर परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की। लेकिन सरकार ने अंतिम निर्णय नहीं किया।

▪ भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली भाजपा सरकार पर निर्णय में देरी के लिए आलोचना झेल ही रही है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भर्ती रद्द करने की मांग की, लेकिन उनकी हालिया चुप्पी आंतरिक असहमति को दर्शाती है।

हाईकोर्ट की सक्रियता से दबाव में सरकार

दरअसल, 19 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति का आदेश दिया। ट्रेनी एसआई की पासिंग-आउट परेड और फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई। यह आदेश नवंबर 2024 में दोहराया गया। फरवरी 2025 में, कोर्ट ने आरपीएससी को "निष्क्रिय संस्था" कहकर आलोचना की, क्योंकि उसने आंतरिक मिलीभगत के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को वित्तीय पहलुओं की जांच के लिए शामिल किया। जस्टिस समीर जैन की अगुवाई में कोर्ट ने सरकार को 21 फरवरी, 15 मई, और 26 मई 2025 तक निर्णय लेने के लिए समय सीमा दी। कोर्ट ने चेतावनी दी कि 26 मई तक निर्णय न होने पर वह हस्तक्षेप करेगा। अब तारीख 1 जुलाई की तय है।

एक कविता

अविरल

डॉ. शोभा भंडारी

बहना है तो, अविरल गति से,
जैसे नदिया की लहरे हों,
उदित होना है सूरज की तरह,
और अविरल परिक्रमा, पृथ्वी की तरह।
अविराम, निरंतर, निर्बाधित,
जैसे वृक्षों का हो पल्लवन।
है प्रचुर मात्रा में प्राणवायु का,
रग रग में होता अविरल संचारण।

प्रकृति के हर कण में होता सतत्,
अविरल ऊर्जा का संचालन।
प्रकृति सर्वश्रेष्ठ गुरू है,
सर्वश्रेष्ठ है इसका मार्गदर्शन,
सतत् अवलोकन -चिंतन करने से,
बहती अविरल जीवनधारा प्रति क्षण।
करती पुरुषार्थ -पराक्रम का मार्ग प्रशस्त,
होता अविरल जीवन का क्रम।

हे पथिक सूरज की गरिमा लेकर,
लेहरों सा जीवट बनकर,
लेकर ऊर्जा -उष्मा सहज -सरल,
ऐसा बने जीवन का हर क्षण अविरल।।।
बाधा न बनें, रोड़ा न बनें,
दूजे के अविरल सुलभ मार्ग में,
प्रयत्न हो सहयोग भाव का,
है समरसता का लक्ष्य बने।।।।

साहित्य की आंख कैमरे की आंख नहीं, इससे कुछ ज्यादा है

रचना के जरिए खुद को ढूंढता है रचनाकार

साहित्यकार समाज की विसंगतियों को, विद्रूपताओं को ज्यों का त्यों सामने नहीं रखता, संवेदनात्मक तरीके से सामने रखता है। जिसे संवेदनात्मक ज्ञान कहा है। यह संवेदना पहले रचनाकार को रचती है। 'हुआ करती जब कविता पूर्ण, हुआ करता कवि का निर्माण।' पहले कवि का निर्माण होता है। साहित्य पहले रचनाकार को रचता है। उसके होने के अर्थ से उसका परिचय करवाता है। एक रचनाकार रचना के माध्यम से अपने होने को ढूंढता है। वह अपनी स्वयं की तलाश में निकलता है।

दिनेश सिंदल ✍ कवि, लेखक

कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। किसी समय विशेष में समाज की स्थिति क्या थी.. इसे समझने के लिए हमें भूतकाल में जाने की जरूरत नहीं है, केवल उस समय के साहित्य का अध्ययन ही हमें उस समय के समाज से रु-ब-रु करवा देता है। इसका अर्थ ये लिया जाता है कि समाज में जो कुछ भी हो रहा है, साहित्य उसे ज्यों का त्यों समाज के सामने रखता है। उसे उकेरता है, उसे चित्रित करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। साहित्य की आंख कैमरे की आंख नहीं है।

हां, साहित्य वह दर्पण है जिसमें समाज अपना चेहरा देखता है। साहित्य समाज के चेहरे के साथ साथ उसके अंतर मन को भी उसके सामने प्रकट करता है। कोई रचनाकार समाज का एक कैमरे की तरह चित्र नहीं उतारता। वह उसे रचता है। रचनाकार की आंख कैमरे का लेंस नहीं है। वह उससे कुछ ज्यादा है। वह जब देखता है तो केवल उसकी भौतिक आंख ही काम नहीं करती, बल्कि उसकी मन की आंख भी काम करती है, वह भी देखती है। साहित्यकार जो कुछ भी इस समाज में अपनी भौतिक आंख से देखता है, उसमें कुछ जोड़ता है और उसे जोड़ने के बाद वह चित्रित करता है, प्रकट करता है।

सूरदास ने कृष्ण के जिस बाल रूप को देखा है, वह केवल सूरदास की भौतिक आंख से देखा गया कृष्ण का रूप नहीं है। वह उससे कुछ ज्यादा है, जो कैमरे की आंख नहीं दिखा सकती।

मुझे महान चित्रकार पिकासो की एक घटना याद आती है। एक व्यक्ति पिकासो के पास जाता है। वह पिकासो से अपनी पत्नी का चित्र बनाने का आग्रह करता है। वह अपनी जेब से अपनी पत्नी का एक छोटा सा फोटो निकाल कर पिकासो को देते हुए कहता है कि मेरे लिए आप इसका एक बड़ा पोर्ट्रेट बना दे। पिकासो चित्र रख लेता है और कुछ दिनों बाद आकर पोट्रेट ले जाने को कहता है।

कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति पोट्रेट लेने आता है। पिकासो उसे पोट्रेट देता है। वह व्यक्ति देखता है कि पिकासो द्वारा बनाया गया चित्र उसकी पत्नी के चित्र से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है। वह उसे देखते ही भड़क जाता है। ये क्या बनाया है आपने? ये तो मेरी पत्नी के चेहरे से बिल्कुल मेल ही नहीं खा रहा।

वह फोटो दिखाते हुए कहता है। देखो इसमें मेरे पत्नी की नाक कितनी छोटी है, आपने कितनी बड़ी और ऊंची बना दी। इस फोटो में उसकी आंखें कैसी हैं, आपने ये कैसी बना दी।

पिकासो उसे समझाते हुए कहता, 'तुम्हारी पत्नी बड़ी अहंकारी है, उसकी नाक इतनी ऊंची ही होनी चाहिए। वह बहुत गुस्सैल है, उसकी आंखें प्रेम बरसाती हुई नहीं.. आग उगलती हुई ही होनी चाहिए। यही तुम्हारी पत्नी का सही चित्र है।'

साहित्यकार का संवेदनात्मक ज्ञान

साहित्यकार समाज की विसंगतियों को, विद्रूपताओं को ज्यों का त्यों सामने नहीं रखता, संवेदनात्मक तरीके से सामने रखता है। जिसे संवेदनात्मक ज्ञान कहा है।

यह संवेदना पहले रचनाकार को रचती है। 'हुआ करती जब कविता पूर्ण, हुआ करता कवि का निर्माण।' पहले कवि का निर्माण होता है। साहित्य पहले रचनाकार को रचता है। उसके होने के अर्थ से उसका परिचय करवाता है। एक रचनाकार रचना के माध्यम से अपने होने को ढूंढता है। वह अपनी स्वयं की तलाश में निकलता है।

अतः हमें एक बार रुक कर देख लेना चाहिए कि कविता के नाम पर कहीं हम अपनी कुंठाएं तो नहीं परोस रहे?

आपकी कविता आपको कितना सुख देती है? या आपको तभी सुख देती है जब कोई उस पर ताली बजाता है। कोई उस पर पुरस्कार देता है। फिर आप उस कोई और के इशारे पर चलते हैं। उस कोई और का काम होता रहता है और आपकी आत्मा कूड़े करकट के नीचे दबती रहती है। क्योंकि आपने कभी अपनी आत्मा के लिए तो गाया ही नहीं। कभी एकांत में अपना गीत अपने आप को तो सुनाया ही नहीं। कभी क्या आपने स्वयं के लिए ताली बजाई..? अपनी कविता पर खुश हो कर..। स्वयं को कोई पुरस्कार दिया..? स्वयं ने ताली बजा दी होती तो भीड़ की तालियों की याद नहीं रहती, भीड़ की तालियां प्रभावित नहीं करती। वह बजाए.. चाहे नहीं बजाएं।

कवि वह सपेरा है जिसकी पिटारी में सांपों की जगह लोगों के दिल बंद होते हैं। लेकिन उसमें एक दिल उसका अपना भी है और रचना उसके हृदय का प्रकटीकरण है। कागज पर रचना के माध्यम से कवि का दिल ही उतरता है। कवयित्री ' अदा ' का एक शेर है -

कहती दुनिया देख 'अदा' ने शेर कहे
कागज़ पर ये दिल उतरा है ऐसे ही

रचना पहले रचनाकार से संवाद करती है। वह उसके आत्मशोधन, आत्मशुद्धि का कारण बनती है। फिर समाज तक पहुंचती है।

शेर जब सिक्कों में ढलकर आ गए
हम अदब से दूर चल कर आ गए

छोड़ कर हमको कहां जाती नदी
देखने पर्वत पिघल कर आ गए

बात तो दिल को बदलने की हुई
आप तो कपड़े बदल कर आ गए..

आज इतना ही।
फिर कभी किसी नए विषय के साथ।

भारत से लेकर रूस तक है दीवानगी मिथुन की

कट्टर नक्सली से अभिनेता बनने का सफर

सुधांशु टाक
लेखक, समीक्षक

यह बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है कि मिथुन फ़िल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले एक कट्टर नक्सली थे, लेकिन उनके परिवार को कठिनाई का सामना तब करना पड़ा जब उनके एकमात्र भाई की मौत दुर्घटनावश बिजली के करंट लगने से हो गई। इसके बाद मिथुन अपने परिवार में लौट आये और नक्सली आन्दोलन से खुद को अलग कर लिया, हालांकि ऐसा करने के कारण नक्सलियों से उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता था, क्योंकि नक्सलवाद को वन-वे रोड माना जाता रहा। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और जीवन में उन्हें एक आइकोनिक दर्जा प्रदान करने में प्रमुख कारण बना। यह बात भी कम लोग ही जानते हैं कि उन्होंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है।

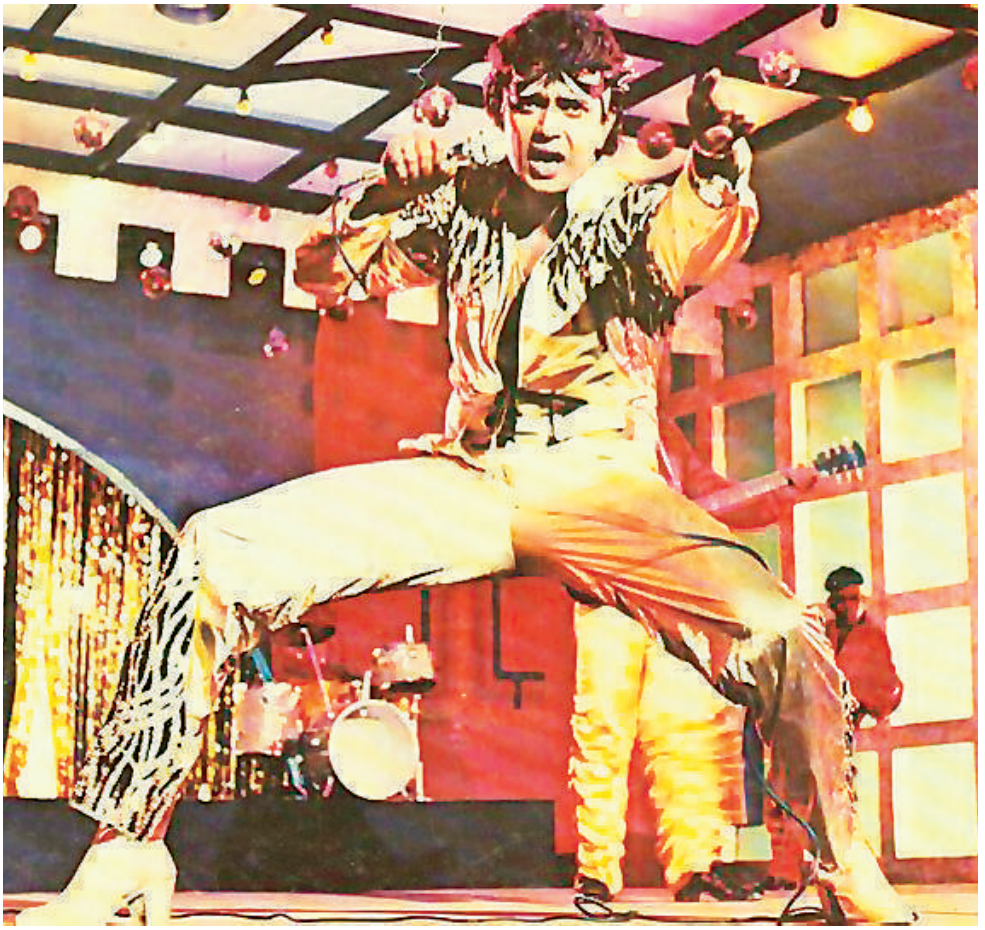

बात सन् 1982 की है। मिथुन चक्रवर्ती की 'डिस्को डांसर' भारत में प्रदर्शित होने के बाद रूस में रिलीज हुई। इस फिल्म पर न रूसी समाजवाद का असर था और न इसे किसी प्रगतिशील विचारधारा के निर्देशक-लेखक का सान्निध्य प्राप्त था। यह तो बस बप्पी लहरी के कुछ चुराए हुए विदेशी गीतों के हिंदी संस्करणों और मिथुन के डांस मूव्ज की वजह से 80 के दशक में हिंदुस्तानी पॉप कल्चर का हिस्सा बनी थी।

रूस के कल्चर का भी हिस्सा, 'डिस्को डांसर' इसी वजह से बनी। रूसी समाजवाद और राज कपूर वाले दौर से बाहर आ चुका रूसी युवा 80 के दशक में पलायनवादी सिनेमा में मनोरंजन ढूंढने लगा था और आशावादी बातों से ज्यादा उसे पश्चिम का भौतिकवाद पसंद आने लगा था। इसी वजह से जिस मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में एक जमाने में 'दो बीघा जमीन' जैसी यथार्थवादी फिल्में प्रशंसा पाती थीं, वहां पर 'डिस्को डांसर' ने हाउसफुल होने के कीर्तिमान रचे। रूसियों ने इसके निर्देशक बी सुभाष और मिथुन चक्रवर्ती के लिए फिल्म खत्म होने के बाद खड़े होकर तालियां बजाईं।

मिथुन के लिए हिन्दी सीखने लगे रूसी

इस फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती को राज कपूर की ही तरह सारा रूस जानने लगा। उन्हें वहां के एयरपोर्ट व सड़कों पर देखकर लोग दौड़े चले आते और जिस तरह आज जस्टिन बीबर के प्रशंसकों को 'बीलिबर्स' कहा जाता है, 80 के दशक के रूस में मिथुन चक्रवर्ती के फैन्स को 'मिथुनिस्ट' कहा जाता था। रूसी युवा सिर्फ उनके लिए हिंदी सीखते थे और इसलिए पैसे बचाते थे कि एक दिन वे इंडिया आकर अपने पसंदीदा सुपरस्टार से मिल सकें। बाद में दिए अपने साक्षात्कारों में खुद मिथुन भी कहा करते कि मिथुनिज्म रूस में एक धर्म बन गया था और उनके प्रशंसकों में 70 फीसदी केवल लड़कियां हुआ करती थीं।

यह तथ्य आश्चर्यचकित करने वाला जरूर है, लेकिन आज भी जब मिथुन उम्र के सातवें दशक में हैं, उनको लेकर रूस में दीवानगी कम नहीं हुई है। 80 के दशक की उन युवा लड़कियों की बेटियां आज मिथुन की फैन हैं। एक लेगेसी मां से बेटी को मिली और भाषा, संस्कार व समय की बंदिशों की परवाह नहीं हुई।

मार्शल आर्ट के जानकार है मिथुन

मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून, 1950 को कलकत्ता (अब कोलकाता) में हुआ और कोलकाता के ही विख्यात स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे से जुड़े और वहीं से स्नातक भी किया। यह बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है कि मिथुन फ़िल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले एक कट्टर नक्सली थे, लेकिन उनके परिवार को कठिनाई का सामना तब करना पड़ा जब उनके एकमात्र भाई की मौत दुर्घटनावश बिजली के करंट लगने से हो गई। इसके बाद मिथुन अपने परिवार में लौट आये और नक्सली आन्दोलन से खुद को अलग कर लिया, हालांकि ऐसा करने के कारण नक्सलियों से उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता था, क्योंकि नक्सलवाद को वन-वे रोड माना जाता रहा। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और जीवन में उन्हें एक आइकोनिक दर्जा प्रदान करने में प्रमुख कारण बना। यह बात भी कम लोग ही जानते हैं कि उन्होंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है। मिथुन ने भारतीय अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की और वे तीन बेटे और एक बेटी के पिता हैं। ज्येष्ठ पुत्र, मिमो चक्रवर्ती; जिन्होंने 2008 में बॉलीवुड फ़िल्म 'जिमी' से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की। उनका दूसरा बेटा, रिमो चक्रवर्ती जिसने फ़िल्म 'फिर कभी' में छोटे मिथुन की भूमिका में अभिनय किया। मिथुन के अन्य दो बच्चे नमाशी चक्रवर्ती और दिशानी चक्रवर्ती हैं।

नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स

- **1977** – बेस्ट एक्टर – मृगया
- **1993** – बेस्ट एक्टर – ताहादेर कथा
- **1996** – बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर – स्वामी विवेकानंद
- **2022** – दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड – भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स

- **1991** – बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर – अग्निपथ
- **1996** – बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए नेगेटिव रोल – जल्लाद
- **2008** – बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (नॉमिनेशन) – गुरु
- **2023** – बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (नॉमिनेशन) – द कश्मीर फाइल्स

डिस्को शर्ट की धूम

मिथुन के टाइम में एक डिस्को शर्ट भी काफी लोकप्रिय हुआ था। पूरे देश में सरस्वती और दुर्गा की मूर्ति स्थापना के लिए निकलने वाली टोलियों में ये डिस्को शर्ट खूब दिखते थे। रिक्शे पर लाउडस्पीकर से करकराती हुई आवाज़ को चिरता हुआ डिस्को डांसर का गाना और सर पर पट्टी बांधे मोहल्ले के नौजवान आयोजक अबीर-गुलाल से नहाये हुए डांस करते थे। अमिताभ बच्चन की जादुई छवि के बीच मिथुन दा एक ब्रेक की तरह आए और अपने स्टाइल से छा गए।

अपने अभिनय से जीता सबका दिल

▪ 1993 में बांग्ला फिल्म तहादेर कथा के लिए फिर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1996-में फिल्म स्वामी विवेकानंद के लिए मिथुन दा को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस अवार्ड की जूरी के सदस्य रहे ऋषिकेश मुखर्जी ने यहां तक कहा था कि "रामकृष्ण परहंस का अभिनय मिथुन के अलावा और कोई इतना बेहतर नहीं कर सकता था। यदि कोई करता तो स्वयं भगवान ही कर सकते थे।"

▪ फिल्मफेयर अवार्ड में भी इनके साथ भेदभाव हुआ। फिल्म मुजरिम, प्रेम प्रतिज्ञा, प्यारी बहना, प्यार झुकता नहीं आदि में अपने अभिनय से सबका दिल जीता, लेकिन मुख्य अभिनेता का फिल्मफेयर का एक भी अवार्ड नहीं मिला। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के फिल्मी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल आया 8 अक्टूबर 2024 को। इस दिन डांसिंग सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में 70वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिथुन दा को वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से मिथुन दा को सम्मानित किया।

सामाजिक कार्यों में भी अग्रणी

▪ सामाजिक कार्य में मिथुन दा बहुत अग्रणी रहे हैं। कई स्कूल, मेडिकल कॉलेज, डायग्नोसिस्ट लेबोरेट्री एंड रिसर्चर सेंटर, इंजीनियरिंग कालेज में ग़रीब छात्रों के लिए वे छात्रवृत्ति योजना चला रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा हिम्मत के साथ संघर्ष करते रहे हैं और आज इसी संघर्ष, सरल स्वभाव के कारण उन्हें दुनिया सलाम करती है। मिथुन के साथ जिन्होंने बुरा बर्ताव किया था, स्टार बनने के बाद मिथुन ने कभी बदले की भावना नहीं रखी। उलट उनके साथ गहरी दोस्ती हो गई।

▪ आज के युवा/अभिनेता, अभिनेत्री ज़रा से अवसाद के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। हमें और सभी संघर्षशील लोगों को मिथुन चक्रवर्ती के जीवन संघर्ष से सबक और प्रेरणा लेनी चाहिए। बीते 16 जून को मिथुन चक्रवर्ती का जन्मदिन था। उनको हार्दिक बधाई। शुभकामनाएं।

ग्रहों की चाल

ज्योतिषी : विपुल डोभाल
ईमेल : vipravaani@gmail.com
मोबाइल : 9928424374

मेष

मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना आय के साधन लाता हुआ दिखाई दे रहा है। मन बेहद प्रसन्न रहेगा। सुखद समाचार प्राप्त होंगे। शुभ कार्यों पर खर्च संभव है। आर्थिक जोखिम से बचें और स्वयं को व्यर्थ के विवादों से दूर रखें। कुछ जातकों को कृषि भूमि की खरीद का लाभ मिल सकता है। किसान और फल विक्रेता काफी लाभ में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं।
भगवान बुद्ध की स्तुति इस महीने आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगी।

वृषभ

वृषभ राशि के जातकों को प्रेम की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। नव विवाहित दंपतियों में प्रेम बढ़ता दिखाई दे रहा है। किंतु जिन लोगों के प्रेम संबंधों को 5 साल से अधिक हो गए हैं और विवाह नहीं हुआ है, उन्हें धोखा मिल सकता है। नेत्र दोष संभव है, साथ ही सिर दर्द की शिकायत रह सकती है। व्यापारियों को लाभ मिलने की संभावना है। छाती, फेफड़े और हृदय से संबंधित रोगों की जांच करवाते रहें। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है।
भगवान शिव की उपासना इस महीने आपको निश्चित रूप से लाभ देने वाली है।

मिथुन

मिथुन राशि के लिए यह महीना आर्थिक लाभ देता दिखाई दे रहा है। किंतु अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा में आपकी कुछ ऊर्जा जाती दिखाई दे रही है। क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। रिस्क लेने की क्षमता इस महीने बहुत बढ़ी रहेगी और कोई बड़ा नुकसान भी दे सकती है। बहुत नपे तुले रिस्क के साथ आगे बढ़ें। भाग्य का प्रतिशत कर्म की तुलना में काफी कम दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है कि आप अपने कर्म से लक्ष्यों की प्राप्ति करते दिखाई दे रहे हैं ना कि भाग्य से।
हनुमान जी की उपासना आपके लिए शुभ फलदाई होगी।

कर्क

कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए यह समय अत्यधिक लाभदायक दिखाई दे रहा है। अपने बुद्धि विवेक से आप धनार्जन भी करते दिख रहे हैं और साथ ही साथ कई समस्याओं का निदान स्वयं करने में सक्षम रहेंगे। सिर या आंख के आसपास चोट इत्यादि का भय रहेगा। साथ ही नेत्र दोष भी हो सकता है। किसी धार्मिक कार्य में धन व्यय करना आपके लिए भविष्य में शुभ फलदाई रह सकता है। भाग्य बिल्कुल भी साथ देता नहीं दिखाई दे रहा है। आपका स्वयं के प्रयास और मेहनत निश्चित रूप से आपको शुभ फल देने वाली है।
हनुमान जी की स्तुति और महामृत्युंजय मंत्र का जाप लिए शुभ रहेगा।

सिंह

सिंह राशि के जातकों को इस महीने अपनी भावनाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा अन्यथा अपनी वाणी और क्रोध के कारण बने बनाए कार्य ध्वस्त हो जाएंगे। आंख के आसपास चोट लग सकती है साथ ही पेट और आंतों संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। पुलिस या कानूनी पचड़ों से स्वयं को दूर रखें तो अच्छा रहेगा। आय से अधिक व्यय होंगे। व्यर्थ की मानसिक चिंताएं परेशान रख सकती हैं। भगवान शिव की उपासना लिए शुभ फलदाई रहेगी।

कन्या

कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना धन लाभ देता दिखाई दे रहा है। आप घूमने फिरने और अन्य प्रकार की लग्जरी पर खर्च करते दिख रहे हैं। नए वस्त्र आभूषणों की खरीदारी होगी। परफ्यूम इत्यादि अन्य कॉस्मेटिक पर धन खर्च करेंगे। संभव है महीने के अंत में आवश्यकता से अधिक खर्च करने पर पछतावा हो। कुल मिलाकर यह माह आपके लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। शत्रु परास्त होते दिख रहे हैं। संतोषी माता की स्तुति इस महीने आपके लिए शुभ फलदाई रहेगी।

तुला

तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य कष्ट का सामना करना पड़ेगा। कार्यस्थल पर वाद-विवाद की स्थिति के कारण नौकरी खतरे में पड़ सकती है। स्वास्थ्य पर व्यय होता दिखाई दे रहा है। संतान के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। हालांकि 17 जुलाई तक किसी पदोन्नति के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। भाग्य 50% तक आपके साथ दिखाई दे रहा है। अगर आप 40 वर्ष से अधिक आयु के हैं तो कान से संबंधित समस्या आ सकती है।

वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुछ हद तक सुख बाधित होते दिख रहे हैं। आपके कार्य तो बनेंगे किंतु रुक-रुक कर आगे बढ़ेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आती दिखाई दे रही है। भाग्य आपका साथ देता दिख रहा है। कृषि कार्यों से संबंधित व्यवसाईयों और किसानों को लाभ हो सकता है। संतान के स्वास्थ्य को कष्ट रहेगा।
इस महीने शनिवार और मंगलवार को बालाजी की स्तुति आपके लिए शुभ रहेगी।

धनु

धनु राशि के जातकों के लिए इस महीने सुख बाधित रहेंगे। बनते हुए कार्यों में बाधाएं आएंगी। दांपत्य जीवन में कड़वाहट रहेगी। पहले से वैवाहिक जीवन में कष्ट झेल रहे लोग जीवनसाथी से अलग हो सकते हैं। भूमि, भवन या वाहन की खरीद इस महीने पूरी तरह रोक दें अन्यथा हानि हो सकती है। व्यवसाय और ऑफिस में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। पित्त संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। किसी महिला के कारण अपमान या बदनामी की स्थिति बन सकती है।
भाई बहन के साथ रिश्तों में कड़वाहट घुल सकती है। शनि देव की उपासना इस महीने आपके लिए शुभ रहने वाली है।

मकर

मकर राशि के जातकों के लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होता दिख रहा है। आपको धन लाभ होगा और आपके मान सम्मान में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। बुद्धिबल से आप लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें। संतान की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता बन सकती है। स्वयं के लिए भी कमर और निचले हिस्सों को चोट इत्यादि से बचाने की आवश्यकता है। पत्नी के साथ संबंध मधुर होंगे। साथ ही पत्नी की तरफ से कुछ धन लाभ प्राप्त हो सकता है।
भगवान श्री गणेश की उपासना आपके लिए शुभ होगी।

कुंभ

कुंभ राशि के जातकों के लिए कुटुंब में कुछ तनाव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आकस्मिक धन हानि के योग हैं। कीमती वस्तुओं के खोने का भय रहेगा। फिर भी कुछ सुखद समाचारों की प्राप्ति हो रही है और आप यात्राएं करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। परिवार और मित्रों के साथ काफी आनंद दायक समय व्यतीत करते दिखाई दे रहे हैं। बीच-बीच में दांपत्य जीवन में कुछ कड़वाहट आ सकती है किंतु कुछ क्षणों में पुनः प्रेम उत्पन्न हो जाएगा।
इस महीने शनि के उपाय आपके लिए शुभ रहेगा।

मीन

मीन राशि के जातकों का भाई-बहन से विवाद हो सकता है। माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। संतान की ओर से अवश्य सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। पैरों में चोट इत्यादि लगने का भय रहेगा। आप अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच इस बीच अवश्य करते रहें। महीने का अंत होते-होते भाग्य आपका साथ देता दिखाई दे रहा है।
सूर्य को जल अर्पित करना आपके लिए शुभ रहेगा।

राजस्थान टुडे

आपकी पत्रिका, आपकी बात

मासिक समाचार पत्रिका के लिए सदस्यता प्रपत्र

नमस्कार,

हम आपको हमारी मासिक समाचार पत्रिका के साथ जोड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारी पत्रिका में आपको देश और दुनिया की नवीनतम खबरें, विशेषज्ञों के लेख और विश्लेषण, और विशेष सामग्री मिलेगी।

सदस्यता विवरण

- सदस्यता शुल्कः 1000 पोस्टल चार्ज सहित प्रति वर्ष (12 अंक)
- सदस्यता अवधिः 1 वर्ष (12 अंक)
- भुगतान विकल्पः ऑनलाइन UPI भुगतान

सदस्यता प्रपत्र

नाम : _____

पता : _____

शहर : _____

राज्य : _____

पिन कोड : _____

मोबाइल नंबर : _____

ईमेल आईडी : _____

भुगतान विवरण

ऑनलाइन भुगतान

UPI QR code

8107800000@pz

हमारा पता

राजस्थान टुडे

बी-4, एम आर हाईट्स,
भास्कर सर्कल, रातानाडा,
जोधपुर- 342011

संपर्क जानकारी

वाट्सएप नंबर : +91 8107800000
ईमेल : rajasthantoday@gmail.com

धन्यवाद,
राजस्थान टुडे टीम

RNI No.- RAJHINDI/2020/11485

सदस्यता के लिए आवेदन करें : यदि आप हमारी मासिक समाचार पत्रिका के लिए सदस्यता लेना चाहते हैं, तो कृपया इस प्रपत्र को भरें और हमारे WhatsApp नंबर पर भेजें। हम आपको जल्द ही अपनी पत्रिका के साथ जोड़ देंगे।

हर घर रोशनी

आरजीबी
RGB

'आरजीबी सूर्य घर'

मुफ्त बिजली योजना के साथ

मात्र
6.90%
ब्याज दर पर*

सोचिए नहीं अपनाइए

बिजली का बिल 0, खुशियां 100%

हर महीने के बिजली बिल से छुटकारा पाएं

अपने घर की छत को अपना बिजलीघर बनाएं

मुख्य विशेषताएं

- ₹6 लाख* तक का लोन उपलब्ध
- सब्सिडी ₹95000* तक की
- 0 प्रोसेसिंग शुल्क*

याद रखिए पैसा बचाना भी पैसा कमाना है

राजस्थान ग्रामीण बैंक

(भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उपक्रम)

आज ही अपनी निकटतम RGB शाखा में आवेदन करें

*नियम एवं शर्तें लागू

www.rajgb.in | leads@rmgb.in | 0291-2593100